

MOTION OF THANKS ON THE
ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT
DISCHARGING THE
FUNCTIONS OF THE PRESIDENT
—continued.

श्री तंजा शरण सिंह (बिहार) : उप-सभापति महोदया, कल मैं काश्मीर के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। दुर्भाग्य हमारा यह रहा है कि काश्मीर के सम्बन्ध में जिस सफाई से और जिस मुस्वैदी से बातें होनी चाहिये थीं उस तरह से नहीं हुई। आज भी जो कुछ हुआ, जो कुछ मिनिस्टर साहब ने कहा, नाम बतलाने के बारे में, वह भी, इस बात का सबूत है कि एक तरह की सीक्रेसी का, एक तरह की गुप्तता का, एक तरह का रहस्यमय वातावरण वह काश्मीर में बनाए रखना चाहते हैं और उसके चलते बहुत नुकसान हो चुका है। पहले भी हुआ है और अभी भी वह जारी है और शायद आगे भी वह रवैया जारी रहे। अगर यह रवैया जारी रहेगा तो उससे हमारे मुल्क के लिये दिक्कतें पैदा होंगी। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि काश्मीर के मामले में और ज्यादा सफाई से बात होनी चाहिये, ज्यादा सफाई से काम होना चाहिये। यदि बाल की चोरी का सवाल लिया जाय तो चोरी हुई यह बात समझ में आ भी सकती है, लेकिन चोरी होने के बाद जब फौज के लोग वहां मौजूद थे, पुलिस के लोग मौजूद थे जनता के हजारों आदमी मौजूद थे, ऐसी हालत में वह बाल कैसे फिर से रख दिया गया, कब रख दिया गया, यह बात अभी भी समझ में नहीं आती और इसके मामले में चूंकि सफाई से बातें नहीं कही गई हैं इसलिये उसका नतीजा यह है कि तरह तरह के रयूमर्स, तरह तरह की अफवाहें आज काश्मीर में और काश्मीर के बाहर चल रही हैं। कुछ अफवाहों का जिक्र कल मैंने किया था। और भी अफवाहें आज हमारे मुल्क में चल रही हैं, मैं उनका जिक्र करके आपका समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि काश्मीर के मामले में जितनी सीक्रेसी बरती जा रही है, जल्द से ज्यादा सीक्रेसी बरती जा रही है, उससे मामला कुछ बिगड़ता जा

रहा है। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो मुकदमा इस सिलसिले में चले वह खुले आम चलना चाहिये। जो ट्रायल होना चाहिये वह ट्रायल कोई सीक्रेट ट्रायल नहीं होना चाहिये, प्राइवेट ट्रायल नहीं होना चाहिये। आम जनता के सामने वह खुला हुआ ट्रायल हो तब उसके साथ न्याय हो सकेगा और तब हिन्दुस्तान की जनता की शंका का समाधान होगा। अब तक जो मुकदमा चल रहा है काश्मीर में, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। जितने दिनों से वह चल रहा है जिस तरह धीरे धीरे, कछुए की गति से उस मुकदमे की कार्यवाही हो रही है, उसको देखते हुए मैं नहीं जानता कब तक उसका फैसला होगा। जो मुकदमे की गति है उससे न काश्मीर का नाम ऊंचा हो रहा है, न हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि जो नया मुकदमा चले उसमें सफाई से काम चले और कुछ कहने का मौका लोगों को न मिले। जहां तक हमारा सवाल है हम शुरू से ही काश्मीर के पूरी तरह से देश के साथ समन्वय के पक्ष में रहे हैं, हम शुरू से चाहते रहे हैं कि काश्मीर का पूरे तौर पर देश के साथ इन्टीग्रेशन हो। आज भी हमारा वही मुतालबा है, आज भी वही मांग है। मेरा खयाल है कि अगर शुरू में काश्मीर का इन्टीग्रेशन, पूरा समन्वय, देश के साथ हुआ होता तो आज जो समस्याएं देश के सामने आई हैं, काश्मीर के सामने आयी हैं, उनमें से बहुत सी समस्याएं नहीं आती। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारे मिनिस्टर शास्त्री जी ने कल उस सदन में कहा कि काश्मीर के सभी लोग यह चाहते हैं और कुछ उन्होंने इस सम्बन्ध में बातें कहीं। अगर यही बात पहले कही जाती और पहले उस पर अमल किया जाता तो मेरा खयाल है कि बहुत सी मुश्किलें हमारी आसान हो सकती थीं। इस सम्बन्ध में काफी विलम्ब हो चुका है, काफी देरी हो चुकी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि काश्मीर के मामले में अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिये और इन्टीग्रेशन की पूरी

पूरी कोशिश की जानी चाहिये; नहीं तो यह बीच की चीज चलने वाली नहीं है। अगर काश्मीर हमारे देश का हिस्सा है तो जिस तरह से देश के और हिस्से हैं और जिस तरह से और हिस्सों के साथ बर्ताव किया जाता है उसी तरह से उसके साथ भी बर्ताव किया जाना चाहिये। अगर सरकार समझती है कि वह हमारा हिस्सा नहीं है, अगर दिल में चोर है, तो वह बात साफ कहिये। इस तरह हाँ या ना कहने से बात साफ मालूम नहीं होती है। इस तरह से यह बात नहीं चलनी चाहिये जैसा कि पिछले जमाने में काश्मीर के सम्बन्ध में दुविधा से काम लिया गया। मैं देखता हूँ कि वही दुविधा जो दिल में पहले काश्मीर और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में थी वही आज भी है। अगर यह दुविधा चलती रही तो इससे देश को नुकसान होगा। इसलिए काश्मीर का पूरी तरह से इन्टीग्रेशन हमारे देश के साथ होना चाहिये। जैसे देश के दूसरे वाशिन्डे हैं, जैसे देश के दूसरे राज्य हैं और जैसे उनके अधिकार और कर्तव्य हैं वैसे ही काश्मीर के होने चाहियें। यह हमारी मांग है।

अब जहाँ तक सवाल है राष्ट्रपति जी के भाषण का और उसमें जिन विषयों के बारे में जिक्र किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यह ठीक है मुनासिब है कि उपराष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रेजिडेंट केनेडी की मृत्यु का जिक्र किया गया। लेकिन मुझे अफसोस होता है—प्रेजिडेंट केनेडी की मृत्यु का जिक्र किया गया, वह मुनासिब किया गया, लेकिन हमारे देश के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के निधन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं नहीं समझ सका हूँ कि यह गफलत जो हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति की मृत्यु का उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस भाषण को जब मैंने पढ़ा और इस बात

पर ध्यान आया तो मेरा सर शर्म से झुक गया। यह गफलत जिसकी भी तरफ से हुई है एक शर्मनाक गफलत है और इससे हम सब लोगों का सर नीचे हो जाता है।

मैं यह उम्मीद करता था कि हमारी सरकार और सरकार के लोग ज्यादा एलर्ट होंगे, ज्यादा मुस्तैद रहेंगे और जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का भाषण होता तो वे आखिरी एक दो दिन तक की बातों तक का उसमें उल्लेख करते। इस दृष्टि से मैं पाता हूँ कि इस भाषण में खामियाँ हैं। हमारे उपराष्ट्रपति का भाषण जिस रोज हुआ उसके ठीक एक रोज पहले बर्मा के रेवोल्युशनरी कौंसिल के चेयरमैन जेनरल नेविन हमारे मुल्क से गये थे। जहाँ इस भाषण में दूसरे देशों से आए प्रमुख लोगों का जिक्र हुआ वहाँ एक दिन पहले ही जो हमारे देश से गये उनका जिक्र नहीं किया गया। इसके बारे में यह कहा जायेगा कि भाषण पहले ही छप चुका था, लिखा जा चुका था, इसलिए उनके बारे में उल्लेख नहीं किया गया। यह तो कहने की चीज है और इसके बारे में एक्सक्यूज और बहाना बनाया जा सकता है। मेरा कहना है कि जिस समय भाषण दिया गया हो उस समय तक की घटनाओं का उल्लेख उसमें होना चाहिये। बर्मा के रेवोल्युशनरी कौंसिल के चेयरमैन जेनरल नेविन का उस भाषण में उल्लेख होना चाहिये था। जहाँ दूसरे देश के प्रमुख लोगों के आने का उसमें उल्लेख था वहाँ उनके आने का उल्लेख भी जरूरी था।

महोदया, देश में भ्रष्टाचार के बारे में काफी चर्चा चल रही है और सबत में भी काफी चर्चा चलती रहती है। उपराष्ट्रपति जी के भाषण में भी उसकी चर्चा है और इसके बारे में एक विजिलेन्स कमीशन बनाया गया है जिसकी कि आजकल बड़ी चर्चा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितनी चर्चा होती है उसके बारे में तजुर्बा यह हुआ है कि जितनी चर्चा

[श्री गंगारण सिंह]

इसके बारे में की जाती है उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विजिलेन्स कमीशन की चर्चा के बाद भी वही रवैया जारी नहीं रहेगा जो अब तक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिस अनुपात से चर्चा हुई उसी अनुपात से भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। यह तो वही कहावत हुई कि मर्ज बढ़ता गया ज्यूं ज्यूं दवा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आयन्दा उस तरह की बातें नहीं होंगी। मुझे इसमें इस बात का खतरा है कि जहाँ तक सरकार के अधिकारियों का प्रश्न है, उसके लिए तो विजिलेन्स कमीशन बनाया गया है लेकिन जहाँ तक राजनीतिक स्तर पर, मिनिस्ट्रों के स्तर पर और ऊँची जगहों पर भ्रष्टाचार का सवाल है, उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ भ्रष्टाचार कोई नीचे से विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी की तरह नहीं है जो कि पृथ्वी के नीचे से, पहाड़ के नीचे से विस्फोट होता हो। भ्रष्टाचार तो नदी की धारा की तरह है और जिस तरह से नदियाँ पहाड़ों के ऊपर से होकर नीचे उतरती हैं, नीचे बहती हैं, समुद्र तक चली जाती हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार की धारा हमारे देश में ऊपर से पैदा होती है। अधिकार के ग्लेशियर से, अधिकार के हिमानी से, वह पैदा होती है और बहती हुई नीचे सतह तक चली जाती है। इसलिए सिर्फ नीचे से ही भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करना बेकार है। उसका जो स्रोत है, उसका जो उद्गम है वह ग्लेशियर, जहाँ से भ्रष्टाचार की नदी निकलती है, अगर हम उस स्रोत को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो मेरा अपना ख्याल है कि हमारे प्रयत्न बेकार होंगे और उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो उसको जहाँ उसका स्रोत है, उद्गम है, जहाँ से भ्रष्टाचार पैदा होता है, जहाँ पर भ्रष्टाचार की जड़ है, वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिये। अब तक सरकार ने जो कुछ किया है उसका उपराष्ट्रपात

जी के अभिभाषण से पता नहीं चलता है। भ्रष्टाचार का जो स्रोत है उसको रोकने के लिए हमारी सरकार की ओर से कौन सी चेष्टा की जा रही है। यह तो जड़ को न पकड़कर शाखा को पकड़ने की कोशिश हो रही है। शाखा को भी पकड़ना चाहिये लेकिन जड़ को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ।

एक बहुत ही दर्दनाक चीज है जिसकी तरफ मैं आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि हमारे देश में जो इमरजेन्सी की घोषणा हुई थी, सारे देश ने, हर पार्टी ने, लोगों ने पूरे दिल से उसका समर्थन किया था। सारा देश और सारे देश की जनता इस इमरजेन्सी के हक में थी। इस इमरजेन्सी की वजह से सरकार को अधिकार प्राप्त हुए जो साधारणतया प्राप्त नहीं हो सकते थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने जैसा बर्ताव किया, जैसा व्यवहार किया, उसका नतीजा यह हुआ कि आज देश में अधिकांश जनता यह चाहने लगी है कि इस इमरजेन्सी को खत्म होना चाहिये। इमरजेन्सी में जिसके लिए अधिकार दिये गये थे उस तरह से काम नहीं लिया गया और उसका दुरुपयोग किया गया। इमरजेन्सी के लिए इसलिए सरकार को अधिकार दिये गये थे कि देश को तैयार किया जाय, देश को साधनों की दृष्टि से तैयार किया जाय, देश को मनोवृत्ति की दृष्टि से तैयार किया जाय। इसीलिए सरकार को ये अधिकार दिये गये इमरजेन्सी के लिये। लेकिन वह तैयारी नहीं हुई, या अगर हुई तो देश को पता नहीं है। भीतर ही भीतर तैयारी हुई हो तो हम नहीं कह सकते लेकिन बाहर जो तैयारी होनी चाहिये संगठन के जरिये, मनोवृत्ति के जरिये, वह तैयारी हमें देश में देखने में नहीं आती है। इस इमरजेन्सी का सरकार ने नाजायज फायदा उठाया और दलबन्दी को प्रथम दिया गया। डिफेंस आफ इंडिया क्ल्स का नाजायज फायदा उठाया गया और उसका

नाजायज उपयोग किया गया। ऐसी चीजों के लिए उपयोग किया गया जिन चीजों के लिये नहीं किया जाना चाहिये था और जिस चीज के लिये उपयोग किया गया वह शर्म की बात है। जहाँ साधारण कानून से काम लिया जा सकता था वहाँ डिफेंस आफ इंडिया रूल्स से काम लिया गया। ऐसे दर्जनों उदाहरण दिये जा सकते हैं लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ एक दो बातें इसके संबंध में बतलाना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद सदन को पता हो। शायद सदन को पता हो और मैं उस चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अपने सदन के दो सदस्य प्रो० मुकुट बिहारी लाल और श्री चन्द्र शेखर डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के मातहत गिरफ्तार किये गये थे। किस लिये गिरफ्तार किये गये? क्योंकि वे यू० पी० से दिल्ली गुड़ लाना चाहते थे और गुड़ लाने वालों के खिलाफ डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग किया गया। मैं नहीं समझता कि इस सदन में कोई ऐसा आदमी होगा या देश में कोई ऐसा आदमी होगा जो यह कल्पना करता होगा कि जब डिफेंस आफ इंडिया रूल्स बनाये गये थे तो उसका प्रयोग यू० पी० से दिल्ली गुड़ लाने के लिए किया जायेगा? क्या डिफेंस आफ इंडिया रूल्स यू० पी० से दिल्ली गुड़ लाने वालों के खिलाफ प्रयोग करने के लिये बनाया गया था। एक जमाना था जब हर आदमी तक नमक पहुँचाने के लिए, नमक कानून पर से टक्स उठाने के लिए गांधी जी ने इस देश में एक राष्ट्रीय आन्दोलन किया था। और फ्रद्ध के साथ हम सब के सब उसमें जेल गये और हम सब के सब उसमें शामिल हुये। आज शर्म की बात यह है कि हम ऐसी सरकार के मातहत रह रहे हैं जो गुड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग करती है, और पार्लियामेंट के मेम्बरों को गिरफ्तार करती है।

श्री ए० बी० बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) :
गुड़ का भी चीनी से सम्बन्ध है।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Hang your head in shame. Are you listening, gentlemen of the Treasury Benches.

श्री गंगाशरण सिंह : एक तरफ हम प्रामोद्योग की बातें करते हैं, एक तरफ हम तमाम दुनिया भर के छोटे उद्योगों की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुड़ के बारे में जो खैरिया अख्तियार किया गया है, वह मेरी समझ में नहीं आता है। गुड़ के बारे में जो कुछ सरकार कर रही है और जिस तरह से पार्लियामेंट के मेम्बरों पर गुड़ के मामले में आप डिफेंस आफ इंडिया रूल्स लागू कर रहे हैं उससे सरकार को चाहे शर्म लगती हो या न लगती हो, लेकिन मुझ को शर्म आपके इस कारनामे से लगती है।

आज सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है बल्कि जहाँ कहीं जरूरत पड़ी है, ट्रेड यूनियन के लिये जहाँ कहीं जरूरत पड़ी है, वहाँ अपने दल को, अपनी पार्टी को और सरकार के समर्थकों को बढ़ावा देने के लिये डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग किया गया है। गोमिया में मैं जानता हूँ, मेरे सूबे का सवाल है, वहाँ गोमिया में बिहार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन, भूतपूर्व और वर्तमान जो चेयरमैन हैं, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया डिफेंस आफ इंडिया रूल्स में, ट्रेड यूनियन के चलते, ट्रेड यूनियन के काम के चलते और ट्रेड यूनियन के झगड़े के चलते। मैं उसमें तफसील से नहीं जाना चाहता। लेकिन कभी यह कल्पना नहीं की गई थी कि जहाँ आई० एन० टी० यू० सी० के यूनियन के साथ झगड़ा होगा या आई० एन० टी० यू० सी० के वर्कर के साथ झगड़ा होगा, वहाँ आई० एन० टी० यू० सी० के वर्कर के मुखालिफों के विरुद्ध डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग होगा। वहाँ श्री बसावन सिंह और श्री सूर्य नारायण सिंह जो कि बिहार लेजिस्लेचर के मेम्बर हैं और बिहार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व और वर्तमान चेयरमैन हैं, उन दोनों को और उनके साथ कई दर्जन आदमियों को डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के मातहत गिरफ्तार

[श्री गंगाशरण सिंह]

कर जेल भेजा गया। अगर यही रवैया है डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के प्रयोग का अगर यही रवैया रहा इमरजेंसी के जमाने में, अगर इमरजेंसी का यही नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं तो इससे अच्छा यह है कि इमरजेंसी को खत्म कीजिये। असल जो तैयारी होनी चाहिये चीन का हटाने के लिये, उसके लिये क्या तैयारी कर रहे हैं? अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो वह कम से कम इस सदन के लोगों को नहीं मालूम है और देश भी नहीं जानता है। चीन ने जिस जमीन पर बखल कर लिया है उसके लिये क्या कर रहे हैं इमरजेंसी के अधिकार और कानून के जरिये से, उसका पता नहीं चलता है, लेकिन यहां जो सरकार के दल के विरोधी हैं, जिनसे मतभेद है उनको दवाने के लिये डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। यह नाजायज चीज है और हमने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी जब डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अधिकार दिये गये थे, जिस समय पार्लियामेंट में वह पास हुआ था या जिस समय इमरजेंसी यहां डिक्लेयर हुई थी। आज बहुमत के बल पर, आज मेजारिटी के बल पर देश के हित में बनाई गई चीजों को इस तरह जो नाजायज उपयोग में ला रहे हैं, वह सिर्फ यही नहीं है कि गलत है बल्कि मैं तो इसको राजनैतिक बर्झमानी समझता हूं जो आज यह सरकार कर रही है।

SHRI BHUPESH GUPTA: To put it mildly.

श्री गंगाशरण सिंह : जहां तक देश की आर्थिक अवस्था का प्रश्न है, दिन पर दिन अवस्था बुरी होती जा रही है और सरकार जो कुछ कोशिश थोड़ी बहुत करती है वह इतनी देर से करती है, इतना नाकाफी करती है और इस तरीके से करता है कि उसका कोई असर नहीं होता है। आज जो हमारे यहां कास्ट आफ लिविंग का इंडेक्स बनता है

आज की परिस्थिति में और जो हमारी जरूरतें हैं और इस देश के रहने वालों को जिन चीजों की आवश्यकता है उन पर और इंडेक्स निकालने में जितने मदों का उसमें उल्लेख करके, इंडेक्स बनता है, अगर आप उन दोनों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वह चीज काफी आउट-आफ डेट हो गई है और बहुत सी चीजों का, बहुत से मदों का, उससे आज सम्बन्ध नहीं रह गया है। अभी महाराष्ट्र में जो लकड़ावाला कमेटी बनी थी और उसने जो सुझाव दिये थे वे बहुत हद तक सही थे, और जो तरीका हमारा अब तक रहा है उससे वह तरीका कुछ ज्यादा अच्छा है और मेरा खयाल है कि अगर हो सके तो उसमें कुछ और सुधार करके केन्द्रीय सरकार को और दूसरी जितनी प्रादेशिक सरकारें हैं उनको वह तरीका अख्तियार करना चाहिये। अगर वह तरीका अख्तियार कर लिया जाता तो शायद जो इंडेक्स हमारे सामने आ रहे हैं वे ज्यादा सही आते। लेकिन जो गलत तरीका आपका है, जो बहुत सही तरीका नहीं है, उसके मुताबिक भी इंडेक्स के नम्बर बढ़ते जा रहे हैं और उसके मुकाबिले में आप कोई कार्रवाही नहीं कर रहे हैं। उसकी पूर्ति के लिये आप कुछ नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वह बिल्कुल नाकाफी है। थोड़ा सा डिप्लेनेस अलाउंस आप देते हैं लोगों को, लेकिन जब तक आप डिप्लेनेस अलाउंस देते हैं या देने का फैसला करते हैं तब तक इंडेक्स का नम्बर फिर आगे बढ़ जाता है। इस तरह से डिप्लेनेस अलाउंस और महंगाई में जो भाग-दौड़ मच रही है, उस दौड़ में महंगाई बराबर आगे रहती है और डिप्लेनेस अलाउंस आपका बराबर पीछे रहता है। वह कभी उसके पास नहीं पहुंच पाता है। आप रफू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रफू से काम नहीं चलता है जैसा कि किसी ने कहा है :

कपड़ा सड़ा गला हो तो मुमकिन नहीं रफू, सीते थे आस्तोना, गरेबान फट गया। इतना ही नहीं है, आगे भी है :

बार गुनाह बढ़ गया उज्र गुनाह से,
धोने से और दामने ईमां चिकट गया ।
आज जब मैं इस सम्बन्ध में सोचता हूँ तो मुझे
बार बार यह बात याद आती है :
धोने से और दामने ईमां चिकट गया ।

आज सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि हमें बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ आर्थिक क्षेत्र में भी कदम बढ़ाना चाहिये । नहीं तो देश की जो हालत आज हो रही है, देश की जो तबाही हो रही है और मामलों में, अगर आर्थिक मामला उसी तरह से आगे खराब होता गया, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की हालत एक रोज ऐसी हो जायगी जिससे फिर हमारा निस्तार नहीं हो सकेगा । एक ओर तो महंगाई आगे बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर बेकारी का भी वही हाल है । बेकारी के लिये आप कोशिश करते हैं, लेकिन जो बैकलाग है, जो पहले से बेकारी चली आ रही है उसमें बजाय कम होने के बेकारी और बढ़ती ही जाती है । यह महंगाई और बेकारी का सबाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ये मुंह बाये हमें खाने को आ रही हैं और हमारे देश की जो आर्थिक नीति है, उसका पता नहीं क्या हाल होगा; इन दोनों महंगाई और बेकारी के चक्कर में पड़ कर और इसमें सैंडविच हो कर हम क्या हो जायेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) in the Chair]

स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की बहुत चर्चा होती है, लेकिन सारी चर्चा के बावजूद अगर सारे देश के भीतर आज आप श्रौर करें तो पता चलेगा कि इन गृह उद्योगों की जैसी बुरी हालत है वैसी बुरी हालत शायद किसी की नहीं है । कहीं स्कीम ही नहीं बन पाई है । कहीं उनके लिये रा मॅटीरियल ही नहीं है, कच्चा माल ही नहीं है । अगर कहीं

कच्चा माल है तो फिर उसके लिये उनको पास साधन नहीं हैं । उसके लिये जो उनको उधार मिलना चाहिये, उसके लिये उनको जो पैसा मिलना चाहिये, उसको भी आज कमी मालूम होती है । हमारे देश की जो अवस्था है, हमारे देश में जितनी बेकारी है, हमारे देश में जितनी जनसंख्या है, उसको देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे छोटे उद्योगों के बगैर हमारे देश का उद्धार नहीं होने वाला है । छोटे छोटे उद्योगों के बगैर न तो हमारी आर्थिक अवस्था सुधरेगी और न हमारी बेकारी दूर होगी । इसीलिये छोटे उद्योगों की ओर आज सब से अधिक हम लोगों को जोर देना चाहिये ।

ऐसे बहुत से गांव हैं जहां आपने बिजली दे दी है । ऐसे बहुत से गांव मैं जानता हूँ बिहार में भी और दूसरे सूबों में भी जहां आपने बिजली दे दी, आपने बिजली के खम्बे खड़े कर दिये, बिजली पहुंचा दी, लेकिन गांव वालों को यह नहीं बताया कि बिजली का उपयोग उद्योगों के लिये किस तरह करना चाहिये, उनको साधन नहीं दिये, नहीं बतलाये । जो हिन्दुस्तान के गांव हैं उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो बिजली का उपयोग कर सकते हैं सिर्फ पंखों के लिये और रोशनी के लिये और सिर्फ आराम की चीजों के लिये । गांवों में अगर आपने बिजली पहुंचाई है, तो उसके साथ ही साथ आप को वहां स्कीमें पहुंचानी चाहियें कि उन गांवों में बिजली का क्या उपयोग होगा, उसका उद्योग से क्या सम्बन्ध होगा, और गांवों में जो कृषि होती है उस कृषि से उसका क्या सम्बन्ध होगा, लेकिन उसमें कोई समन्वय नहीं है । गांवों में जो आप बिजली दे रहे हैं उसके साथ कृषि और उद्योगों का सम्बन्ध नहीं है । हजारों गांवों में आपने बिजली दी है । उसमें एक तो गवर्नमेंट को धाटा देना पड़ता है और कुछ बड़े लोग अपने घरों में रोशनी लगा सकते हैं, पंखे लगा सकते हैं, लेकिन बाकी गांव वाले जो गांवों में बिजली जाती है उस बिजली से फायदा नहीं उठा सकते हैं । यह मैं व्यक्तिगत तजुर्बे की बिना

[श्री गंगाशरण सिंह]

पर बहुत से गांवों को देख करके कह रहा हूं। आज ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बिखल हो गया है। कोई शृंखलता हमारे बीच में नहीं है, कोई समन्वय नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो हमारे देश में जो नीति चलेगी उसमें कृषि और छोटे उद्योगों के बीच में एक सामंजस्य और समन्वय करना होगा और बिजली का उपयोग अधिक से अधिक हमारे गांव वालों को सिखलाना होगा। इस दिशा में मैं लेनिन के उस कथन और कार्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रूस में क्रांति होने के बाद लेनिन ने सब से ज्यादा जोर जिस पर दिया था, वह इलेक्ट्रीफिकेशन पर जोर दिया था, बिजली पर जोर दिया था और बिजली हर जगह पहुंचाने की उसने चेष्टा की थी और साथ ही साथ बिजली के उपयोग की भी चेष्टा की थी। मैं आप से यही कहना चाहूंगा कि आज जो कुछ एकांगीरूप से कर रहे हैं वह एकांगीरूप से नहीं होना चाहिये बल्कि उसका समन्वय का रूप होना चाहिये, उद्योग का भी और कृषि का भी।

राष्ट्रपति के अग्निभाषण में दो बातों का मुख्यतः जिक्र होना चाहिये, लोग यह अपेक्षा रखते हैं—एक तो पिछले वर्ष से इस वर्ष तक भाषण के समय तक जो मुख्य घटनायें हुई हैं उनके सम्बन्ध में कुछ जिक्र होना चाहिये और दूसरा यह कि आगे के सम्बन्ध में दिशा का, गति का, कोई उल्लेख होना चाहिये। उस दृष्टि से मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति का भाषण बिल्कुल ही सूखा, निर्जीव, बिल्कुल ही दिशानिर्देशहीन है और एक वाजाव्ती के बयान की तरह से लगता है, उससे किसी तथ्य का या दिशा का या आज की परिस्थिति में आवश्यक चीज का पता नहीं चलता। एक और ऐसी बात इस बार हुई है जिसकी तरफ भी मैं सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, आम तौर से अगर राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, भाषण होने

वाला हो तो अगले साल जो विधेयक आने वाले हों, जो सरकार की नीति हो उनका उल्लेख भाषण में ही सब से पहले हो तो ज्यादा अच्छा है लेकिन इस बार मैंने यह देखा कि उपराष्ट्रपति के भाषण में उनका जिक्र होने के पहले ही यहां के अखबारों में उनका जिक्र हुआ। पता नहीं कि यह चीज सरकार के तरफ से दी गई, जानबूझ कर दी गई या अखबार वालों ने अपनी मेहनत के जरिये से, अपने स्कूप के जरिये से हासिल की लेकिन मैं समझता हूं कि हाउस की डिगनिटी, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की डिगनिटी और पद्धति के लिहाज से भी यह आवश्यक है कि जो ऐसी घोषणा हो वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा हो और अखबारों में पहले से नहीं निकले। इस बार स्पष्ट रूप से आप पायेंगे कि उपराष्ट्रपति का भाषण जिस रोज हुआ उससे पहले अखबारों में—मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक अखबार में—पूरे कानूनों का और सब चीजों का जिक्र छप गया। ऐसा भालूम होता है—किसी मिनिस्ट्री के अफसर ने दिया, किसी मिनिस्टर ने दिया या किसी ने भी दिया हो या वाजाव्ती सरकार की तरफ से वह दिया गया हो। उन चीजों का उल्लेख भी उस समाचार पत्र में किया गया जिन में से कुछ का तो उल्लेख राष्ट्रपति के भाषण में हुआ ही नहीं लेकिन सब चीजों का जिक्र समाचार पत्र में किया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का भाषण जब होने वाला हो तो ऐसी बातों का जिक्र—अखबार वालों को आवलाइज करने या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन की वजह से इस तरह की बात न करके—उपराष्ट्रपति के भाषण द्वारा ही किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और यह ज्यादा उपयुक्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री भगवत नारायण भार्गव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस

प्रस्ताव का समर्थन एक कविता के द्वारा कर रहा हूँ ।

पाया सतत मान जग में जिन पूज्य
राष्ट्रपति ने शुचि अनुपम ।

उन धर्मज्ञ आत्मज्ञानी का हम करते
सादर अभिनन्दन ॥

हिन्दी हिन्द राष्ट्र की भाषा निश्चित
है उसका अभिवर्धन ।

त्याग मोह आंगल भाषा का करें सभी
हिन्दी आराधन ॥

सुखद समाजवाद संयममय जीवन में
होवे साकार ।

सत्यं शिवं सुन्दरं का हो जन जन में
पावन संचार ॥

दुख दारिद्र्य विषमता का हम करें
अविद्या का संहार ।

अष्टाचार अनाचारों का कर दें हम
अन्तिम संस्कार ॥

जग गन मन हो धर्म न्याय से ओतप्रोत
सदा कर्तार ।

सच्चे गांधीवादी बन कर करें देश शासन
विस्तार ॥

करके मर्दन मान शत्रु का ऊँचा रखें
माँ का माल ।

अजय हिन्द की जय सदैव हो पहिनें
लाल जवाहर माल ॥

SHRI R. R. DIWAKAR (Nominated):
Mr. Vice-Chairman, I must thank you very much for the opportunity that you have given me to make a few observations on the President's Address. I associate myself with the Motion of thanks that has been moved by Shri Deokinandan in this House. I think the subjects covered by the President's speech are so many and so important that I must be satisfied with making a few observations on some of

the subjects which I feel are very important. I must say that so far as the tenor and the cast of the whole speech of the President was concerned, we expected a far more brilliant, a far more stirring and a far more directional speech from one who is known throughout the world as an exponent of the Indian cultural point of view and very deeply soaked in what may be said to be the deeper channels of the Indian mind. Yet when it comes to our reading the Presidential Address we feel that it is somewhat of an official narration or enumeration of certain subjects and nothing beyond that. I do not know if the Presidential chair acts as a kind of damper on the enthusiasm and the spiritual power that a man can command outside officialdom and the official chair.

Now, I think I must first draw the attention of the House, Mr. Vice-Chairman, to the new phrase which has been used in the second paragraph of the Address, 'a democratic and socialist order'. I think we have been familiar, so far as reports in the newspapers and the Congress party policies are concerned, with the phrase, democratic social order, and not with 'a democratic and socialist order'. I do not know why these two words have been now separated, if at all this is a repetition of the policies adumbrated at Bhubaneswar. I think if these words continue to be as they are, they raise some problem in semantics. If a socialist order is to be there, unless it is definitely mentioned that it is through democracy and through non-violence, it may mean any type of socialism. Today a socialist order does not necessarily mean a democratic order; nor does a democratic order necessarily mean a socialist order. So India is in a happy position to say that we are trying to arrive at a socialist order through democratic means. I think unless that is clarified in the clearest possible manner it would create confusion in the minds of the people and they would try to interpret these words in their own way. A socialist order of the Communist type today, for instance, is supposed

[Shri R. R. Diwakar.] ♦0 be democratic and Communists declare it in that way to the world. Communism they say, is a socialist order; not only that, it is a democratic order also! That is why I make the plea that these matters require clarification. Moreover we should also examine in what direction we are going. It happens that a socialist pattern was declared as early as the Avadi session of the Congress. Since then we have been travelling along that line and now we come to the socialist order. But if we examine the different sectors in which nationalisation has been introduced, we have no doubt the full impact of nationalisation but we see very little of the socialist order in that nationalisation. If socialism or the socialist order is to spell only nationalisation, I am afraid we shall not be going in the direction of real socialism but in the direction of State Capitalism. Therefore, it is very necessary for a country like ours to have our ■fingers on the pulse of the direction as to where we are going and be clear about our destination.

Casting a glance at the international field and the remarks! made by the President I am very glad to say that a policy, which had been adumbrated by the Government of India through our Prime Minister that there should be a nuclear test ban—which was really speaking advocated as early as 1958—has after all come to pass during the last year. It is partial, no doubt, but something is better than nothing and let us hope that this test ban is extended, in due course, to underground tests as well. Another welcome sign is that the use of nuclear power in and from outer space has been banned by agreement between rulers of the two countries concerned. The establishment of the *hot line' also is a very welcome sign. At the same time, I do not think that there is any scope for complacency, because simultaneously France has stood out. Not only that. It is actually making progress in 'nuclear arms. This morning's papers convey the news that France has now jets which can be

re-filled in mid-air and its planes carrying nuclear war-heads can travel •s far as 4,700 miles, meaning thereby that France can very easily cover some of the targets in Russia on the one side and some other countries on the other side. This is not a development which is very happy, especially in view of the progress towards peace that is being made by the two chief nuclear powers. Similarly, China is still out of bounds, so to say, of international peace efforts and, therefore, it is quite free to carry on its experiments and confront the world one day with nuclear bombs. Therefore, there is very much scope or very great necessity to be as alert as India has been from the beginning, not only in international councils but, I think, also as a people, Indians should be alert about these matters. I may mention that as regards nuclear test ban, the people of India also played their humble part. They boldly took upon themselves the responsibility of conveying to the nuclear powers their clear opinion that what the powers were doing was something which was against the health as well as the future of humanity itself; they had no right to poison the atmosphere of the world in trying to arm themselves against each other.

Then, I should make a reference here to what is going on in the United Nations Security Council. That is also a part of international affairs. I think every one of us appreciates very much the able part played by Mr. Chagla in giving a fitting reply to the allegations and a number of things that Mr. Bhutto said against India on the floor of the Security Council. But one is surprised at the attitude taken by Sir Patrick Dean on behalf of the British Government. While he made a plea for mediation or something like that, there was no mistake in our seeing that his speech was more like that of an advocate of Pakistan than that of a representative of a great nation like England, which had very vital and friendly connections with India. As the British Government as well as the British people must be knowing, India

is making every effort to see that our friendship continues; but it should not be made difficult for India, for instance, to continue that friendship and to continue in the Commonwealth with the goodwill of all the other nations in the Commonwealth. Therefore, I think whatever be the Tory inclinations or the Conservative traditions of British diplomats and British administrators today, they must take into consideration that, if they want real friendship to establish itself between two members of the Commonwealth, they should not adopt a partisan attitude and make it difficult for India and Pakistan to come together. It might be very uncharitable, but some people and historians do say that Pakistan was the creation of the British Government and if such attitudes are struck by the British now and then in the course of diplomacy, well, perhaps that kind of allegation by historians gets support. I think it is necessary that we should raise our voice against such an attitude of the British not only in diplomatic circles in the international sphere but also in this Parliament of ours.

I may now mention a few things about industry—the public sector and the private sector. I need not say that much progress has been made. But after all we are here not merely to register the progress but also to think in terms of where we have failed. So far as mixed economy is concerned, I think it has been declared so many times from the platform as well as in Parliament itself. At the same time, one cannot but feel that the private sector is made to feel a kind of inferiority complex. Those who are running the public sector are naturally in a better position to drive home this kind of inferiority complex. I do not think that Mr. J. R. D. Tata who has made a certain statement in New York to the "New York Herald Tribune" has done it in a lighthearted manner. He is one of the few persons who carries weight with the Government of India. He has easy access to the highest authority and he must be enjoying a number of deserved facilities for

building up big industry in the private sector. But even in spite of that, I am glad that he has given vent to the difficulties of the private sector and what the private sector is feeling. This certainly is on behalf of the smaller industries, possibly the smallest of them. What he has said is this that India has infinite capacity and scope for development of industries. While the public sector may go on developing, if the private sector also is given the necessary facilities and encouragement, he says, it will definitely develop faster. These are the words he uses so far as the private sector is concerned. At the same time he asks what it is that comes in the way—well, he says controls and also red-tapism. He has not mentioned the word "red-tapism" but he has mentioned the word "controls". Naturally he does not mean all kinds of controls, but he means that controls have acted in a restrictive manner and they have not been able to give the necessary encouragement for the private sector industries. The third thing that he has mentioned is that these controls have acted as a curb on foreign capital coming into India. I do not mean to say that the Government is not aware of all these difficulties which the private sector is suffering from. I know personally of a few industries where, for instance, they have engaged their capital, carried on the work, constructed buildings, engaged money in machinery and for six months or eight months right from the beginning they have been asking for the necessary licences, and yet at the end of six months or eight months or whatever it is, they do not get the licences; thus all the capital and all the labour is wasted which adds to their frustration. I think this kind of thing should not happen. If this continues to happen, then I think the private sector cannot develop and play its legitimate part in the building up of the nation.

One word about agriculture. Figures have been given that 6 million acres have come under irrigation and 5.5 million acres also are going to come under irrigation. Within my own per-

[Shri R. R. Diwakar.] sonal knowledge there are two big irrigation projects in which thousands and thousands of acres of land are statistically under irrigation but not a drop of water is passing on to them. And why? The dam is there, about Rs. 100 crores have been sunk on it, Rs. 6 crores are being paid as annual interest, and yet thousands and thousands of agriculturists are not willing to take, the water on account of want of co-ordination among the P.W.D., the Irrigation Department, the Revenue Department, and so on, or because the water-cess is heavy or because there are no technical personnel who can give them the proper advice. These things are happening. Therefore, we should not be led away by the figures but we should actually see what is the exact acreage under irrigation. This naturally leads us to the point that agriculture has not been able to play its part in producing enough food in our country, and I think all these matters ought to be looked into. While theoretically we are legislating for social justice, and we are taking action for more production, why is it that production is lagging? Is there want of sufficient incentive to the agriculturist, to the peasant who is working in the field or is this legislation only doctrinaire? We have to see whether this legislation is taking into consideration both social justice and production which are equally important, whether there is a lopsided legislation on the side of social justice and not enough emphasis on the side of production.

I think these are all important matters which have to be taken into consideration. Fortunately I am in the happy position of not being identified with any political point of view. What ever I have said, I should emphasize I have said as an observer of things as they are actually being done. While I have every praise and compliment for all that the Government is doing, I would say that they should be far more careful, far more self-introspective and far more responsive to the needs of the small man, to the small

industry people and to the man in the street. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Before I call upon the next speaker I would like to know if the House is prepared to sit through the lunch hour as there are a large number of speakers.

«

SOME HON. MEMBERS: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Shri Dahyabhai Patel

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, I missed the presence of the dignified personage of the President of India when we had the Address on the opening day of Parliament. We have been so used to seeing him in this House that perhaps some of us might not fully realise how much dignity his presence on the day of the opening of Parliament lends to the proceedings. I hope his illness is insignificant and that he will soon be restored to health. In him we have somebody who is very clear about his thoughts. Indeed a little over a year ago, he said in very clear terms that the Indian reverses in NEFA should be regarded as a matter of sorrow, shame and humiliation, that we have to retrieve our lost prestige and that India's freedom, security and honour are things which are endangered today. Are we doing anything about it?

Next also I would like to say *how* sorry I am to see our Prime Minister in this state of health. I hope he also will be soon restored to health. But let us recognise that there is such a thing as time, that there is such a thing as age, and the Prime Minister is a sick man and the chances of his being what he was five years ago or ten years ago are rather bleak. Hence his sickness is reflected in the Government. Today we have a sick Prime Minister. We have a sick Government. I am sorry that in certain circles the sickness of the Prime Minister is being exploited by some people, and

people are being asked to be restrained in their criticism, legitimate criticism of Government in Committees. I do not know whether it is going to be repeated here. Sir, we come here as Members of Parliament to do our duty to the country. And I hope that

we shall continue to do so I P.M. fearlessly in spite of what has

happened. If the Government is sick, let it go on a rest cure. If the Prime Minister is sick, more so, let him also go on a rest cure. But what is the use of having a Government which cannot keep it; mind? The Kamaraj Plan is not going to affect the country, the Government or the Cabinet. What we want is a firm, stable Government. What is happening on both sides of our borders and in the two border States is an indication that the Government is very sick and needs to go on a rest cure, if not go altogether. I must also at this stage take the opportunity of congratulating our representative in the United Nations, Mr. Mohammad Currim Chagla, as he is now known, instead of Mr. M. C. Chagla—Mr. Justice Chagla as we knew him in Bombay—for his bold exposition of India's case in the United Nations. It is a sad reflection on the people who have been in charge, on the people who have been our spokesmen in the United Nations for the last 15 years that they did not raise the many logical points that he raised in his address. His address was; cold logic and reasoned. Why did not anybody think of them? So many of them are going to the United Nations again and again. Nobody could think of the point that Kashmir acceded to India as all other Indian States did through the Head of the State. Now, this point was not mentioned even in the United Nations all these years. It is; a sad reflection on the people who have been in charge of arguing our case. I need not repeat. There are several other arguments in his case—if it is read properly—which were missed previously. *(Interruptions)* We are not dealing. . . .

SHRI A. M. TARIQ (Jammu and Kashmir); For the hon. Member's in-
1100RSD—4.

formation, the Letter of Accession is already on the record of the United Nations; it was from the Maharajah of Kashmir. That is our part.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Mr. Tariq, I am not denying that. I am dealing with the presentation of our case. And the people who were there, who went there on behalf of the Government of India to present our case, should have presented it more logically, in a reasoned manner and not with their hearts full of prejudices; they always went and made more enemies for India than friends. That is why our case which is so just and so clear has been bogged down in the Security Council all these years.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Kerala): Their logic did not win many friends.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: That is because of the prejudices created by his predecessor. My friend, you know it fully well; you may support him. But the truth cannot be hidden. It is because of his attitude, because he was offensive—his predecessor, I mean—to the free nations of the world that our case has been misunderstood. *(Interruptions.)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : Order, order, let him proceed.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): The Communist friends along with Mr. Tariq are trying to defend their leaders.

SHRI A. B. VAJPAYEE: What leaders?

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : Please proceed, Mr. Patel.

SHRI BHUPESH GUPTA: We can defend ourselves.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am fully in agreement with the sentiments

[Shri Dahyabhai V. Patel.] expressed by Mr. Ganga Sharan Sinha and other friends in this House about the refugees who are coming from across the border. They deserve our every sympathy. It is not their fault that they are in this plight. We have a certain obligation towards them and I hope that the Government will be liberal towards them. Unnecessary obstacles in the way of their coming back should not stand. I know that this means a great drain on our resources, that it means a great burden to the exchequer. But the Government of India will have to stand up and bear it. If the Government—and when the Government—has courage enough—I do not know if it ever will have it—it must demand a portion of territory, land from Pakistan. When so many people are exploited, when they are thrown out from Pakistan, Pakistan must be made to yield so much territory, so that we can house those people. I do not know whether this sick Government will ever have the courage to do so.

Sir, I repeat that this Government is sick. What is happening in regard to the two distinct issues which have figured prominently in this House and how is the feeling of the people being circumvented? I refer to the Sprajud-din affair. That has been referred to a Judge.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

But while the proceedings are going on against Serajuddin, the Magistrate, I understand, is being transferred as Chief Presidency Magistrate elsewhere. It is a very ingenious Government that can stop or prolong legal proceedings in this manner by giving promotion to a Magistrate. What will be the result? So many witnesses have been examined.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): The case may remain on the file, of the Magistrate even if he is promoted.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Thank you, I know that. Even a child knows that. But the purpose of this

• * *

SHRI ARJUN ARORA: I do not consider the hon. Member to be a child, ! much less my child.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am grateful to God for that. What would have been my fate if I were his child? I am certainly not willing to exchange my position. (Interruptions.) Whatever this gentleman may say, I better restrain myself. He will have plenty of opportunities. My time is limited, I am trying to save my time for the other friends of my party who also want to speak.

SHRI LOKANATH MISRA: His friend is involved in the Serajuddin case.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: The trial, I am saying, will go on. Certain people have been examined. Another Magistrate in his place will take up the re-examination of all those witnesses. It is a legitimate request of any accused. Some of the witnesses will be available, some of them will not be available. So, the trial will prolong. Then the matter will go to the higher courts and to the Supreme Court whether such witnesses should be called again or not. These are all dilatory tactics with only one intention, to shield the co-conspirator in this, and I make this charge with a full sense of responsibility, and if this Government tolerates it, they are pleading guilty, demonstrating the charge that I make that this Government is a sick Government.

Sir, the other affair which I would refer to is something much more serious; it is about the border State of Punjab. The Prime Minister has entrusted the enquiry into the allegations against the Chief Minister of Punjab to a Judge. That was expected, of course. We know, Sir, of a member of the Legislature, a member of the Congress Party, who was beaten up because he made certain charges. He has.

himself said so, he has offered to prove them before anyone. But much more serious is what has happened a few days ago—a person was shot dead, five bullets were fired into his body at eleven of the clock in broad daylight and not one line has appeared in the newspapers anywhere. The person was a close relation of a former Defence Minister of this country. The people who shot him went to shoot him—I am told—in a truck belonging to the son of the Chief Minister. Will the Government enquire into this? Why have no arrests been made? Mr. Nanda wants to arrest Members on a charge of bringing *gur*, under the Defence of India Rules. Where are the Defence of India Rules in the case of murderers, people who murder persons in broad daylight and of their accomplices, people who assist them? What is happening to this Government? It is therefore that I say that this is a sick Government and I do not think that this Government can be cured. The only remedy is to end it, and shall I say also that this country is sick of it? Therefore, they are losing repeatedly all the by-elections that have taken place in the last few months. Let them realise it.

AN HON. MEMBER: Not all.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Most of them.

SHRI A. B. VAJPAYEE: What happened in Mahuwa?

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI (Uttar Pradesh): That is recent.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: My friend, Mr. Bhupesh Gupta, yesterday butted in on my question to make a speech when I asked questions about the affairs of the Bank of China. This is one more example of the sickness of this Government. Responsible Ministers made statements in the Bengal Assembly about the affairs of the Bank of China, of the people who were given money and of a Bombay weekly that is supposed to have received money.

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Vice-Chairman . . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Mr. Vice-Chairman, I do not yield. He has got his right to speak. He made a speech yesterday butting in during the Question Hour when I was putting questions, which was very wrong. I do not yield, Mr. Vice-Chairman.

SHRI BHUPESH GUPTA: Then there will be a deadlock.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: There can be no deadlock.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Unless he yields you cannot . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: My friend very often returns to the same question. So I presented to the House a statement made by Mr. Prafulla Sen in reply to a calling attention notice given by Mr. Kashi Maitra, the P.S.P. leader, in which Mr. Prafulla Sen said that he had no information. It is in their December proceedings. I made it a part of my question and quoted it. Unfortunately my friend was not here then. The 'Current', a weekly in Bombay, wrote it.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: More than one paper wrote it, even a Bengali daily, though I have not got the cuttings with me, now.

SHRI BHUPESH GUPTA: Anyway I leave it at that. He is a good friend otherwise.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Now the Defence of India Rules are used against friends who protest against orders, like, the *Gur* Control Order, against people who are agitated about certain things in Bombay, and so on. Somebody who was standing to look at one of these demonstrations was also arrested, because he happened to help certain members of the Swatantra Party, and even my letter to Mr. Nanda explaining the position has not secured his release, while people like this go about freely in this country.

[Shri Dahyabhai V. Patel.] What sort of Government have we? Mr. Nanda promised to eradicate corruption in three months.

HON. MEMBERS: Two years.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Two years? Well, six months of the two years have nearly gone.

AN HON. MEMBER: Three months.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Do you see corruption on the decrease? Let Mr. Nanda go to Saurashtra where a by-election is taking place and let him see for himself with open eyes what corruption is taking place at every stage, what pressure is being put on people, how people are being called because they assisted in the previous by-election when Mr. Masani fought at Rajkot. When honest citizens, when people working in State Transport offices and such like offices are being called daily to report to the police station when there is no charge against them, it is simply harassment; it is because they helped others against the Congress. Are these Defence of India Rules or Defence of Congress Rules?, I want to ask, and therefore it is that we demand repeal of this lawless law. If the Government wanted to continue the Defence of India Rules, they must convince us of the reasons therefor. They have to convince this country that they are serious about defending this country. There are rumours, there, is documentary evidence—if required it will be forthcoming—that the Prime Minister has already given his assurance that India is not going to advance further than the present line.

SHRI N. C. KASLIWAL (Rajasthan): That is not correct, I will challenge, your statement.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: We will come to that, my friend. There are so many defenders of the Prime Minister. You need not be in a hurry. The matter is coming.

SHRI N. C. KASLIWAL: I will show that the letter that you have circulated is completely wrong in facts; you have misquoted facts.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I have not circulated any letter. My friend is labouring under a misapprehension. But the letter that he refers to may come out. What does it matter? Let the Home Minister come out with a full statement on the matter. We want to know about it, and if the Defence of India Rules are there, why not arrest the forgers? Why don't you use the Defence of India Rules there? Why do you want more power when you cannot use it?

Sir, this sick Government has given us enough worry. Now I will come to the condition of the country as it is. The review of the state of economy, the President has referred to in detail, to every item, and the President has very frankly acknowledged that the overall rate of economic growth has lagged behind despite a certain upward trend in industrial production and improvement in the balance of payments. The President has made the following main points: The general level of industrial output in 1963-64 is expected to be 7 to 8 per cent higher than the previous year. Basic industries like coal and steel have made a little more progress and production in the steel plants is now coming up to what their rated capacity was. They should have come to this some years ago. Now we see some hope of their coming up to that capacity. Then power shortages continue to hinder the growth of industrial progress everywhere; the total availability of power may have improved and the transport position has certainly eased a little. There has been an improvement in export earnings and with continuing external assistance from friendly countries our foreign exchange reserves and the country's balance of payments position have not been under the same kind of pressure as it was in the previous year. Some public sector undertakings have made significant progress.

The first Indian manufactured A.C. electric locomotive rolled out of Chittaranjan works. The National Mineral Development Corporation has practically completed the development of the Kiriburu iron ore mines. The Atomic Energy Establishment at Trombay has begun exporting radio isotopes. The expansion of the three public sector steel plants is well underway. Work on the alloy and tool steel plant at Durgapur is in progress, we are told. Action has been initiated for the setting up of the Bokaro steel plant—that is the best that can be said about it, because it is still in a nebulous state. Production in the ordnance factories in 1963-64 is expected to be Rs. 100 crores as compared to Rs. 66 crores in 1962-63 and Rs. 41.45 crores in 1961-62.

To a fair extent, the slow growth of economic progress is due to the shortage of agricultural production which in 1962-63 recorded a fall of 3.3 per cent. While it may be argued that in a country like India in which, over large areas, the volume and distribution of rainfall are decisive factors in agriculture, it is difficult to achieve a steady rate of growth in agricultural production from year to year. This however makes it all the more essential to secure high yields per acre in areas with irrigation and assured rainfall, and the most important factor to be noted in this connection is that the policies and proposals of the Centre and the State Governments regarding ceiling on land, food procurement and distribution, and cooperative cultivation, and the proposed Seventeenth Amendment to the Constitution have disturbed the mind of the agriculturists. They have disturbed the framework in which alone agriculture can progress, and have aggravated the situation by introducing factors of uncertainty and insecurity all round.

As regards industry, the estimated increase of 7 to 8 per cent falls very much short of the postulated annual increase of 11 to 12 per cent. The pace of implementation of new industrial projects as also of expansion of

existing ones, and therefore, of additions to installed capacity suffered on account of the none too encouraging situation which prevailed in the capital market on the one hand, and the growing cost of construction on the other. In the case of nitrogenous fertilisers, vital for the sustenance and growth of the agricultural sector, a number of schemes remain unimplemented. Government seems to have little or no interest in the simple, inexpensive process of introducing Gobar gas plant which provides a cheap method of replenishing the land with nitrogenous fertilizers. The Government seem to be thinking only in terms of large factories, importing large amounts worth of machinery from abroad. Fertilizers produced in the factories go mainly to benefit large plantations and sugar factories for, the manner in which the controlled distribution is made it hardly ever reaches the poor agriculturist. And the amount of corruption and red tape involved in getting the fertilizers makes it impossible for him to get any of these fertilizers produced in the large fertilizer factories.

Progress in implementation suffered also in such industries as newsprint, paper and paper board, rayon grade pulp and cement. The uncertainty in the supply position of important raw materials and the general difficulty regarding foreign exchange continue,

A review of the Government's policies discloses considerable lack of coordination. A sick Prime Minister and a sick Government! After all, the whole economy has to function as a single entity. The different parts of it are closely inter-related. There must, therefore, be a uniformity in the working of different policies. This is not fully apparent at present. The monetary policy, while aiming to control prices of certain commodities, has affected the general level of productive activity. If the decontrol of prices on certain commodities announced recently represents a shift in Government's policy, it is certainly

[Shri Dahyabhai V. Patel.]

a step in the right direction. In isolation, however, this step will not have the desired effect. The fiscal policy is fashioned to draw away resources to the public sector without considering its effect on overall development. It is of less importance whether investment is made in this sector or that sector rather than whether it promotes the development of the whole economy. This purposive co-ordination between different sectors to maximise the flow of production with existing resources is the specific problem of planning and its timely execution. In both these aspects, our administrative machinery has, unfortunately, not reached the high standards which are needed.

A notable development of the year is, however, the record increase of about Rs. 100 crores in export earnings during the year 1963 which has been due mainly to the large quantity exported and the higher unit price. Exports of items covered by the various incentive schemes forming well over 20 per cent, of the total earnings have also shown considerable increase.

This should not, however, make us complacent. It is just possible that the rate of increase attained in the current year may not be sustained in the remaining two years of the Third Plan. For instance, sugar which is expected to account for exports worth Rs. 30 crores during the current year may not go beyond Rs. 15 crores next year due to lack of exportable surplus. Again, in the case of jute the encouraging trend of Rs. 175 crores in 1963-64 as against Rs. 155 crores in the previous year may not be continued in the year to come as the increase in the demand in the world markets is not likely to continue. Further, in respect of oil cakes, the increase in exports in the last two years of the Third Plan might just be moderate because of increasing domestic demand. Nor are the prospects in the case of textiles brighter.

One of the major handicaps to exports lies in the rising costs of Indian goods, brought about by fiscal levies, growing labour costs, low productivity, paucity of raw materials, administrative delays and the like. Little effort seems to have been made to show any improvement in this. The problem of exports cannot be dealt with in isolation and must, in the nature of things, form part of the national endeavour to create surpluses at reduced costs. It cannot be overemphasised that having regard to the increased foreign exchange content of our developmental programmes (heightened on account of defence requirements), the country's repayment obligations, and the fact that the scope for any significant pruning of the country's import bill is very limited, there is imperative need for an all-out effort to solve our export problem in a concerted and urgent manner.

Sir, slow progress is taking place in the matter of oil exploration particularly in Gujarat and in the setting up of refineries. I must repeat that Gujarat suffers from lack of coal. Coal has to be hauled to Gujarat from a thousand miles away. Gujarat suffers from lack of power. The hydro-electric schemes promised to Gujarat during the last two elections by the Congress Party as a sop to the voters have not yielded any power yet. And with the coming of the next election, the carrot of the Narbada Valley scheme is being dangled before the voters of Gujarat. How many years is this Narbada Valley scheme going to stay? We know the fate of the Kakrapar and the Mahi schemes. Is the execution of the Narbada Valley scheme going to be on the same lines? How much of the money allocated for these schemes is going to be spent on administrative, set-ups, on payment of salaries to officers and staff, and how much of it is going to be actually used on the working of the scheme, is a matter of doubt if the past experience is any guess. It is going to be very, very unsatisfactory.

Before I conclude, I must say that I agree with my friend, Shri Ganga Sharan Sinha, about the serious omission in the President's Address to refer to the loss to the country in the death of Dr. Rajendra Prasad. It is one more instance of the sickness that our Government suffers from.

شری اے۔ اہم۔ طارق : جناب والا۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے نائب صدر کے بیٹھن پر بولنے کا موقع دیا ہے۔ ہمارے بزرگ ممبر گنگا شاہو نے ہمارے سامنے اس چیز کو رکھا ہے کہ جہاں اس بیٹھن میں پوزیشنز کھینچنے کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ایک اچھی بات کہی گئی ہے وہاں اس ملک کی اس عظیم شخصیت کا جس نے اس ملک کی آزادی کی جنگ میں کافی قربانی کی۔ یعنی ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو ان کے خالص ان کی محنت ان کے ایثار ان کی وطن پرستی سے واقفیت نہ رکھتا ہوگا انہوں نے اس ملک میں ایک سب سے بڑی چیز پر زور دیا تھا وہ ہندو مسلم اتفاق تھا ان کے صداقت آشوب کو بھی بھی ہندوستان کے لوگ نہیں بھولیں گے لیکن اس عظیم شخصیت کا ذکر ہمارے اس ایڈریس میں کرنا ہم بھول گئے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کیا جائے ورنہ ہندوستان کے لوگ یہ سمجھیں گے

کہ پارلیمنٹ کے ممبرس یہ وہ لوگ جو ہندوستان کی حکومت میں آ جاتے ہیں وہ ایسے پرانے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں۔ لہذا ہم کو اس کمی کو پورا کرنی چاہئے۔

میں اس ایڈریس کی اور باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن ایک مسئلہ ہے جس سے میں ذاتی طور پر وابستہ ہوں جس کے ساتھ میری وابستگی میرا مستقبل ہے میری اولاد کا مستقبل ہے اور اس ملک کے رہنے والوں کا مستقبل ہے۔ وہ ہے کشمیر کا مسئلہ۔ جناب والا۔ اس ملک میں اور اس اہوان میں بہت لوگ ہیں جنہیں انتہائی تکلیف ہوئی یہ سن کر کہ امریکہ اور انگریز نے کیا رویہ اختیار کیا ہے اور جو کہ بہت افسوس ناک ہے لیکن وہ لوگ جو کشمیر کے سوال سے واقف ہیں۔ جو کشمیر کی تحریک آزادی سے واقف ہیں۔ جو ہندوستان کو آزادی کس طرح سے دی گئی ان حالات سے واقف ہیں ان کے لئے انگریز اور امریکہ کا یہ رول گوئی نئی چیز نہیں ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو سلوک ہماری شکایت کے ساتھ اقوام متحدہ میں ہوا اور اس کے بعد جس وقت ہم پر چھٹی حملہ ہوا اس دور میں بھی جو رول انگریز اور امریکہ کا رہا ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ

[شری اے - ایم - طارق]

یہ دونوں ملک ہندوستان کے ساتھ
انصاف کرنا نہیں چاہتے -

یہ بات میں نہیں سمجھ پایا اپنے
ہریز دوست سے جو کہ مجھ سے بزرگ
ہوں - میرا ایک کہس عدالت میں
ہے - اگر میرا وکیل اچھا نہیں ہے،
اگر میرا وکیل تھورا بہت مشغول ہو
جاتا ہے یا میرا وکیل عدالت کو
مشغول کرتا ہے تو اس کے معنی یہ
نہیں ہوں کہ جج اپنے انصاف کے
دخ کو بدل دے - اقوام متحدہ میں
یہ بھی ایک بہانہ ہے - یہ بھی کہا
گیا ہے کہ شری کرشنا مہلن نے
کشمیر کے کہس کو اس طرح سے
نہیں رکھا - صاحب کشمیر کے کہس
کو آپ ایسے رکھئے یا ویسے رکھئے -
ہونا وہی ہے جو انگریز اور امریکہ
چاہتے ہوں - اس کے متعلق میں
یہ کہنا چاہتا ہوں -

وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف تھرے
اقربا تھرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر
اگر آپ اس تھورل کے پھوٹے جائیں
گئے - اگر پارٹیشن کے زمانہ میں صوبہ
سرخد کے گورنر اولف کیرو کی تقریر کا
مضمون پڑھیں گے - اگو آپ کے سامنے
وہ خط ہوتا جو گورنر پنجاب سر موقی
نے اس زمانہ میں چودھری خلیل
الزماں کو لکھا تھا - سر کیرو نے گورنر
کی حیثیت سے ہتھیانوں کو مجبور

کہا تھا اور انہوں نے سمجھایا تھا کہ
کشمیر پر کس طرح سے حملہ کرنا
چاہئے - اس وقت یہ ہماری انتہائی
بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے ماحول
میں ہیں کہ جب ہم کسی ایک گروہ
کو ناراض نہیں کر سکتے ہوں - ورنہ
یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ساتھ
انگریزوں کی دشمنی ہے اور وہ ہونی
چاہئے - میں اس پوری تاریخ کو جو
انگریزوں کی اس ملک میں وہی ہے
ایک شعر میں بیان کر سکتا ہوں -

ان کا آنا حشر سے کچھ کم نہ تھا
اور جب پلٹے قیامت ڈھا گئے

انگریز جس طرح ہندوستان کو چھوڑ
کر گئے اس کے زخم ہم پر اور سو سال
تک وہیں گئے - یہ انگریزوں کی
سازش کا نتیجہ ہے جس کی وجہ
سے اس ملک میں ہندو مسلم
فسادات ہو جاتے ہیں اور بے گناہ
انسانوں کا خون کیا جاتا ہے - یہ بھیج
انگریزوں کا بویا ہوا ہے - ہم نے صرف
کوشش یہ کی تھی کہ اس زمین کی
تپہ کو صاف کریں اور ہم اس بھیج
تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے - اور
اس بھیج کی جڑ تک - -

ڈا॰ سوپال سیھ (نام নির্দেশিত) :
کونگرےٹس ہلکے خیلاف ہے لیکن آو وہاں
کا لےبر کا ہلکا ہے اور اصرام ہے، وہ
خیلاف نہیں ہے۔

شرعی ہے۔ ایم طارق : بہر حال
 لیبر حلقوں میں ہم ضرور ہیں لیکن
 ہمارے علم میں اتنی کمی ہے کہ
 ڈاکٹر گوپال سنگھ ہمیں کسی راستہ
 میں قائل کر سکتے ہیں لہذا اس میں
 ہم مسامحہ طور پر شریک ہیں لیکن
 اس بات کا دیکھ نہیں ہونا چاہئے
 بلکہ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہئے
 ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان
 کے لوگوں کو ہندوستان کی پارلیمینٹ
 کو کہ کشمیر کی حالت اتنی اچھی
 کر دیں کہ پھر ہمیں اقوام متحدہ
 میں انگریزوں کی حمایت کی ضرورت
 نہ پڑے نہ روس کے وٹو کی ضرورت
 پڑے۔ جب تک ہم کشمیر کی
 اندرونی حالت کو ٹھیک نہیں کرتے
 اس وقت تک ہمارے پاس یہ خوف
 رہے گا کہ یہ خوف ہم لوگوں میں
 خواہ مخواہ پیدا کر رکھا ہے۔ پچھلے
 سولہ سترہ سالوں میں سارے
 ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ انصاف
 نہیں کیا۔ ہندوستان کی حکومت
 نے ہندوستان کے عوام نے ہندوستان
 کے سیاست دانوں نے ان کے ساتھ ستم
 کئے اور ان معصوم بے گناہ شریف
 النفس کشمیریوں کی تاریخ سے آپ
 سب واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں
 کہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ کو جب اس
 ملک کی تقسیم اس بنیاد پر ہوئی
 کہ ہندو ہندوستان میں رہے گا اور
 مسلمان پاکستان میں رہے گا۔ ایک

طرف کشمیری مسلمانوں کے لئے قرار
 اور اسلام کا اسلامی جھنڈا رکھا گیا
 اور دوسری طرف ان کے سامنے یہ
 صورت دکھی گئی۔ ہندو ہندوستان
 ایک طرف اور اسلامی پاکستان ایک
 طرف۔ لیکن کشمیر کے مسلمانوں
 نے جن کی اکثریت تھی کہا نہیں۔
 یہ سوال ہندو مسلمانوں کا نہیں ہے۔
 یہ سوال بھگت رنگ کے جھنڈے اور
 سبز رنگ کے جھنڈے کا نہیں ہے۔
 یہ جنگ بھگت گیتا اور قرآن کی
 نہیں ہے یہ جنگ اقتصادیات کی
 ہے اور ہمارے روشن مستقبل کی ہے۔
 جہاں ہمارا روشن مستقبل ہوگا ہم
 وہیں جائیں گے۔ کشمیری ابھی
 فیصلہ کر بھی نہیں پائے تھے کہ ہم پر
 پاکستانیوں نے حملہ کر دیا۔ اور اس
 وقت کشمیریوں کا یہ حال تھا کہ نہ
 اس کے پاس کوئی فوج تھی نہ کوئی
 حکومت تھی۔ اگر کشمیر کے مسلمان
 چاہتے تو وہ پاکستان چا سکتے تھے اور
 آپ ان کو نہیں روک سکتے تھے لیکن
 کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان جانے
 سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا
 کہ ہمارا وطن ہندوستان ہے اور ہم
 ہندوستان میں رہیں گے۔ اس کے
 بعد ان کے ساتھ جو سلوک آئے کیا
 ہے اس کو ذرا دیکھئے کتنے لوگ ہیں
 اس ایران میں جو کشمیر کے کسی
 پولیٹیکل ورکر کو ذاتی طور پر جانتے
 ہوں گے۔ آپ نے کشمیری عوام کے
 ساتھ کیا ناتہ رکھا اور کشمیری لوگوں کے

[شری اے۔ ایم۔ طارق]

ساتھ آپ کے کہا تعلقات اور کہا سیاسی رشتہ ہے۔ لیکن آپ نے وہاں کی جھٹکا کے سامنے کبھی شہخ عبداللہ اور کبھی ہفتی فلم محمد کو پیش کیا۔ آپ کا تعلق کشمیری عوام کے ساتھ کبھی نہیں رہا اور نہ کشمیری عوام کو یہ معلوم ہے کہ اٹل دہری باجپٹی کون ہیں؟ ہونہیں گھٹا کون ہیں؟ مسٹر بہارگو کون ہیں اور گلنا شرن بابو کون ہیں۔ اس میں آپ کا تصور ہے ہم لوگوں کا نہیں ہے۔

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह (बिहार):
हमने श्री मुहम्मद तारिक से भी अपना
सरोकार रखा।

[شری اے۔ ایم۔ طارق: بہر حال

آپ نے علی محمد طارق سے کوئی سروکار رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا کریڈٹ طارق کو ہوگا کہ اس نے ایلے آپ پر تھوس دیا اور مجبور کیا کہ آپ اس کو مانیں۔ آپ نے اسے پہلے ماننے سے انکار کیا۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ آج پاکستان کی جو شکایت ہے اگر اس شکایت کو دیکھیں تو اس شکایت کے پیچھے چھڑ کیا ہے۔ پاکستان شکایت میں یہ کہتا ہے؟ مسٹر بہارگو نے یہ کہا ہے۔ پاکستان کے پریذیڈنٹ کہا ہے اور ان کے سامنے

اس سے ہوا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہفتی فلم محمد نے بھی کہا ہے کہ لوگ پابوسالٹ چاہتے ہیں۔ پریذیڈنٹ ایوب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہفتی فلم محمد نے بھی کہا ہے کہ لوگ شہخ عبداللہ کی دھائی کی سانگ کرتے ہیں۔ اور یہ کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ ہے۔ پریذیڈنٹ ایوب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہفتی صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر میں یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ کشمیر کا التاق پاکستان کے ساتھ ہونا چاہئے۔ اگر ہفتی فلم محمد نے یہ کہا ہے تو انہوں نے غلط کہا ہے۔ اگر اس غلطی کو استعمال کیا ہے پریذیڈنٹ ایوب نے تو یہ ان کی دانائی نہیں ہے؟ یہ ان کی خود فریبی ہے اور انہوں نے خود بھی دھوکا کھایا اور دنیا کو بھی دھوکا دیا۔ اس دوران کشمیر میں صرف یہ نعرے لگے تھے کہ موٹے مبارک کو حامی کرو، ہندو مسلمان کا اتحاد زندہ باد موجودہ حکومت کو برطرف کرو۔ یہ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے۔ یہ ہندوستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ یہ کہے کہ نہرو کی حکومت کو ہٹا دو۔ اگر گلنا بابو کہہ سکتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کی حکومت کو ہٹا دو تو وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ لیکن جب علی محمد طارق کہتا ہے کہ جواہر لال نہرو کی حکومت کو ہٹا دو تو میں پاکستانی ہوں۔

نہیں ہوں - ہندوستان کی حکومت ہندوستان کے لوگ اور ہندوستان کے اخبار مجھے اس طرح سے دبا نہیں سکتے - مجھے بھی اس ملک میں اس بات کا حق ہے کہ میں ظلم و ستم اور جبر کے خلاف آواز اٹھوں - آپ مجھے سے پاکستانی کہہ کر یہ حق چھین نہیں سکتے - آپ اس بات کو کہوں نہیں سوچتے کہ اثر اقلیت کو جن کی لڑکھوں کی عصمت خطرہ میں ہے جن کے بچوں کا مستقبل تاریک ہے - آپ کشمیریوں کو پاکستانی کہہ کر ان کی قربانی اور تاریخ کی توہین کر رہے ہیں - آپ صرف کشمیریوں کی توہین نہیں کر رہے ہیں - آپ اہلے انصاف اہلی دانوں ملدی اور اہلی سچہ کی بھی توہین کر رہے ہیں - اگر آپ لوگوں کو موت کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے تو کل یہ کہہ لگے کہ ہندوستان کی اکثریت نے کشمیری اقلیت کے ساتھ بلا احتیاط مذہب و ملت ظلم کیا، انصاف نہیں کیا - کشمیر کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں - لہٰذا کشمیر کے مسلمان بھی پاکستانی نہیں ہیں - کشمیر کے ہندو بھی پاکستانی نہیں ہیں - کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان سے نفرت ہو تو جائز ہے - انہوں نے آپ کی شکل نہیں دیکھی - جو دیکھی ہے تو وہ اہل حق غلام محمد کی شکل میں دیکھی ہے - جس نے

ایک مکان سے شروع کیا اور ۴۸ مکان پر ختم کیا - جس نے کشمیر میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا اور وہاں کی اقتصادیات پر قبضہ کیا ہے - اس لئے وہاں کی موٹر ٹرانسپورٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے، الٹل پمپس پر قبضہ کیا ہوا ہے - جنگلات کے ٹھیکے اور سڑکوں کے ٹھیکے سلہما ہاؤس وہ سب اس کے چلتے ہیں - یہ چند چیزیں ہیں جس پر کسی شہر، کسی ریاست اور کسی ملک کا مستقبل ہوتا ہے لیکن ان سب پر ایک خاندان نے قبضہ کیا ہوا ہے -

اس کے علاوہ آپ پچھلے پانچ دس سال کو اور مہاراجہ کشمیر کے تمام عہد حکومت کو دیکھ لیجئے - چلتے رہے کے کشمیر مہاراجہ کے سارے عہد حکومت میں ہوئے ہیں اس سے زیادہ کشمیر میں ایک دفعہ نہیں ہوتے ہیں - لہٰذا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ان شکایتوں کو کافذ ہر خرچ کرے - میرے پاس ایسے ثبوت ہیں - یہ میرے اخباروں کے ثبوت نہیں ہیں - یہ وہ اخبار ہیں جو کشمیر کے چھوٹے سائیکلو کونسل شہنوائن فرتہ دار کی پارٹی کے ہیں ایک ہفتہ میں ان میں چھ ریپس کا ذکر ہے - یہ لوکی معمولی آدمی کی لوکی نہیں ہے ایک کرنل کی لوکی ہے، ایک مسام کریجیویٹ لوکی ہے اور دو کشمیری پلٹانیاں ہیں جو اسکول جا رہی ہیں لیکن کسی کا کہیں درج نہیں کیا گیا - چھ مہلے سے زیادہ عرصہ گذرا ہے

[شہری اے - ایم - طارق]

اور اب تک ایک ملزم نہیں پکوا
گیا ہے کیونکہ ملزم دولت گ پارتی کے
ممبر ہیں - ملزم وہی ہیں جو
ہر سزاوار لوگوں کے دوست ہیں -
ہم یہاں ہیں ، ہم نشین ہیں -

حضور والا - آپ خود جانتے ہیں
کہ آپ نے اور ہم نے جو انگریزوں کو
شکست دی وہ توپ سے نہیں دی
کیونکہ ہمارے پاس توپیں نہیں تھیں -
صرف انگریزوں کے خلاف ہم میں
ایک نفرہ تھی - قوموں کی نفرہ
ایک ہی ہے زیادہ خطرناک اور تباہ کن
ہے اور جس کے سامنے تاریخ وہ ہے
اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا
ہے - آپ کس قوم سے نفرہ کریں اور
ان پر بار بار ظلم کرنے کی کوشش
کریں اور جب وہ ظلم کے خلاف آواز
اٹھائیں تو ان کی نیشنلسٹک بدلتے کا
قہقہہ بہت آسان نہیں ہے - کسی
مسلمان کو اس ملک میں پاکستانی
کہنا ایک لحاظ سے آسان ہے -

شہری فریدالحق انصاری : ہوم

سریکریٹری کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی
نعرہ لگا رہے ہیں -

[شہری اے - ایم - طارق : یہ درخواست

ہے میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا
کہ وہاں پاکستان کا نعرہ لگایا گیا ہے
وہاں شیخ عبداللہ زندہ باد کا بھی
نعرہ لگایا گیا - وہاں ایک وقت یہ

نعرہ بھی لگایا گیا جواہر لال مردہ باد -
میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں
اور اگر کشمیریوں نے یہ نعرہ لگایا ہے
جواہر لال نہرو مردہ باد ، تو یہ ان
کشمیریوں نے نعرہ لگایا ہے جس کا
واحد سہارا جواہر لال نہرو ہے - آپ
کو معلوم ہو کہ جب امپھ ٹوٹ جائے
جب یقین کو دھکا لگ جائے جب
انسان بے سہارا ہو جائے تو وہ اپنے
خدا کو بھی گالی دیتا ہے یقیناً
جواہر لال جی نہرو تو ایک طرف ان
کشمیریوں سے آپ آج بھی پوچھئے
کہ میں واحد انسان تھا کہ جب
کشمیر میں کوئی چلی تو میں ان
زخمیوں کو دیکھنے ہسپتال میں گیا -
کوئی بھٹی غلام محمد اس ہسپتال
میں نہیں گیا کوئی شمس الدین
نہیں گیا کیونکہ ان کا گھر سے نکلنا بے حد
مشکل ہے - وہ اگر گھر سے باہر بھی
آجائیں تو ان کو پولیس کی پٹا
میں بندو قوں اور دوسرے ہتھیاروں
کے ساتھ میں گڈرنا پڑتا ہے - میں
جب اس ہسپتال میں گیا تو مجھے
ان بیماروں نے کہا کہ جب آپ دہلی
جائیں تو اس چاچا سے کہیں -
اور ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اب چاچا
کو ان کی یاد بھی نہیں ہے - انہوں
نے یہ بھی کہا - کہ اس چاچا سے
کہنا کہ آج بھی ہم اس بات پر یقین
رکھتے ہیں جو آپ نے لال چوک میں
کہی تھی اور ہمارے سینوں میں جو
ہندوستانی

گولیاں ہندوستانی جسموں میں
 ہوں - یہ پاکستانی جسم نہیں
 ہوں - یہ چند لوگوں نے اپنا ظلم
 اپنے کرپشن اور ایلی شرارتوں کو
 چھپانے کے لئے نعرہ لگایا - ہم
 پاکستانی نہیں ہیں - میں آپ کو
 یقین دلانا چاہتا ہوں ایک کشمیری
 کی حیثیت سے کہ کشمیر میں بھی
 کچھ پاکستانی ہوں - میں ان لوگوں
 میں سے نہیں ہوں جو آپ کو دھوکا
 دینا یا جھوٹ بولنا - وہ ہیں ،
 لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے
 اور وہ آج سے پاکستانی نہیں ہوں
 بلکہ ۱۹۴۷ء سے پاکستانی ہوں جو
 یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان
 میں جائے - ایسے بھی کچھ لوگ
 ہوں جو شہنشاہ محمد عبداللہ کے ساتھ
 ہیں لیکن ہندوستان کے دشمن نہیں
 ہوں اور ایسے بھی بہت سے لوگ
 ہیں جو بخشی غلام محمد کے ساتھ
 ہیں لیکن ہندوستان کے دشمن ہیں -
 کشمیر کی موجودہ حکومت آج کشمیر
 کے مسلمانوں کو پاکستانی کہتی ہے
 اس لئے کہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں اس
 کے ظلم اور تشدد کے خلاف - کشمیر
 میں انڈیا پاکستانیوں کو کسی نے ہذا
 دی ہے تو وہ بخشی غلام محمد نے
 دی ہے اور کسی نے نہیں ، میں اس
 بات کو چیلنج کرتا ہوں اور میں
 اس بات کو کسی موقع پر اور کسی

جگہ پر ثابت کرنے کے لئے تھا
 ہوں - - -

SHRI SONUSING DHANSING PATIL
 (Maharashtra): On a point of order, Sir. The
 hon. Member may avoid personal references.

SHRI A. M. TARTQ: It is the history of the
 country. It is not a personal reference.

SHRI ^ONUSING DHANSING PATIL: iuu
 are making references to persons who are not
 present here.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Let
 him go on.

AN. HON. MEMBER: Let him go on.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: I
 am appealing to the Chair.

SHRI BHUPESH GUPTA: There is no point
 of order. He was the former Prime Minister
 there and the Kashmir question cannot be
 discussed without reference to a person who
 was the Prime Minister there for ten years.
 How can you do it?

SHRI A. B. VAJPAYEE: Yesterday, a
 Congress Member, Shri Deokinandan
 Narayan, referred to a speech delivered by
 Shri Golwalkar who was not present in the
 House. But I did not object to that. Why
 should Congress Members lose their patience?

AN HON. MEMBER: Because it pinches
 them.

SHRI P. N. SUPRU: How do you know that
 Mr. Tariq is not prepared to repeat outside the
 House what he has said here, and repeat it
 everywhere?

SHRI A. M. TARIQ: Everywhere, wherever
 you like. Who is the Chief Conservator of
 Forests there? Do you know, Mr. Patil?

[Shri A. M. Tariq.]

وہ ایلڈر برادر ہوں نام نہاد کشمیر کے
پریذیڈنٹ خورشید احمد خان کے -

AN HON. MEMBER: Who is he?

SHRI A. M. TARIQ: He is the elder brother of the so-called President of the so-called Azad Kashmir.

آج جو کشمیر میں I.A.S سپرنٹنڈنٹ تھانگ سے بلائے گئے ان میں سے چند کو شہخ مسعود عبداللہ نے پاکستانی ایجنٹ کے نام سے گرفتار کیا تھا - اور آج وہ آئی۔اے۔ ایس میں ہیں - کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ خود بخشی غلام مسعود کے دور حکومت میں جب ایک قی آئی - جی۔ریٹائر ہوئے اور جو بھی پیسہ ان کو ملا وہ اس پیسہ کو لے کر پاکستان چلے گئے - آج جس مولوی عباس کو آپ نے گرفتار کیا ہے یہ کہہ کر کہ وہ پاکستانی ہے -- اس میں دو راہیں نہیں ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے -- لیکن پتہ چلے ایک سال سے وہ کس کی سفارش پر ویزا بدلتا رہا - وہ صرف اس چابوس میں نکلتے سے پاکستانی نہیں ہوا ، وہ پاکستانی اس دن بھی تھا جب کشمیر میں آیا تھا اگر وہ ہندوستان کے لئے یہاں آیا تھا تو اس کے ویزا کے ریگمنڈیشن کون کرتا رہا اس وقت تک اور آج جب اس نے اس تحریک آزادی میں حصہ لیا تو وہ پاکستانی ہو گیا - یہ کس نے کیا تھا کہ جب

اس مہر واعظ کے بزرگ سر گئے تو کس نے اس کی موت کے دن کو نہشتل قائم کہہ کر تمام جموں کشمیر میں چھٹی کرائی تھی اور یہ چھٹی اس وقت کے ہوم منسٹر شری لال بہادر شاستری کی مرضی کے خلاف بخشی غلام مسعود نے کرائی تھی - کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مولوی فاروق جو اس ایکشن کمیٹی کا ممبر ہے اس کی دستار بندی خود بخشی غلام مسعود نے کی تھی - اگر یہ سب چھڑیں درست ہوں تو آج آپ کشمیریوں کو ظلم و ستم کا نشانہ کہوں بتاتے ہیں - کشمیریوں کا قصور کیا ہے - میں پچھلی باتوں کو چھوڑتا ہوں - میں انٹرنس کی بات ، امپورٹ کی بات اور بخشی غلام مسعود کی دولت کی بات چھوڑتا ہوں - اللہ نے اس کو دی ہے اور دے - ہو سکتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد کچھ حصہ سمجھکو بھی مل جائے لیکن سوال دولت کا نہیں ہے - میں دولت کی فکر بھی نہیں کرتا ہوں - حضرت بل میں مولے شریف چوری ہو جاتا ہے اور تاریخ کے پتہ چلے پانچ سو سال ... میں آپ سے صرف درخواست کروں گا اور آپ کی کھنتی کے خلاف پورے ملک میں نہیں کوونگا -

شری فرید الحق انصاری : ان کو

بھان کرنے دیجئے -

شرعی اے - اہم - طارق - حضرت

بل میں موٹے شریف کی چوری ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف لوگ پروٹسٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ موٹے شریف حاصل کرو۔ چوروں کا پتہ لگاؤ اور کوئی دوسری بات پہلے دن نہیں ہوتی ہے۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں لال چوک میں اور دوسری جگہوں میں اور ان کے دو ہی نعرے ہوتے ہیں کہ موٹے شریف حاصل کرو اور چوروں کا پتہ لگاؤ۔ اب اوقاف کمیٹی انصاف کرے۔ اب اوقاف کمیٹی ہے کیا؟ اوقاف کمیٹی چند لوگوں کا مجمع ہے جو اس وزارت کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کے چھرمیں ہیں ہمارے خاندان کشمیر جناب مرد آہن، بخشی غلام صاحب اور اس مرد آہن کے ساتھ ہی اس کے تین قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک ایکس ڈی - آئی - جو ان کے ایک عزیز کے فادر ہیں اور ایک ایکس کسٹوڈین جو ان کے ایک اور عزیز کے فادر ان لاہیں۔ ان کے علاوہ دو آدمی ہیں جن میں ایک چھوٹے مرد آہن بخشی عہد الرشید خود ہیں اور ایک متولی ہیں اور یہ سب آدمی اس وزارت کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اچانک چوری ہونے سے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے پروٹسٹ کیا۔ بخشی غلام مصدق کے اثر کا نتیجہ تھا کہ

دیکھو کشمیر نے اس کو انوائس نہیں کیا، آل انڈیا رینڈو نے بھی کچھ وقت کے لئے اس کا ذکر نہیں کیا اور پریذیڈنٹ ایوب خاں نے نہوز فلمیں کی۔ پاکستانوں نے کہا کہ اسکا چرانے والا ہندو ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر مشرقی پاکستان میں غریب ہندو ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور ہندوستان میں، کلکتہ میں، غریب مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔

لیکن آپ ذرا اس بات کو غور سے دیکھئے - معزز ممبران پارلیمنٹ میں چور کے ذریعہ سے اس بات کی درخواست کرونگا کہ آپ اس بات کو دیکھئے کہ اس دن اگر آل انڈیا رینڈو اس خبر کو براڈکاسٹ کر دے کہ چوری گوئے میں مسلمان کا ہاتھ ہے اور ہندو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو مشرقی پاکستان میں بے گناہ ہندو نہیں مارا جاتا اور یہاں بلکال میں بے گناہ مسلمان نہیں مارا جاتا تو اس اثر کو دیکھئے کہ ایک اہم واقعہ کی خبر کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ اس لئے کہ ایک کشمیری کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے، اس مرد آہن کو جو کہ دن کی روشنی میں گھر سے باہر نہیں آ سکتا، اور اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے پروٹسٹ کیا اور اس پروٹسٹ میں کشمیر کے ہندو شامل

[شہری - ایم - طارق]

تھے، مسلمان شامل تھے، سکھ شامل تھے اور کوئی ہندو مسلم فساد کی بات نہیں تھی۔ اچانک جب لوگ یہ سمجھ کر کہ حضرت بل جائینگے اکتے ہوئے تب بعضی عبدالرشید صاحب تشریف لاتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں سرکاری موٹر میں؟ اس کا جے۔ ایئرڈ کے - ۱۴ نمبر ہے وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے فرماتے ہیں - میں اس کا اردو ترجمہ کروں گا اور آپ میری ان باتوں کو انٹیلیجنس رپورٹ سے پوری دیکھ سکتے ہیں - وہ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ بیکار ہو و فقیر ہو تمہاری کانگریس میں آگ نہیں ہے۔ تم کہو جلوس نکالے آئے ہو، جاو، موٹے شریف وہاں پہنچ جائینگے۔ لوگوں نے اس کو اپنی توہین سمجھا اور ان کے پاس جتنی کانگریاں تھیں وہ سب کانگریاں عبدالرشید صاحب کے سر پر قربان کر دیں اور کہا کہ دیکھو ان میں آگ ہے کہ نہیں - وہ دو تھیں سو کانگریاں ان کے سر پر نچھاور کر دیں - جیسے کہ ہم ایک دوسرے پر پھول نچھاور کرتے ہیں - اسی آسانی سے وہ کانگریاں ان پر نچھاور کر دیں - کسی طرح یہ دوسرے سربراہان غائب ہو گئے تو لوگوں نے ان کی سرکاری گاڑی کو چلایا اور

چلانے کے بعد اس گاڑی کو عظیم الشان طریقہ سے دریابرد کر دیا - وہ کار - سرکاری تھی - ان کی اپنی نہیں تھی - اس کے بعد یہ ہجوم بعضی غلام متحید کی طرف جاتا ہے لیکن اس جائیداد کے پہلے اور اس جائیداد کے بعد غیر مسلمانوں کی لاکھوں روپوں کی دوکانیں ہیں - جنہوں نے ریپبلکنسی روٹ کو دیکھا ہے - ڈاکٹر گوپال سنگھ یہاں ہیں، باجھٹی صاحب یہاں ہیں -- وہ جانتے ہیں کہ لاکھوں روپوں کی ہندوؤں کی یہاں جائیداد ہے لیکن کسی ہندو کی جائیداد کو نہیں چھوڑا گیا بلکہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جن کی دوکانیں کھلی ہوئی تھیں ان پر کپڑا ڈالا کہ ان کو نہیں چلایا جاتا ہے اور اس خاندان کی جائیداد کو ہی چلانا ہے - تو ان کو اتنا صدمہ تھا ان کو اتنا قصہ تھا - جب کسی قوم کا قصہ کسی فرد کی طرف ہو جائے تو حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ سنگھن نکالے اور لوگوں کے قصہ کا جواب دے بلکہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے قصہ کا علاج کرے - اس جائیداد کو چلانے کے بعد لوگ واپس چلے آئے اور وہ کسی اور کی جائیداد کو نہیں چلاتے - اب گولی چلائی جاتی ہے - میری ایک شکایت ہے جو حکومت کے سامنے بھی ہے - ایک ایس - پی -

نے پستول سے ایک ہندو کو نشانہ بنا کر اس کو ایم کر کے گولی چلا دی تاکہ اس ہندو کے مرنے سے ہندو مسلم فساد ہو جائے۔ یہ میں آپ سے ایک ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے جو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو جانتا ہے کہتا ہوں کہ ایک ایس۔ پی۔ ایم کرتا ہے اور ایک ہندو کو جو کشمیر کا نہیں تھا، جو سہیا کا نوکر تھا، جو جاسوس سے کافی دور تھا، اس کے قریب نہیں تھا، اپنی دیوالیہ سے مارتا ہے اور اب تک اس معاملے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد ہندو مسلم تسادات کو کرانے کی کوشش کی گئی، کسی پر پاکستانی ہونے کا الزام لگایا گیا، کسی پر جن سنگھی ہونے کا الزام لگایا گیا۔

میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ آپ کو کشمیر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیئے۔ اس لئے نہیں کہ کشمیر بہت خوب صورت جگہ ہے بلکہ اس لئے کہ کشمیر آپ کے سیکولرزم کا نمائندہ بنا ہے اور کشمیریوں کو یہ تمنا ہے کہ وہ اسی ملک میں مریں گے، اسی ملک میں چھین گئے، لیکن اگر آپ کو واقعی کشمیری قوم کو اپنے ساتھ لانا ہے۔۔۔ اس کے۔۔۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے علیحدہ ہیں، آپ ہمارے جسم کو ساتھ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے دل

1100 RSD-5.

و دماغ کو ہمارے خلوں کو ہماری صحبت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہئے ہیں۔۔۔ تو پ بھی ہم سے خلوص و صحبت کا برتاؤ کیجئے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ کو ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کے اخباروں کو ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کہ آپ کو ایک خاندان وہاں چاہئے یا ۳۲ لاکھ انسان چاہئیں۔ آپ کو کشمیر کی پہاڑیاں چاہیں، آپ کو کشمیر کے سبزہ زاروں میں، کشمیر کی جھلنوں اور پہلوں میں دلچسپی ہے یا کشمیر کے انسانوں میں دلچسپی ہے اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو کر چکے یہ آپ کو کرنا ہے۔

نکتا بابو کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ اس ایڈریس میں مرحوم ڈاکٹر راجندر پرشاد کا نام نہیں ہے، مجھے بھی بہت ناگوار گزرا لیکن ہم کشمیریوں کو بھی ناگوار گزرا جب ہم پر گولی چلی تب کسی نے نہ اٹل بھاری ہانپتی نے منہ کھولا اور نہ بھوپیش کپتا نے منہ کھولا اور نہ گڈا بابو کوئی تیلیکیشن لے کر گئے۔ اب تک نہیں گئے تو اب جاوے اب یہی چاکر دیکھو کہ کشمیری کس حال میں ہیں، کشمیر کی ماؤں سے پوچھو، کشمیر کی بہنوں سے پوچھو، وہاں کے بچوں سے پوچھو۔

[شری اے - ایم - طارق]

میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ کشمیر میں آج چنگیز خاں کے نام میں اور بخششی غلام محمد کے نام میں کوئی فرق نہیں ہے -

شری اے - ایم - طارق : جو وہاں جاتے ہیں وہاں پیٹا جاتا ہے ۔

شری اے - ایم - طارق : جو مرد مجاہد ہوتے ہیں وہ مار سے نہیں دیتے -

شری اے - ایم - طارق : کشمیر میں بڑی طرح سے مارا جاتا ہے ، بے رحمی سے مارا جاتا ہے ۔

شری اے - ایم - طارق : آپ کو اس سے قریب نہیں چاہئے -

شری اے - ایم - طارق : اشنوک مہتا کا کیا ہوا ؟

شری اے - ایم - طارق : اچھا ہوا اور وہ پلاننگ کمیشن کے قیدی چیرمین ہو گئے - آپ بھی مار کھائیں - آپ بھی کچھ ہو جائیں گے - ایسی بات نہیں ہے - آپ نے اس چمڑ کو دیکھا نہیں ہے -

لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم کشمیریوں کو دکھ ہے کہ ہم سے کوئی سیاسی تعلق بھی ہندوستان کے لوگوں نے نہیں رکھا - آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ کون سنگھ توکرا ہیں جو افسوس کی بات ہے - یہ ہم کشمیری نہیں جانتے - ہم تو صرف

یہ جانتے ہیں کون سنگھ بہت اچھے اور بہت پاپولر ہیں - آپ کو دیکھنا چاہئے کہ کیا کیا حرکتیں کشمیر میں ہو رہی ہیں یا کشمیر میں وہ لوگ کر رہے ہیں - ہندوستان میں ایم - ایل - ایز - کا ڈیپارٹمنٹ لے کر آئے ہیں - بتائیے ایم - ایل - ایز - کیا ہیں - اس سے کہا ہوگا - کشمیر کے اس مرد آہن سے کہئے کہ ذرا سری نگر کی سڑک پر چلے - میں چیلنج کرتا ہوں میں اور بخششی غلام محمد ہاتھ میں ہاتھ دے کر سری نگر کی گلیوں میں نکلیں اور جو اپنے گھروں میں گور واپس آ سکے وہی پرانے مسٹر ہے - یہ جرات ان میں نہیں ہے - ایم - ایل - ایز - کو لے کر یہاں آنے سے کیا فائدہ ؟ کیوں نہیں کانگریس پروپیگنڈا کو جہوں اور سری نگر میں بلاتے اور وہاں کا نمونہ دکھاتے ؟ یہاں کانگریس پروپیگنڈا کے پاس آنے کی کیا بات ہے ان کو ذرا جفاں بلا کر دکھائیے -

شری بھراگی دھیرے : (وڈیسا) : کیا پراڈم مینسٹر آف انڈیا کو یہ پتا نہیں ہے ؟

شری فریدالاحق انصاری : یہ سب ان کو پتا ہے -

شری بھراگی دھیرے : یانی انکو بھی پتا ہے ۔

شری اے - ایم - طارق : ہم آپ سب کو پتا ہے - اس میں آپ

سب شریک ہیں۔ اس میں آپ بھی ہیں۔ آپ صرف کانگریس میں نہیں ہیں اور بھی کچھ ہیں۔ اس میں پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہیں سب ہیں۔ صادق علی صاحب بھی ہیں، گوپال سنگھ صاحب بھی ہیں، سب ہیں۔

تو اس کو آپ اجتماعی شکل میں دیکھئے۔ اگر کشمیر کی حالت بگڑے گی تو یہ غلط بات ہوگی، سارے ہندوستان کے نقشے کو بدلنا ہوگا۔ یہ صرف چند لوگوں کا سوال نہیں ہے پوری تواریخ کا سوال ہے۔ میں آج پوچھتا ہوں کون چیز دیکھتی ہے گنڈا بابو کو، بھوپیش کپتا کر، اٹل بھاری باجپئی کو، صادق علی صاحب کو کہ اکٹھا جا کر کم سے کم اس قوم کی حالت کو معلوم کریں۔ اگر آپ ان کے زخم پر مرہم نہیں لگا سکتے ہو تو ان کا زخم تو دیکھ سکتے ہو جو زخم دیکھنے سے انکار کرتا ہے وہ انسان نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آکر ان کے زخم کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر ان سے کوئی پوچھے کہ تم پر کیا گزری ہے۔ اتنا تو کرو۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے ورنہ یہ بھی واقعہ ہے کہ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں اس لئے ہیں کہ وہاں چولہلال ہیں، وہاں پی۔ این۔ سی۔ ہیں۔ آپ

نے کشمیریوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ چولہلال ہی نہیں ان کے ساتھ گنڈا بابو بھی ہیں، اٹل بھاری باجپئی ہیں، بھوپیش کپتا ہیں، گوپال سنگھ بھی ہیں۔ وہ بھی اس ملک میں رہتے ہیں اور وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔

उपसभाध्यक्ष (महावीर प्रसाद भार्गव) :
तारिक साहव, आधा घंटा हो चुका है।

شری اے۔ ایم۔ طارق : میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں لیکن آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمیں انگریزوں کو امریکنوں کو، شکست دینی ہے تو اس کا بہتر علاج یہی ہے کہ کشمیریوں کے زخم کا علاج کیا جائے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب مل کر ان زخموں کا علاج کریں گے۔

*[श्री ए० एम० तारिक : जनावे-
वाला, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे
नायब-सदर के भाषण पर बोलने का मौका
दिया है। हमारे बुजुर्ग मेम्बर गंगा बाबू
ने हमारे सामने इस चीज को रखा है कि जहाँ
इस भाषण में प्रेजिडेंट कैनेडी का जिक्र
किया गया है, जो कि एक अच्छी बात कही
गई है, वहाँ इस मुल्क की उस अजीम शक्कीयत
का जिसने इस मुल्क की आजादी की जंग में
काफी कुरबानी की याने हिन्दुस्तान में
शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो उनके
खुलस, उन की मुहब्बत, उनके ईसार, उनकी
वतनपरस्ती से वाकफियत न रखता होगा
और जो उन्होंने इस मुल्क में एक सब से बड़ी

*[] Hindi transliteration.

[श्री ए० एम० तारिक]

चीज पर जोर दिया था वो हिन्दू-मुस्लिम इत्तफाक था, उनके सदाकत आश्रम को कमी भी हिन्दुस्तान के लोग नहीं भूलेंगे, लेकिन उस अजीब शस्त्रीयत का जिक्र हमारे इस एड्रेस में करना हम भूल गये हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस कमी को किसी न किसी तरह पूरा किया जाये। वरना हिन्दुस्तान के लोग यह समझेंगे कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स या वो लोग जो हिन्दुस्तान का हुक्मत में आ जाते हैं वो अपने पुराने बुजुर्गों को भूल जाते हैं। लिहाजा हमको इस कमी को पूरा करना चाहिये।

मैं इस एड्रेस की और बातों की तरफ नहीं जाऊंगा लेकिन एक मसला है जिससे मैं जाती तौर पर वाबस्ता हूँ, जिसके साथ मेरी वाबस्ती मेरा मुस्तकबिल है, मेरो ओलद का मुस्तकबिल है और इस मुल्क के रहने वालों का मुस्तकबिल है। वह है काश्मीर का मसला। जनाबवाला, इस मुल्क में और इस एवान में बहुत लोग हैं जिन्हें इन्तहाई तकलीफ हुई यह सुन कर कि अमरीका और अंग्रेज ने क्या रवैया अख्तियार किया है, और जो कि बहुत अफसोसनाक है, लेकिन वो लोग जो काश्मीर के सवाल से वाकिफ हैं, जो कानून की तहरीकें आजादी से वाकिफ हैं, जो हिन्दुस्तान की आजादी किस तरह से दी गई उन हालात से वाकिफ हैं, उनके लिये अंग्रेज और अमरीका का यह रोल कोई नई चीज नहीं है और हम लोग जानते हैं कि काश्मीर में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो सलूक हमारी शिकायत के साथ एकवामेमुत्तहिदा में हुआ और उसके बाद जिस वक्त हम पर चीनी हमला हुआ उस दौर में भी जो रोल अंग्रेज और अमरीका का रहा है वह इस बात की जगह पर है कि ये दोनों मुल्क हिन्दुस्तान के साथ ईसाफ करना नहीं चाहते।

यह बात मैं नहीं समझ पाया अपने अजीज दोस्त से जोकि मुझसे बुजुर्ग हैं। मेरा एक केस अदालत में है। अगर मेरा वकील

अच्छा नहीं है अगर मेरा वकील थोड़ा बहुत मुश्तइल हो जाता है या मेरा वकील अदालत को मुश्तइल करता है तो इसके मायने यह नहीं है कि जज अपने ईसाफ के रुख को बदल दे। अक्वामेमुत्तहिदा में—यह भी एक बहाना है—यह भी कहा गया है कि श्री कृष्णा मेनन ने काश्मीर के केस को इस तरह से नहीं रखा। साहब, काश्मीर के केस को आप ऐसे रखिये या वैसे रखिये। होना वही है जो अंग्रेज और अमरीका चाहते हैं। इसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूँ—

वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे अकरवा मेरे करें कल का दावा किस पर

अगर आप इस तहरीक के पीछे जायेंगे। अगर पार्टीशन के जमाने में सूबा सरहद के गवर्नर ओलफ कैरो की तकरीर का मजमून पढ़ेंगे। अगर आपके सामने वो खत होता जो गवर्नर पंजाब सर मुडी ने उस जमाने में चौधरी खलीकुज्जमान को लिखा था। सर कैरो ने गवर्नर की हैसियत से पठानों को मजबूर किया था और उन्होंने समझाया था कि काश्मीर पर किस तरह से हमला करना चाहिये। इस वक्त ये हमारी इन्तहाई बद-किस्मती है कि हम ऐसे माहौल में हैं कि जब हम किसी एक गिराह को नाराज नहीं कर सकते हैं, वरना यह हकीकत है कि हमारे साथ अंग्रेजों की दुश्मनी है और वो होनी चाहिये। मैं इस पूरी तारीख को जो अंग्रेजों की इस मुल्क में रही है एक शिर् में बरतान कर सकता हूँ—

उन का आना हथ से कुछ कम न था
और जब पल्टे कयामत ढा गये।

अंग्रेज जिस तरह हिन्दुस्तान को छोड़ कर गये उसके जल्द हम पर और साँ साल तक रहेंगे। यह अंग्रेजों की साजिश का नतीजा है जिसकी बजह से इस मुल्क में हिन्दू मुस्लिम फसादात हो जाते हैं और बेगुनाह ईसानों का खून किया जाता है। ये बीज अंग्रेजों का बोया हुआ है।

हमने सिर्फ कोशिश यह की थी कि इस जमीन की तह को साफ करें और हम इस बीज तक भी नहीं पहुंचे होंगे और इस बीज की जड़ तक . . .

डा० गोपाल सिंह (नाम निर्देशित) : कंजरवेरिब हल्के खिलाफ हैं लेकिन जो वहां का लेबर का हल्का है और अवाम है, व खिलाफ नहीं है।

श्री ए० एम० तारिक : बहरहाल लेबर लकों में हम जरूर हैं लेकिन हमारे इल्म में इतनी कमी है कि डा० गोपाल सिंह हमें किसी रास्ते में डाल सकते हैं लिहाजा इसमें हम मसावी तौर पर शरीक हैं लेकिन इस बात का दुख नहीं होना चाहिये बल्कि हम को यह कोशिश करनी चाहिये, हिन्दुस्तान की हुकूमत को, हिन्दुस्तान के लोगों को, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को कि कश्मीर की हालत इतनी अच्छी कर दे कि फिर हमें अवामेमुरहिदा में अग्नेजों की हिमायत की जरूरत न पड़े, न रूस के वीटो की जरूरत पड़े। जब तक हम कश्मीर की अंदरूनी हालत को ठीक नहीं करते उस वक्त तक हमारे पास यह खौफ रहेगा, यह खौफ हम लोगों में खवामख्वाह पैदा कर रक्खा है। पिछले सोलह सत्रह सालों से सारे हिन्दुस्तान ने कश्मीर के साथ ईसाफ नहीं किया। हिन्दुस्तान की हुकूमत ने, हिन्दुस्तान के अवाम ने, हिन्दुस्तान के सियासतदनों ने उनके साथ सितम किये और उन ब.सूम बेगुनाह, शरीफ-उन-नफस कश्मीरियों की तारीख से आप सब ब.क्रिफ हैं। आप जानते हैं कि पंद्रह अगस्त, १९४७ को जब इस मुल्क की तकसीम इस बुनियाद पर हुई कि हिन्दू हिन्दुस्तान में रहेगा और मुसलमान पाकिस्तान में रहेगा। एक तरफ कश्मीरी मुसलमानों के लिये कुरान और इस्लामी जंडा रखा गया और दूसरी तरफ उनके सामने यह सूरत रक्खी गई—हिन्दू हिन्दुस्तान एक तरफ और इस्लामी पाकिस्तान एक तरफ। लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने जिनकी अवसरियत

थी कहा, नहीं। यह सवाल हिन्दू मुसलमानों का नहीं है। यह सवाल भगवेरंग के झंडे और सब्ज रंग के झंडे का नहीं है। यह जंग भगवत गीता और कुरान की नहीं है, यह जंग एकत-सादियात की है और रोशन मुस्तकबिल की है जहां हमारा रोशन मुस्तकबिल होगा हम वह ज.येंगे। कश्मीरी अभी फैसला कर भी नहीं पाये थे कि हम पर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया और उस वक्त कश्मीरियों का यह हाल था कि न उनके पास कोई फौज थी न कोई हुकूमत थी। अगर कश्मीर के मुसलमान चाहते, तो वो पाकिस्तान जा सकते थे और आप उनको नहीं रोक सकते थे लेकिन ब.इमर के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया। उन्होंने यह कहा कि हमारा बतन हिन्दुस्तान है और हम हिन्दुस्तान में रहेंगे। इसके बाद उनके साथ जो सलूक आपने किया है उसको जरा देखिये। कितने लोग हैं इस ऐवान में जो कश्मीर के किसी पॉलिटिकल वर्कर को जाती तौर पर जानते होंगे और आपने कश्मीरी अवाम के साथ क्या नाता रक्खा और कश्मीरी लोगों के साथ आप के क्या ताल्लुकात और क्या सियामी रिश्ता है। लेकिन आपने वहां की जनता के सामने कभी शेख अब्दुल्ला और कभी बरूशी गुलाम मोहम्मद को पेज किया। आप का ताल्लुक कश्मीरी अवाम के साथ कभी नहीं रहा और न कश्मीरी अवाम को यह मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन हैं, भूपेश गुप्ता कौन हैं, मिस्टर भागवा कौन हैं और गंगा शरण बाबू कौन हैं। इसमें आपका कुसूर है। हम लोगों का नहीं है।

श्री अजकिशोर प्रसाद सिंह (बिहार) : हमने अली मुहम्मद तारिक से भी अपना सरोकार रखा।

श्री ए० एम० तारिक : बहरहाल, आपने अली मोहम्मद तारिक से कोई सरोकार रखने की कोशिश नहीं की, इसका क्रेडिट तारिक

[श्री ए० एम० तारिक]

को होगा कि उसने अपने आपको आप पर ठूस दिया और मजबूर किया कि आप उसे मानें। आपने उसे पहले मानने से इंकार किया। लेकिन यह मसला ऐसा नहीं है। आज पाकिस्तान की जो शिकायत है उस शिकायत को देखें तो उस शिकायत के पीछे चीज क्या है? पाकिस्तान शिकायत में यह कहता है, मिस्टर शुद्रो ने यह कहा है, पाकिस्तान के प्रेजिडेंट ने कहा है, कि उनके सामने इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है जिसमें उन्होंने कहा है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद ने भी कहा है कि लोग प्लेबीसाइट चाहते हैं। प्रेजिडेंट अयूब ने अपनी तकरीर में कहा कि बख्शी गुलाम मुहम्मद ने भी कहा है कि लोग शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग करते हैं। और ये कश्मीर के लोगों का मुतालबा है। प्रेजिडेंट अयूब ने यह भी कहा है कि बख्शी साहब ने यह भी कहा है कि कश्मीर में यह नारा भी लगा था कि कश्मीर का इलहाक पाकिस्तान के साथ होना चाहिये। अगर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने यह कहा है तो उन्होंने यह गलत कहा है। अगर इस गलती को इस्तेमाल किया है प्रेजिडेंट अयूब ने तो यह उनकी दानाई नहीं है, ये उनकी खुदफरेबी है और उन्होंने खुद भी धोखा खाया और दुनिया को भी धोखा दिया। इस दौरान कश्मीर में सिर्फ ये नारे लगे थे कि मुएमुबारक को हासिल करो, हिन्दु मुसलमान का इत्तहाद जिन्दाबाद, मौजूदा हुकूमत को बरतारफ करो। ये कश्मीर के लोगों का हक है। ये हिन्दुस्तान के हर शहरी का हक है कि ये कहे कि नेहरू की हुकूमत को हटा दो। अगर गंगा बाबू कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत को हटा दो तो वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन जब अली मोहम्मद तारिक कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत को हटा दो तो मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं हूँ। हिन्दुस्तान की हुकूमत, हिन्दुस्तान के लोग और हिन्दुस्तान के अखबार मुझे इस तरह से दबा नहीं सकते। मुझे भी इस मल्क में इस बात का हक है कि

मैं जुल्मोसितम और जन्न के खिलाफ आवाज उठाऊँ। आप मुझसे पाकिस्तानी कह कर यह हक छीन नहीं सकते। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते कि अगर अक्लीयत को जिन को लड़कियों की इसमत खतरे में है, जिनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक है — आप कश्मीरियों को पाकिस्तानी कह कर उनकी कुर्बानी और तारीख की तौहीन कर रहे हैं। आप सिर्फ कश्मीरियों की तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप अपने ईसाफ, अपनी दानिशमंदी और अपनी समझ की भी तौहीन कर रहे हैं—अगर आप लोगों को मौत के रहमोकरम पर छोड़ेंगे तो कल ये कहेंगे कि हिन्दुस्तान की अक्सरीयत ने एक कश्मीरी अक्लीयत के साथ बिलालिहाज मजहबोमिल्लत जुल्म किया, ईसाफ नहीं किया। कश्मीर के लोक पाकिस्तानी नहीं हैं। कश्मीर के मुसलमान भी पाकिस्तानी नहीं। कश्मीर के हिन्दु भी पाकिस्तानी नहीं हैं। लेकिन अगर कश्मीर के लोगों को हिन्दुस्तान से नफरत हो तो जायज है उन्होंने आपकी शकल नहीं देखी, जो देखी है तो वो बख्शी गुलाम मोहम्मद की शकल में देखी है, जिसने एक मकान से शुरू किया और ४८ मकान पर खत्म किया, जिसने कश्मीर में किसी चीज को नहीं छोड़ा और वहां की इक्तसादियात पर कब्जा किया है। उसने वहां की मोटर ट्रांसपोर्ट पर कब्जा किया हुआ है, आयल पम्पस पर कब्जा किया हुआ है, जंगलात के ठेके और सड़कों के ठेके, सिनेमा हाउसेज, वो सब उसके चलते हैं। ये चन्द चीजें हैं जिस पर किसी शहर, किसी रियासत और किसी मुल्क का मुस्तकबिल होता है। लेकिन इन सब पर एक खानदान ने कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा आप पिछले पांच दस साल को और महाराजा कश्मीर के तमाम अहदेहुकूमत को देख लीजिए। जितने रेप के केसेज महाराजा के सारे एहदेहुकूमत में हुए हैं उससे ज्यादा कश्मीर में एक हफ्ते में होते हैं लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इन शिकायतों को कागज पर दर्ज करे।

मेरे पास ऐसे सबूत हैं। ये मेरे अखबारों के सबूत नहीं हैं। ये वो अखबार हैं जो कश्मीर के चेरमेन लेजिस्लेटिव कौंसिल, शिव-नारायण फतेदार, की पार्टी के हैं। एक हफ्ते में उनमें छः रेप्स का जिक्र है। ये लड़की मामूली आदमी की लड़की नहीं है। एक कर्नल की लड़की है, एक मुस्लिम ग्रेजुएट लड़की है और दो कश्मीरी पंडितानियां हैं जो स्कूल जा रही थीं लेकिन किसी का केस दर्ज नहीं किया गया। छः महीने से ज्यादा अर्सा गुजरा है और अब तक एक मुजरिम नहीं पकड़ा गया है। क्योंकि मुजरिम रूलिंग पार्टी के मेम्बर हैं। मुलजिम वहीं हैं जो बरसरेइकतदार लोगों के दोस्त हैं, हम-व्याला हैं, हम-नशी हैं।

हजूर वाला, आप खुद जानते हैं कि आपने और हमने जो अंग्रेजों को शिकस्त दी वो तोप से नहीं दी क्योंकि हमारे पास तोपें नहीं थीं। सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ हममें एक नफरत थी। कौमों की नफरत एटम बम से ज्यादा खतरनाक और तबाहकून है और जिसके सामने तारीख है वो इसका अच्छी तरह से देख सकता है। आप किसी कौम से नफरत करें और उन पर बार बार जुल्म करने की कोशिश करें और जब वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएँ तो उनकी नेशनलेटी बदलने का ढंग बहुत आसान नहीं है। किसी मुसलमान को इस मुल्क में पाकिस्तानी कहना एक लिहाज से आसान है।

श्री फरीदुल हक अन्सारी : होम सेक्रेटरी कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नारा लगा रहे हैं।

श्री ए० एस० तारिक : ये दुरुस्त है। मैं इससे भी इंकार नहीं करता कि वहां पाकिस्तान का नारा लगाया गया। वहां शेख अब्दुल्ला जिन्दाबाद का भी नारा लगाया गया। वहां एक वक्त यह भी नारा लगाया गया कि जवाहर लाल नेहरू मुर्दाबाद। मैं इससे इंकार नहीं करता हूँ और अगर कश्मीरियों ने यह नारा लगाया है “जवाहरलाल नेहरू मुर्दाबाद” तो यह उन कश्मीरियों ने नारा लगाया है जिनका वाहिद सहारा जवाहरलाल नेहरू है। आपको

भालूम हो कि जब उम्मीद टूट जाये, जब यकीन को धक्का लग जाये, जब इंसान बेसहारा हो जाये, तो वो अपने खुदा को भी गाली देता है, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू तो एक तरफ। इन कश्मीरियों से आप आज भी पुछिये कि मैं वाहिद इंसान था कि जब कश्मीर में गोली चली तो मैं उन जख्मियों को देखने अस्पताल में गया। कोई बख्शी गुलाम मोहम्मद इस अस्पताल में नहीं गया, कोई शमसुद्दीन नहीं गया, क्योंकि उनका घर से निकलना बेहद मुश्किल है। वो अगर घर से बाहर भी आ जायें तो उनको पुलिस की तनाह में और बन्दूकों और दूसरे हथियारों के साथे में गुजरना पड़ता है। मैं जब उस हस्पताल में गया तो मुझे उन बोमारों ने कहा कि जब आप देहली जायें तो उस चाचा से कहें—और उनके यह अल्फाज हैं कि अब चाचा को उनकी याद भी नहीं है—उन्होंने यह भी कहा—कि चाचा से कहना कि आज भी हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो आपने लाल चौक में कही थी और हमारे सीने में जो हिन्दुस्तानी गोलियां हैं वो हिन्दुस्तानी गोलियां हिन्दुस्तानी जिस्मों में हैं, यह पाकिस्तानी जिस्म नहीं हैं। यह चन्द लोगों ने अपना जुल्म, अपने करप्शन और अपनी शरा-रतों को छुपाने के लिये नारा लगाया। हम पाकिस्तानी नहीं हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ एक कश्मीरी की हैसियत से कि कश्मीर में भी कुछ पाकिस्तानी हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको धोखा दूँ या झूठ बोलूंगा, वो हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत थोड़ी है और आज से पाकिस्तानी नहीं हैं बल्कि १९४६ से पाकिस्तानी हैं, जो यह चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान में जाये। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के साथ हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के दुश्मन नहीं हैं और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बख्शी गुलाम मुहम्मद के साथ हैं लेकिन हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं। कश्मीर की मौजूदा हुकूमत आज कश्मीर के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहती है इसलिये कि लोग आवाज उठाते हैं उसके जुल्मों तशदद के खिलाफ। कश्मीर में अगर पाकि-

स्तानियों को किसी ने पनाह दी है तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने दी है और किसी ने नहीं। मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ और मैं इस बात को किसी मौके पर और किसी जगह पर साबित करने के लिये तैयार हूँ।

SHRI SONUSING DHANSING PATIL (Maharashtra): On a point of order, Sir. The hon. Member may avoid personal references.

SHRI A. M. TARIQ: It is the history of the country. It is not a personal reference.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: You are making references to persons who are not present here.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Let him go on.

AN HON. MEMBER: Let him go on.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: I am appealing to the Chair.

SHRI BHUPESH GUPTA: There is no point of order. He was the former Prime Minister there and the Kashmir question cannot be discussed without reference to a person who was the Prime Minister there for ten years. How can you do it?

SHRI A. B. VAJPAYEE: Yesterday a Congress- Member, Shri Deokinandan Narayan, referred to a speech delivered by Shri Golwalkar who was not present in the House. But I did not object to that. Why should Congress Members lose their patience?

AN. HON. MEMBER: Because it pinches them.

SHRI P. N. SAPRU: How do you know that Mr. Tariq is not prepared to repeat outside the House what he has said here, and repeat it everywhere?

SHRI A. M. TARIQ: Everywhere, wherever you like. Who is the Chief

Conservator of Forests there? Do you, know, Mr. Patil?

वह एलडर ब्रदर हैं नाम निहाद कश्मीर के प्रेजिडेंट खुरशीद अहमद खां।

AN HON. MEMBER: Who is he?

SHRI A. M. TARIQ: He is the elder brother of fee co-called President of the so-called Azad Kashmir.

आज जो कश्मीर में आई० ए० एस० स्पेशल डंग से बनाये गये उनमें से चन्द को शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी एजेंट के नाम से गिरफ्तार किया था और आज वो आई० ए० एस० में हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि खुद बख्शी गुलाम मोहम्मद के दोरे हुकूमत में जब एक डी० आई० जी० रिटायर्ड हुए और जो भी पैसा उनको मिला वो उस पैसे को लेकर पाकिस्तान चले गये। आज जिस मौलवी अब्बास को आपने गिरफ्तार किया है यह कह कर कि वो पाकिस्तानी है— इसमें दो राय नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है—लेकिन पिछले एक साल से वो किस की सिफारिश पर बीजा बदलता रहा? वो सिर्फ इस जुलूस में निकलने से पाकिस्तानी नहीं हुआ, वो पाकिस्तानी उस दिन से भी था जब कश्मीर में आया था। अगर वो १५ दिन के लिये यहां आया था तो उसके बीजा के रिकमैन्डेशन कौन करता रहा इस वक्त तक और आज जब उसने तहरीके आजादो में हिस्सा लिया तो वो पाकिस्तानी हो गया। ये किसने किया था कि जब उस मीर वाइज के बुजुर्ग मर गये तो किसने उसकी मौत के दिन को नेशनल डे कह कर तमाम जम्मू कश्मीर में छूट्टी करवाई थी और यह छूट्टी उस वक्त के होम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री की मर्जी के खिलाफ बख्शी गुलाम मोहम्मद ने करवाई थी। क्या यह हकीकत नहीं है कि मौलवी फारूक जो इस एक्शन कमेटी का मेम्बर है उसकी दस्तारबन्दी खुद बख्शी गुलाम मुहम्मद ने की थी। अगर ये सब चीजें दुस्त हैं तो आज आप कश्मीरियों को

जुल्मोसितम का निशाना क्यों बनाते हैं । कश्मीरियों का कुसूर क्या है । मैं पिछली बातों को छोड़ता हूँ । मैं लाइसेंस की बात, इम्पोर्ट की बात और बख्शी गुलाम मोहम्मद की दौलत की बात छोड़ता हूँ । अल्लाह ने उसको दी है, और दे । हो सकता है कि उसके जाने के बाद कुछ हिस्सा मुझ को भी मिल जाये । लेकिन सवाल दौलत का नहीं है । मैं दौलत की फिक्र भी नहीं करता हूँ । हजरतबल में मुएशरीफ चोरी हो जाता है और तारीख के पिछले पांच सौ साल . . . मैं आपसे सिर्फ दरखास्त करूँगा और आपकी घंटी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करूँगा ।

श्री फरीदुल हक अन्सारी : इनको बयान करने दीजिए ।

श्री ए० एम० तारिक : हजरतबल में मुएशरीफ की चोरी हो जाती है और उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं । वो यह कहते हैं कि मुएशरीफ हासिल करो, चोरों का पता लगाओ, और कोई दूसरी बात पहले दिन नहीं होती है । लोग जमा हो जाते हैं लाल चौक में और दूसरी जगहों में और उनके दो ही नारे होते हैं कि मुएशरीफ हासिल करो और चोरों का पता लगाओ । आँकाफ्र कमेटी ईसाफ करे । अब आँकाफ्र कमेटी है क्या ? आँकाफ्र कमेटी चन्द लोगों का मजमा है जो इस ज़ियारत की देखभाल करते हैं और उसके चेयरमैन हैं हमारे खालिदे कश्मीर जनाब मरदेआहून बख्शी गुलाम साहब और उस मरदेआहून के साथ ही उस के तीन करीबी रिश्तेदार हैं एक एक्स डी० आई० जी० जो उनके एक अजीज के फादर-इन-ला हैं और एक एक्स कस्टोडियन जो उनके एक और अजीज के फादर-इन-ला हैं । उनके अलावा जो और आदमी हैं जिनमें एक छोटे मरदेआहून बख्शी अब्दुल रशीद खुद हैं और एक मुतवल्ली हैं और ये सात आदमी इस ज़ियारत की देखभाल करते हैं । अचानक चोरी होने से लोगों को तकलीफ हुई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया ।

बख्शी गुलाम मोहम्मद के असर का नतीजा था कि रेडियो कश्मीर ने इसको एनाउन्स नहीं किया । आल इंडिया रेडियो ने भी कुछ वक्त के लिये इसका जिक्र नहीं किया और प्रेजीडेंट अबूब खां ने न्यूज फ्लैश की । पाकिस्तानियों ने कहा कि इसका चुराने वाला हिन्दू है और इसका नतीजा यह हुआ कि उधर मशरिफी पाकिस्तान में गरीब हिन्दू जुल्मो सितम का शिकार हुए और हिन्दुस्तान में कलकत्ता में गरीब मुसलमान जुल्मो सितम का शिकार हुए ।

लेकिन आप जरा इस बात को गौर से देखिये । मुअज्जिज मेम्बराने पार्लियामेंट में चेयर के जरिये से इस बात की दरखास्त करूँगा कि आप इस बात को देखिये कि उस दिन अगर आल इंडिया रेडियो इस खबर को ब्राडकास्ट कर दे कि चोरी करने में मुसलमान का हाथ है और हिन्दू का सवाल ही पैदा नहीं होता तो मशरिफी पाकिस्तान में बेगुनाह हिन्दू नहीं मारा जाता और यहां बंगाल में बेगुनाह मुसलमान नहीं मारा जाता । तो इस असर को देखिये कि एक अहम वाकिये की खबर को भी रोका जा सकता है इसलिये कि एक कश्मीरी को नाराज नहीं किया जा सकता है । उस मरदेआहून को जो कि दिन की रोशनी में घर से बाहर नहीं आ सकता और उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता है तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में कश्मीर के हिन्दू शामिल थे, मुसलमान शामिल थे, सिक्ख शामिल थे और कोई हिन्दू मुसलिम फिसाद की बात नहीं थी । अचानक जब लोग यह समझ कर कि हजरतबल जायेंगे इकट्ठे हुए, तब बख्शी अब्दुल रशीद साहब तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाते हैं सरकारी मोटर में । उसका जे एण्ड के १४ नम्बर है । वो लोगों को देखते हैं । बाहर खड़े होते हैं और लोगों से फरमाते हैं—मैं इसक, उर्दू तर्जुमा करूँगा और आप मेरी इन बातों को इंटेलेजेंट

[श्री ए० एम० तारिक]

रिपोर्ट से पूरी देख सकते हैं—वो लोगों से फरमाते हैं कि भिखारियों व फकीरों तुम्हारी कांगड़ी में आग नहीं है, तुम क्यों जुलूस निकलने आये हो, जाओ, मुएशरीफ वहाँ पहुँच जायेगा। लोगों ने इसको अपनी तोहीन समझा और उनके पास जितनी कांगड़ियाँ थीं वो सब कांगड़ियाँ अब्दुल रशीद साहब के सिर पर कुर्बान कर दीं और कहा कि देखो इनमें आग है कि नहीं। वो दो तीन सौ कांगड़ियाँ उनके सिर पर निछावर कर दीं जैसे कि हम एक दूसरे पर फूल निछावर करते हैं, उसी आसानी से वो कांगड़ियाँ उन पर निछावर कर दीं। किसी तरह वो दूसरे मरदेआहन गायब हो गये तो लोगों ने उनकी सरकारी गाड़ी को जलाया और जलने के बाद उस गाड़ी को अजमउशान तरीके से दरियाबुर्द कर दिया। वो कार सरकारी थी, उनकी अपनी नहीं थी। इसके बाद यह हजूम बरूशी गुलाम मोहम्मद की तरफ जाता है लेकिन उस जायदाद के पहले और उस जायदाद के बाद गैर मुसलमानों की लाखों रुपयों की दूकानें हैं। जिन्होंने रेजिडेंसी रोड को देखा है—डा० गोपाल सिंह यहाँ हैं, वाजपेयी साहब यहाँ हैं, वो जानते होंगे कि लाखों रुपये की हिन्दुओं की यहाँ जायदाद है लेकिन किसी हिन्दू की जायदाद को नहीं छेड़ा गया बल्कि लोग उनके सामने खड़े हो गये और जिनकी दुकानें खुली हुई थीं उन पर कपड़ा डाला कि उनको नहीं जलाना है और इस खानदान की जायदाद को ही जलाना है। तो उनको इतना सदमा था, उनको इतना गुस्सा था। जब किसी कौम का गुस्सा किसी फर्द की तरफ हो जाये तो हुकूमत का यह फर्ज नहीं है कि संगीन निकाले और लोगों के गुस्से का जवाब दे बल्कि हुकूमत का फर्ज है कि वो लोगों के गुस्से का इलाज करे। इस जायदा को जलाने के बाद लोग वापिस चले आये और वो किसी और की जायदाद को नहीं जलाते। अब गोली चलाई जाती है। मेरी एक शिकायत है

जो कि हुकूमत के सामने भी है। एक एस० पी० ने पिस्तौल से एक हिन्दू को निशाना बना कर, उसको ऐम करके, गोली चला दी ताकि इस हिन्दू के मरने से हिन्दू-मुस्लिम फसाद हो जाय। ये मैं आपसे एक मेम्बर पार्लियामेंट की हैसियत से जो अपने फरायेज और जिम्मेदारियों को ज.नता है कहता हूँ कि एक एस० पी० ऐम करता है और एक हिन्दू को जो काश्मीर का नहीं था, जो सीबा का नौकर था, जो जुलूस से काफी दूर था, उसके करीब नहीं था, अपने रिवाल्वर से मारता है और अब तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया। इसके बाद हिन्दू-मुस्लिम फसादाद को कराने की कोशिश की गई। किसी पर पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाया गया, किसी पर जनसघो होने का इल्जाम लगाया गया।

मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कश्मीर को अपने साथ रखना चाहिये। इसलिये नहीं कि कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है बल्कि इसलिये कि कश्मीर आपके सेक्युलरिज्म का नुमाइन्दा बना है और कश्मीरियों की यह तमन्ना है कि वो इसी मुल्क में मरेगे, इसी मुल्क में जियेंगे। लेकिन अगर आपको व.कई कश्मीरी कौम को अपने साथ लाना है—इसके यह माइने नहीं हैं कि हम आपसे अलाहदा हैं, आप हमारे जिस्म को साथ रख सकते हैं लेकिन अगर आप हमारे दिल और दिमाग को, हमारे खुलूस को, हमारी मुहब्बत को अपने साथ रखना चाहते हैं—तो आप भी हमसे खुलूस और मुहब्बत का बर्ताव कीजिये। आपको यह फैसला करना है, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को, हिन्दुस्तान के लोगों को, हिन्दुस्तान के अखबारों को, हिन्दुस्तान की तमाम मियासी जमायतों को कि आपको एक खानदान वहाँ चाहिये या ३२ लाख इंसान चाहियें। आपको कश्मीर की पहाड़ियाँ चाहियें, आपको कश्मीर के सबजाजारों में, कश्मीर की झीलों और फलों में दिलचस्पी है या कश्मीर के इन्सानों

में दिलचस्पी है, इसका फैसला आपके हाथ में है। हम तो कर चुके यह आपको करना है।

गंगा बाबू को यह बहुत नागवार गुजरा कि इस एड्रेस में महम्मू डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का नाम नहीं है। मुझको भी बहुत नागवार गुजरा लेकिन हम कश्मीरियों को भी नागवार गुजरा जब हम पर गोली चली तब किनी ने, न अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंह खोला, न, भूपेश गुप्ता ने मुंह खोला, और न गंगा बाबू कोई डेलीगेशन लेकर गये। अब तक नहीं गये तो अब जाओ, अब भी जाकर देखो कि कश्मीरी किस हाल में हैं। कश्मीर की मांओं से पूछो, कश्मीर की बहनों से पूछो, वहां के बच्चों से पूछो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कश्मीर में आज चंगेजवां के नाम में और बख्शी गुलाम मोहम्मद के नाम में कोई फर्क नहीं है।

श्री ए० बी० वाजपेयी : जो वहां जाते हैं उन्हें पीटा जाता है।

श्री ए० एम० तारिक : जो मरदे-मुजाहिद होते हैं वो मार से नहीं डरते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कश्मीर में बुरी तरह से मारते हैं, बेहद मार पड़ती है।

श्री ए० एम० तारिक : आपको इससे डरना नहीं चाहिये।

श्री ए० बी० वाजपेयी : अशोक मेहता का क्या हुआ ?

श्री ए० एम० तारिक : अच्छा हुआ और वो प्लानिंग कमिशन के चेयरमैन हो गये। आप भी मार खाइये, आप भी कुछ हो जायेंगे। ऐसी बात नहीं है। आपने इस चीज को देखा नहीं है।

लेकिन सवाल यह है कि आज हम कश्मीरियों को दुख है कि हमसे कोई सियासी

ताल्लुक भी हिन्दुस्तान के लोगों ने नहीं रखा। आज हमसे कहा जाता है कि कर्णसिंह डोगरा हैं, जो अफसोस की बात है। ये हम कश्मीरी नहीं जानते। हम तो सिर्फ यह जानते हैं कि कर्णसिंह बहुत अच्छे और बहुत पॉपुलर हैं। आपको देखना चाहिये कि क्या क्या हरकतें कश्मीर में हो रही हैं या कश्मीर में वो लोग कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में एम० एल० एज० का डेलीगेशन लेकर आते हैं। बताइये एम० एल० एज० क्या हैं। इससे क्या होगा। कश्मीर के इस मरदेआहन से कहिये कि जरा श्रीनगर को सड़क पर चले। मैं चैलेंज करता हूं। मैं और बख्शी गुलाम मोहम्मद हाथ में हाथ देकर श्रीनगर को गलियों में निकलें और जो अपने कपड़ों में घर वापिस आ सके वही प्राइम मिनिस्टर है। ये जुरंत उनमें नहीं है। एम० एल० एज० को सुकर यहां आने से क्या फायदा। क्यों नहीं कांग्रेस प्रेजिडेंट को जम्मू और कश्मीर में बुलाते और वहां का नमूना दिखाते? यहां कांग्रेस के प्रेजिडेंट के पास आने की क्या बात है? उनको जरा वहां बुला कर दिखाइये।

श्री बैरागी द्विवेदी : (उड़ीसा) : क्या प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया को यह पता नहीं है ?

श्री फरीदुल हक अन्सारी : यह सब उनका पता है।

श्री बैरागी द्विवेदी : यानी उनको भी पता है।

श्री ए० एम० तारिक : हम आप सबको पता है। इसमें आप सब शरीक हैं। इसमें आप भी हैं। आप सिर्फ कांग्रेस में नहीं हैं। और भी कुछ हैं। इसमें पार्लियामेंट के मेम्बर ही नहीं हैं, सब हैं, सादिक अली साहब भी हैं, गोपाल सिंह साहब भी हैं, सब हैं।

तो इसको आप इज्तमाही शकल देखिये, अगर कश्मीर की हालत बिगड़ेगी तो यह गलत बात होगी। सारे हिन्दुस्तान

[श्री ए० एम० तारिक]

के नक्शे को बदलना होगा। ये सिर्फ चन्द लोगों का सवाल नहीं है। पूरी तारीख का सवाल है। मैं आज पूछता हूँ कि कौन चीज रोकती है गंगा बाबू को, भूपेश गुप्ता को, अटल बिहारी वाजपेयी को, सादिक अली साहब को, कि इकट्ठा जाकर कम से कम इस कौम की हालत को मालूम करें। अगर आप उनके जखम पर सरहम नहीं लगा सकते हो तो उनके जखम तो देख सकते हो। जो जखम देखने से इंकार करता है वो इंसान नहीं। वो चाहते हैं कि कोई आकर उनके जखम को देखे और इसको देख कर उनसे कोई पूछे कि तुम पर क्या गुजरी है। इतना तो करो, यह आपका इखलाकी फर्ज है वरना यह भी वाकिया है कि कश्मीरी यह समझते हैं कि हम हिन्दुस्तान में इसलिये हैं कि वहाँ जवाहरलाल हैं, वहाँ पं० एन० सप्रू हैं। आपने कश्मीरियों को यह यकीन दिलाया है कि जवाहरलाल ही नहीं, उनके साथ गंगा बाबू भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, भूपेश गुप्ता हैं, गोपाल सिंह भी हैं, वो भी इस मुल्क में रहते हैं और वो भी तुम्हारे साथ हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबोर प्रसाद भागंब) : तारिक साहब, आधा घंटा हो चुका है।

श्री ए० एम० तारिक : मैं आपका बेहद दुःखी हूँ। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खतम करता हूँ लेकिन आखिर में यह कहूँगा कि अगर हमें अंग्रेजों को, अमरीकनों को, शिक त देनी है तो इसका बेहतर इलाज यही है कि कश्मीरियों के जखम का इलाज किया जाये और मुझे उम्मीद है कि आप सब मिल कर इन जखमों का इलाज करेंगे।

श्री ए० बी० वाजपेयी : उपसभाध्यक्ष जी, उपराष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति जी के कर्तव्यों का पालन करते हुए जो अभिभाषण दिया है उसमें न तो कोई रंग है, न रस है;

भाषण में न स्पष्टता है न दृढ़ता है; भविष्य के बारे में उसमें न कोई निसंदिग्ध दिशा—निर्देश है और न जो लक्ष्य रखे गये हैं उनकी पूर्ति का कोई उद्गम संकल्प ही प्रकट किया गया है। शायद इसका कारण यह है कि नई दिल्ली की राजनैतिक परिस्थिति बड़ी नाजुक है और उपराष्ट्रपति जी के भाषण पर उसका असर हुआ है। हमारे राष्ट्रपति जी अस्वस्थ हैं और उपराष्ट्रपति जी उनका भार सम्हाल रहे हैं प्रधान मंत्री जी दुर्बल हैं। कोई उप-प्रधान मंत्री नहीं है मन्त्रियों में इस बात पर विवाद है कि किसका नम्बर एक है, किसका दूसरा, किसका तीसरा, और किसका चौथा।

उत्तराधिकार का संघर्ष पूरे जोर पर चल रहा है। नित्य नए गठबन्धन हो रहे हैं। शतरंज पर नयी चालें चली जा रही हैं। इसका परिणाम देश पर अच्छा नहीं हो रहा है। जनता निराशा में जा रही है, प्रशासन ढीला हो रहा है और विदेशों में जो भारत का चित्र है वह धूमिल पड़ता जा रहा है। आज, जबकि चीन का संकट टला नहीं है और पाकिस्तान से किसी भी क्षण संघर्ष की आशंका बढ़ रही है, नई दिल्ली में यह जो राजनैतिक अस्थिरता और अविश्वास का वातावरण चल रहा है, उसको दूर करना चाहिये। एक उपप्रधान मंत्री की हमें आवश्यकता है। वह कौन हो यह तय करना कांग्रेस पार्टी का काम है। लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष को लम्बा चला कर, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिये।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्र के सामने जो संकट है उनका उल्लेख तो किया गया है, किन्तु उस पर विजय कैसे प्राप्त की जायगी, इस सम्बन्ध में कोई मार्ग निर्देश नहीं किया गया है। चीन के संकट की चर्चा की गई है। लेकिन चीन के प्रति हमारी नीति क्या है, हम कोलम्बो प्रस्तावों से कब तक बंधे रहेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया। कोलम्बो प्रस्ताव हमें छूट देते हैं कि हम अपनी सेनाएं नेफा में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक भेजें, मगर अभी तक सेनाएं भेजी नहीं गई हैं। इस सम्बन्ध

में श्रीमती भण्डारनायक के पत्र को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसने और भी आशंकाएं पैदा हो गई हैं। क्या सरकार ने श्रीमती भण्डारनायक को यह आश्वासन दिया है कि भारत की सेनाएं मेकमहन रेखा तक नहीं जाएंगी? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। यह भी बताया जाना चाहिये कि हम अपनी सेनाएं कब वहां भेजेंगे। कहा जाता है कि रक्षा प्रयत्न प्रचलना के साथ चल रहे हैं, देश को तैयार किया जा रहा है। दो वर्षों में हमने देश को कितना तैयार किया है इसकी कसौटी यह है कि नेफा में हम अपनी सेनाएं कब भेजते हैं। जब नेफा में हमारी सेनाएं थीं तब हम चीन के आक्रमण का सफलता के साथ प्रतिकार नहीं कर सके। बरफ पिघल रहा है, बसन्त की ऋतु आ गई है, कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि चीन फिर सीमा पर गड़बड़ नहीं करेगा। इस स्थिति में नेफा में हमारी सेना का सीमा तक जाना बहुत आवश्यक है; कोलम्बो प्रस्ताव भी हमें इस बात की अनुमति देते हैं। फिर हम अपनी सेनाएं क्यों नहीं भेज रहे हैं?

चीन ने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये। हम कब तक उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करते रहेंगे? यद्यपि कोलम्बो प्रस्तावों में चीन की सेनाओं द्वारा लद्दाख के क्षेत्र को खाली करने का कोई विधान नहीं है और यह घोषणा करते हुए भी कि हम आक्रामक को उसके आक्रमण के फलों का उपभोग नहीं करने देंगे; सरकार ने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लिये। मैं समझता हूं कि वह कोलम्बो देशों के लिये एक कन्सेशन था। लेकिन कोलम्बो देश चीन से अपने प्रस्ताव को मनवा नहीं सके। अब हमें वह कन्सेशन वापस ले लेना चाहिये। हमें स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये कि जब तक चीन की सेनाएं लद्दाख के क्षेत्र को भी खाली नहीं कर देंगी तब तक हम चीन से किसी भी तरह की वार्ता नहीं करेंगे। कोलम्बो देशों से भी हमें कहना चाहिये कि वे चीन को मनाने में व्यर्थ अपना समय नष्ट नहीं करें।

उन्हें भारत के न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करना चाहिये। अभी मोरक्को और ट्यूनिशिया में सीमा सम्बन्धी विवाद हुआ था यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के प्रेसिडेंट नासिर उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते थे। मगर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को हल करने की उनकी इच्छा ने उन्हें मोरक्को को आक्रामक कहने से नहीं रोका। भारत और चीन के विवाद को कोलम्बो देश शांति से सुलझाना चाहते हैं। विवादों को शांति से सुलझाना चाहिये यह भावना मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर आक्रमण के प्रश्न पर तटस्थता में विश्वास करने वाले देश चुप रहेंगे तो तटस्थता के साथ जो नैतिक बल है वह खत्म हो जायेगा और गुटनिरपेक्षता एक अवसरवाद के रूप में जनता के सामने आयेगी।

आज सारे देश का और सदन का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं की ओर लगा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह कहने के अलावा कि उन्हें बसाया जायेगा, और किसी नीति का दिग्दर्शन नहीं किया गया है। जब देश का विभाजन हुआ था तो हमने पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं को आश्वासन दिया था कि उनके जान, माल और इज्जत की रक्षा के प्रति हम कभी उदासीन नहीं रहेंगे। उन आश्वासनों को अमल में लाने का अवसर आया है। १९५० में जब पूर्वी पाकिस्तान में दंगे हुए, तब स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया था और भविष्यवाणी की थी कि नेहरू लयाकत अली पैक्ट पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं की रक्षा नहीं कर सकेगा। आज उनकी भविष्यवाणी सच हो गई है। मगर आज केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में पश्चिमी बंगाल का ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो कुर्सी को लात मार कर, सरकार को अपनी नीति बदलने को विवश करे। आज केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सरदार पटेल की तरह का भी कोई मंत्री नहीं है जो कहे कि अगर पाकिस्तान अपने पूर्वी भाग में हिन्दुओं की रक्षा नहीं करेगा तो उन हिन्दुओं को बसाने के लिये पाकिस्तान

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

को जमीन देनी पड़ेगी। हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू जी ने भी उस समय घोषणा की थी कि अगर पाकिस्तान सीधी तरह से नहीं मानेगा तो और रास्ते अपनाए जायेंगे—**अदर नेथड्स विल बी अडाप्टड**। आज तो प्रधान मन्त्री जी यह घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं। मगर पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं का क्या होगा? उनके सामने इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि वे मर जायें या जबरदस्ती अपना धर्म छोड़ दें, या बेघरबार बन कर भारत माता की गोद में चले आएँ। मगर उनके आने के लिये भी दरवाजे नहीं खोले गए हैं—हफ्ते में दो दिन उन्हें आने के सर्टिफिकेट दिये जायेंगे, बाकी पांच दिन नहीं। राजशाही का हमारा कार्यालय बन्द कर दिया गया। क्या आने वाले शरणार्थी अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिये ढाका जायेंगे? कौन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा? जो हिन्दू भारत में आना चाहते हैं उनकी रक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है, आने वालों पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं। कल रात मुझे त्रिपुरा से एक तार मिला है। मैं आपकी अनुमति से उसको पढ़ना चाहता हूँ :

"One lakh refugees crossed in continuous influx of thousands daily. On sixth evening just on the borders Pakistani police fired on four thousand fleeing refugees from three sides. Hundreds shot dead. Many injured in hospitals. Thousands in Pakistan are stranded and being tortured."

नेहरू लियाकत समझौते के अन्तर्गत उन्हें भारत तक सुरक्षित लाने की व्यवस्था की गई थी। अगर पाकिस्तानी उस समझौते का पालन करने के लिये तैयार नहीं है, तो जो हिन्दू आना चाहते हैं उन्हें भारत तक सुरक्षित लाने के लिये हमें फौज भेजने के लिये भी तैयार रहना चाहिये। हम उन हिन्दुओं को पाकिस्तान में मरने के लिये नहीं छोड़ सकते।

श्री टी० टी० कृष्णामाचारी का यह कहना ठीक नहीं है कि उनके प्रति हमारा केवल नैतिक दायित्व है और कोई संवैधानिक, कानूनी दायित्व नहीं है। हम उनको दिये गये आश्वासनों के साथ बंधे हुए हैं। वे आश्वासन राजनैतिक हैं, वे आश्वासन ऐतिहासिक हैं। देश का बटवारा इसी आधार पर हुआ था कि दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय किया जायगा। हमने उस आश्वासन का पालन किया है, पाकिस्तान ने उस आश्वासन का पालन नहीं किया। एक दृष्टि से पाकिस्तान के कायम रहने का सारा आधार ही खतम हो गया है।

हमने अपने देश में पवित्र अग्नि को लेकर आए हुए पारसियों को आश्रय दिया। तिब्बत से आये हुए बेघरबार बंधु हमारे देश में रहते हैं। क्या पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं के लिये हमारे हृदय में उतनी भी मानवता नहीं है? उनके प्रति हम क्या करने जा रहे हैं? कहा जाता है, हम क्या कर सकते हैं? पहला काम तो हम यह कर सकते हैं कि जो भी आना चाहते हैं उन्हें आने दें और उनको बसाने की पूरी जिम्मेदारी लें। अभी तक, जो पहले के पुरषार्थी आये हुये हैं वे सियालदा की सड़कों पर पड़े हैं। उन्हें भी अभी बसाया नहीं जा सका। आवश्यकता हो तो केन्द्रीय वित्त मंत्री नए बजट में एक हिंद्मिलिटेशन लेवी लगा सकते हैं। सारा देश उन अभागे भाइयों को बसाने के लिये कुछ कर देने में संकोच नहीं करेगा।

लेकिन शासन का दृष्टिकोण इस संबंध में बदलना चाहिये। एक बड़ी चिन्ता की बात यह हुई कि पूर्वी पाकिस्तान के दंगों की प्रतिक्रिया कलकत्ते में हुई। कलकत्ते में भी जगड़े हुए ये जगड़े नहीं होने चाहिये और हमें पाकिस्तान की नकल नहीं करनी चाहिये। लेकिन अगर कलकत्ते की पुलिस और पाकिस्तानी तत्व जरा संयम से काम लेते तो कलकत्ते में रक्तपात रोका जा सकता था। कलकत्ते के दंगों का आरम्भ विद्यार्थियों के

एक जलूस से हुआ। जलूस शान्ति पूर्ण था और उस जलूस से पहले कलकत्ते में कोई उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन उस जलूस पर हमला किया गया उस पर सोडा वाटर की बोतलें फेंकी गईं तीन विद्यार्थियों को छुरा मार दिया गया और पुलिस ने तीन बन्धु एण्ड्रूज कालेज में घुस कर एक विद्यार्थी को गोली से मार डाला। इसके बाद ही दंगे की आग भड़की।

इस बात की जांच होनी चाहिये कि कलकत्ते के उपद्रव में पाकिस्तानी तत्वों का कितना हाथ था? क्या यह सच है कि कलकत्ते में दंगे आरम्भ होने से पहले तरह-तरह की अफव हैं फैलाई गई थीं? क्या यह सच है कि पाकिस्तानी तत्वों ने अपने मकान और अपनी जायदाद का पहले से ही बीमा करा लिया था? क्या यह सच है कि जब दंगाग्रस्त क्षेत्र से कुछ मुसलमानों को एक ट्रक से हटाया जा रहा था तो उस ट्रक ने बम फेंका गया और एक बम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय के सामने फटा? बाद में उस ट्रक की पुलिस ने तलाशी ली तो बम बरामद नहीं हुए किन्तु जब ट्रक आगे चला तो उस में आग लग गई। यह सब कैसे हुआ? यह ऐसे तथ्य हैं जिन से जनता के मन में भ्रम पैदा होता है। उस भ्रम का निरकरण करना बहुत जरूरी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में जांच होनी चाहिये। कलकत्ते के उपद्रव के सम्बन्ध में यह धारणा पैदा होने देना कि जो कुछ किया वह सब हिन्दुओं ने किया और पाकिस्तान के साथ साठ गांठ करने वाले तत्वों ने कुछ नहीं किया, यह सच्चाई के खिलाफ होगा यह दुनिया में भारत को बदनाम करने के पाकिस्तानी जाल में फंसा होगा। कलकत्ते में जो कुछ हुआ वह लज्जाजनक है। हमारे देश में हर एक नागरिक के जीवन की, सम्मान की, रक्षा की जानी चाहिये। लेकिन एक बात साफ समझ ली जानी चाहिये कि अगर हम पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो भारत में साम्प्रदायिक शांति

बनाये रखना बहुत मुश्किल होगा। आखिर इस देश में इन्सान रहते हैं और उनके हृदय में भावना है। कलकत्ते की पुलिस में ऐसे लोग थे जिनके घरवाले पूर्वी पाकिस्तान में कत्ल कर दिये गये। हम उनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अपने कर्तव्य का दृढ़ता के साथ पालन कर सकेंगे। फिर भी हमें मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करना है। जितनी दृढ़ता के साथ कलकत्ते में उपद्रव दबा दिये गये, उतनी ही दृढ़ता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी कदम उठाया जाना चाहिये।

हमने इस प्रश्न पर विश्व के जनमत को प्रशिक्षित तथा जागृत करने के लिये कोई बात नहीं की। पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं पर पर्दा डालने के लिये पाकिस्तान ने काश्मीर का सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं का जो तरस-हार हो रहा है, उसकी ओर हमने किसी विश्व संगठन का ध्यान नहीं खींचा।

भारत में जो पाकिस्तानी रहते हैं जिनकी संख्या का हमें पता है। हम क्यों नहीं उनसे भारत छोड़कर जाने के लिये कहते? अ साम में पाकिस्तानी अवैध रूप से घुस रहे हैं और घुस आए हैं उनका निकालने में हमने कर्मा कर दी है, क्योंकि इस से पूर्वी पाकिस्तान में दंगे हो जायेंगे। दंगे तो पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे हैं फिर भी हम आसाम से पाकिस्तानियों को निकालने में ढिलाई कर रहे हैं। ८ से १० लाख तक पाकिस्तानी आसाम में बसे हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में उनकी संख्या ४ लाख है। सारे देश में सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार ५० लाख पाकिस्तानी रह रहे हैं। उन से कहा जा सकता है कि वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जायें। जो भारत के नागरिक हैं, मजहब के आधार पर उनके साथ भेद भाव नहीं होना चाहिये। मगर पाकिस्तानियों को दो देशों की नागरिकता का उपभोग करने की छुट नहीं देनी चाहिये। पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव डालना चाहिये। हमें शिलांग

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

में पाकिस्तान के कार्यालय को बंद कर देना चाहिये, हमें बेरुबाड़ी के समझौते को तोड़ देना चाहिये। हमें पाकिस्तान से कह देना चाहिये कि अगर पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं के साथ न्याय नहीं करेगा तो भारत की शक्ति में जो भी कदम होगा वह उठायेगा।

गैर सरकारी तौर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के कुछ नेताओं को पूर्वी पाकिस्तान जाना चाहिये। कठिनाई यह है कि यह सरकार न तो सरदार पटेल की भाषा में बात कर सकती है और न यह सरकार गांधी जी के कदमों पर ही चल सकती है। शांति और अहिंसा का उपदेश देने वाले क्यों नहीं ढाका और खुलना जाते और वहाँ के हिन्दुओं की स्थिति देखते? प्रोफेसर हुमायून कबिर जा सकते हैं, जनरल शाहनवाज खाँ जा सकते हैं, हमारे श्री फखरुद्दीन अहमद जा सकते हैं और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों से कह सकते हैं कि अगर तुम पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं के साथ न्याय नहीं करोगे तो हम भारत में मुसलमानों के साथ न्याय की भाग कैसे कर सकते हैं? मगर गांधी जी का नाम लेने वाले गांधी जी के कदमों पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। पूर्वी पाकिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है? क्यों नहीं डा० सुशीला नायर वहाँ जातीं, क्यों नहीं गवर्नर पद्मजा नायडू जातीं? श्रीमती इंदिरा गांधी भी थोड़ा समय निकाल कर वहाँ जा सकती हैं।

SHRI JOSEPH MATHEN (Kerala):
Why don't you go there?

श्री ए० बी० वाजपेयी : मैं जाने के लिये तैयार हूँ, अगर कोई चलने को तैयार हो। मगर हमारे जनरल सेक्रेटरी को तो पश्चिमी बंगाल से ही निकाल दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान में कौन जाने देगा। हम गैर सरकारी आचार पर इस बात का प्रयत्न करें

और इस समस्या को सुलझाने के लिये गम्भीरता से आगे बढ़ें।

उपसभाध्यक्ष जी, पूर्वी पाकिस्तान के दंगों को काश्मीर के साथ जोड़ा गया। काश्मीर की जनता के साथ नई दिल्ली न्याय नहीं कर रही है। काफी वर्षों के बाद काश्मीर से मिला जूली आवाज उठी कि केन्द्रीय सरकार को वहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम काश्मीर की जनता के साथ बेइन्तफाई करेंगे। काश्मीर की वर्तमान सरकार वहाँ की जनता का विश्वास खो चुकी है। अब मौका है फ़ेडरल सरकार को हस्तक्षेप करने का। जो सरकारी अफसर हमने भेजे थे, एक को जम्मू काश्मीर का ज्वइन्ट सेक्रेटरी बनाकर भेजना चाहते थे और एक को इन्फार्मेशन डायरेक्टर, बना कर। जब वे श्रीनगर पहुंचे तो उन से कहा गया कि किसी कागज को हाथ मत लगाना और वे अपना बोरिय बिस्तर बांध कर वापस आ गये। वहाँ पर केवल कुछ अफसरों को भेजने का सवाल नहीं है। जम्मू काश्मीर की जनता का जो विश्वास डिग गया है उसको फिर से जमाना होगा और इसके लिए कठोर कार्यवाही होनी चाहिये। मैं श्री तारिक के सुझाव का स्वागत करता हूँ कि संसद् के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू काश्मीर जाये और जम्मू काश्मीर की स्थिति का अध्ययन करे। संसद् को भी एक विशेष समिति नियुक्त करनी चाहिये और इस बात की जांच करनी चाहिये कि ऋण के रूप में, अनुदान के रूप में, जम्मू काश्मीर राज्य को अब तक जो धनराशि दी गई है वह किस तरह से खर्च की गई। पी० ए० सी० और इस्टीमेट कमेटी यह काम नहीं कर सकती। इस के लिये संसद् की एक विशेष समिति नियुक्त होनी चाहिये।

भारत की जनता को सुरक्षा परिषद् में ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जिस तरह से भाषण दिया बड़ा धक्का लगा है।

चीन के आक्रमण के समय ब्रिटेन जिस तरह से हमारी सैनिक सहायता पर आया और उससे जो सद्भावना हुई थी, मित्रता के जो बंधन दृढ़ हुये थे, उन्हें वर्तमान रवैये से गहरा घक्का लगा है। पाकिस्तान और भारत दोनों राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और ब्रिटेन राष्ट्रमंडल का प्रमुख है। दो राष्ट्रमंडलीय देशों के झगड़े में ब्रिटेन को तटस्थता की नीति अपनानी चाहिये। वह पाकिस्तान को आक्रमणकारी भी नहीं कहता। वह बदली हुई परिस्थिति को स्वीकार करने से इन्कार करता है। वह पूर्वी पाकिस्तान के दंगों के लिये भी पाकिस्तान को दोष देना नहीं चाहता। ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों के लिये बहुत बुरा काम किया है। यदि यह रवैया जारी रहा तो भारत में यह आवाज उठेगी कि हमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अपने सम्बन्ध तोड़ने चाहिये। काश्मीर हमारे लिये राजनीतिक की शतरंज का मोहरा नहीं है। यह हमारे लिये शीत युद्ध का एक अंग भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ब्रिटेन की वर्तमान सरकार फूट डालें और राज्य करो की साम्राज्यवादी नीति से अभी तक अपने को पूरी तरह अलग नहीं कर सकी है। भारत की जनता, अमेरिका के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद् में क्या कहते हैं, इस बात की प्रतीक्षा कर रही है।

हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से झगड़ा न बढ़े। देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पाकिस्तान से लड़ाई चाहती है। श्री देवकीनन्दन नारायण यहां नहीं हैं। कल उन्होंने श्री गोलवलकर का नाम लिया और कहने लगे कि वे अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत की बात तो मैं भी करता हूं। अखंड भारत की बात करना कोई जुर्म नहीं है। मैं सपना देखता हूं कि भारत और पाकिस्तान कभी एक होंगे। अगर जर्मनी के एक होने का सपना देखा

जा सकता है; अगर कोरिया और वियतनाम के एक होने का सपना देखा जा सकता है, तो भारत के एक होने का सपना क्यों नहीं देखा जा सकता। मगर यह सपना जोर और जबरदस्ती से पूरा नहीं होगा। इस सपने को पूरा करने के लिये फौज काम में नहीं लाई जायेगी। यह लड़ाई के जरिये प्राप्त नहीं किया जायेगा। यह हृदय परिवर्तन से प्राप्त होगा। पाकिस्तान की जनता जब चाहेगी तभी यह सपना पूरा होगा। उन्हें किसी के भाषण को संदर्भ से तोड़ कर, मरोड़ कर, सदन में पेश नहीं करना चाहिये। मैं वह समय देखता हूं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वीला महासंध और रक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से और विदेश सम्बन्धों की दृष्टि से हम निकट आ जायें। आज तो यह सपना ही है मगर यथार्थ कितना भी कटु हो हम सपना देखना तो नहीं छोड़ सकते। जो "जय जगत" का नारा लगाते हैं वही अखंड भारत के सपने पर आपत्ति करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ सकता। लेकिन जब तक पाकिस्तान अलग है, हमें पाकिस्तान के प्रति दृढ़ नीति अपनानी होगी। कमजोर नीति को उदारता नहीं समझा जाता। उस के गलत अर्थ लगाये जाते हैं। जब हम चीन से संघर्ष में फंसे हैं, हम पाकिस्तान से झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते। मगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो तीन महीने में पाकिस्तान से सम्बन्ध और भी बिगड़ेंगे और उस समय हमें सतर्क रहना होगा, देश के भीतर काम करने वाले पाकिस्तानी तत्वों पर नज़र रखनी होगी और कम्युनिस्ट पार्टी के उस हिस्से पर भी नज़र रखनी होगी जो चीनपरस्त है और चीनपरस्त होने के कारण आज पाकिस्तानपरस्त हो रहा है।

मुझे खेद है कि कलकत्ता के दंगों के संबंध में जो बातें कही गई हैं वह एकतरफा हैं और एकतरफा बातें यह बताती हैं कि हम ऐसा प्रचार करना चाहते हैं जो प्रचार

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

न तो सत्य पर आधारित है और न राष्ट्र के हितों के लिये काम में आ सकता है। ऐसे प्रचार से हमको सावधान रहना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कह कर खत्म कर दूंगा। अभी गृह मंत्री जी ने घोषणा की है, आज प्रश्नोत्तर काल में भी उसकी चर्चा हुई थी कि दो साल के भीतर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जायेगा। मैं नहीं जानता कि किन ज्योतिषियों से विचार विमर्श कर के, किस पंचांग को देख कर के उन्होंने दो साल का समय निर्धारित किया है। यह समय डेढ़ साल क्यों नहीं हो सकता? यह समय तीन साल क्यों नहीं हो सकता? भ्रष्टाचार का निराकरण आवश्यक है, लेकिन इस समय जो नाटकीय कदम उठाये जा रहे हैं, वे भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते। दिल्ली में हमने एक नाटक देखा। कसमें खिलाई गईं। रामलीला मैदान में हरिजन बन्धुओं को इकट्ठा किया गया, झाड़ू लगाने वालों को, और प्रधान मंत्री जी को वहां ले जाया गया, और उन हरिजन बन्धुओं को कसम खिलाई गई कि वे रिश्वत नहीं लेगे। हरिजन बन्धु कितनी रिश्वत लेते हैं? और क्या रिश्वत इसलिये ली जाती है कि लेने वालों ने कसम नहीं खाई है? क्या कसम खाने के बाद वे रिश्वत नहीं खाएंगे? अभी दिल्ली में एक घटना हुई है। एक ठेकेदार थे। वे कहीं अपना गलत काम करने के लिये रिश्वत देने लगे। जिन अफसर को रिश्वत लेनी थी उन्होंने कहा कि मैं तो रिश्वत नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने कसम खाई है। फिर थोड़ी देर में वे बोले कि मेरी पत्नी ने कसम नहीं खाई है। तो क्या पत्नियों के साथ पत्नियों को भी कसमें खिलाई जायेंगी? क्या गाठ बांध कर वेदी पर बैठ कर शपथ ली जायगी? और अगर पत्नियों को कसमें खिना दी गई तो बच्चे तो बच ही जायेंगे और फिर उन के नाम पर रिश्वतें ली जायगी। मुझे एक

और आशका है कि जब तक लोगों ने कसमें नहीं खाईं थी तब तक दो चार रुपये में काम हो जाता था। अब कोई दो चार रुपये में काम करने वाला नहीं है क्योंकि दो चार रुपये अगर कोई देगा तो वे कहेंगे कि हमने कसम खाई है। भला दो चार रुपये के लिये कसम क्यों तोंडें? अगर सौ पचास रुपये दे तो कसम तोंड भी सकते हैं। इस तरह रिश्वत के साथ कसम की कीमत भी मिल जायेगी और देने वाले को यह बड़ा महंगा पड़ेगा। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार को मिटाने का यह तरीका नहीं है। भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो ऊचे क्षेत्रों में शुद्धाचरण आदर्श रखा जाना चाहिये। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे बड़ लोग आचरण करते हैं, बाकी लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। कोई यह नहीं कह सकता है कि मंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है। उसकी जाच कैसे होगी? आंध्र के मुख्य मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, मगर पंजाब के मुख्य मंत्री चिपके हुये हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान आंध्र में ही होना चाहिये, पंजाब में नहीं होना चाहिये? पंजाब के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया?

पंजाब के गृह मंत्री ने विरोधी दल पर आरोप लगाया कि वे विरोधी शक्तियों के साथ साजिश कर रहे हैं। जब मैंने सदन में कहा कि अगर यह आरोप साबित नहीं किया गया तो मैं भूख हड़ताल करूंगा तो वे पलट गये और कहने लगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था तो दूसरे दिन उसका खडन कर सकते थे। यदि विदेशी शक्तियों के साथ साजिश करने का आरोप लगाया जाता है तो फिर उसे साबित किया जाये और अगर साबित न किया जाये तो कम से कम उसका खडन करके उसको खत्म किया जाये। मगर पंजाब के गृह मंत्री यह भी नहीं कर सकते।

दास कमिशन के सामने—मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि जांच हो रही है—जो तथ्य आ रहे हैं वे बड़े गंभीर हैं। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों को अगर आश्रय देगी, तो विजिलेंस कमिशन की घोषणाएँ भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकतीं। आवश्यकता इस बात की है कि जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी जांच की जाय, खुली जांच की जाय और जांच के दौरान में वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर जांच में वे निर्दोष साबित हो जाय तो अपने पद पर सनमान वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के निराकरण का मतलब यह है कि छोटी-छोटी मछलियों को फांसा जाय और बड़े-बड़े मगरमच्छ जाल में से निकल जाय तो जनता में विश्वास पैदा नहीं हो सकता।

दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि दिल्ली में जो एक कोआपरेटिव स्टोर चलता है, जिसने गुड़ में मुताफाखोरी की थी और जिस कोआपरेटिव स्टोर के संचालक एक बड़े कांग्रेस के नेता हैं, जिनके विरुद्ध जांच हो रही है। उस जांच का परिणाम क्या होगा? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाने वाली है? यह एक मामला है जो सब के सामने है। यह कसौटी है कि उस पर गृह-मंत्रालय क्या करता है। गृह मंत्रालय कठोर कार्यवाही कर सकता है। भ्रष्टाचार के निराकरण का प्रश्न किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, सब के सहयोग से देश में ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन और हमारा शासन शुद्ध हो, भ्रष्टाचार से रहित हो। मगर इसका प्रारम्भ केन्द्र से होना चाहिये, नई दिल्ली से होना चाहिये। लेकिन नई दिल्ली में आज नया कदम उठाने को, दृढ़तापूर्ण कदम उठाने की स्थिति नहीं दिखाई देती—यह स्थिति

बदनी जानी चाहिये, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

شمري پور محمد خان (جموں ایڈٹ)
کشمیر): وائس چھرمہن صاحب
مہن پریڈیڈنٹ صاحب کے ایڈریس
پر جو ووٹ آف تھیلکس کا مومن
آیا ہے اس کا سموتھن کرنے کے لئے کہوا
ہوا ہوں۔ مہن زیادہ تر کشمیر کے
متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا
لیکن پہلے چائلا کے متعلق بھی تھوڑا
کہنا چاہتا ہوں۔ چائلا کے متعلق
ایک پالیسی ہی کام آئے گی کہ ہم
اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنا
علاقہ واپس لیں۔ پاکستان کے متعلق
جو کچھ سیکورٹی کونسل میں ہو
رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اور
سیکورٹی کونسل میں جو کچھ پہلے
ہو چکا ہے اس کو دیکھنا میں دیکھنے
کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں
آئندہ یہ کرنا چاہئے کہ اگر پاکستان
پھر سیکورٹی کونسل میں جائے تو
ہم اس شرط پر ہی وہاں جائیں کہ
وہ ایکویشن ویکٹ کر دے اور جب
تک وہ ایکویشن ویکٹ نہ کرے تب
تک ہمیں ایسی مہنگوں میں
شامل نہیں ہونا چاہئے۔

اب میں کشمیر کے متعلق کہنا
چاہتا ہوں۔ کشمیر میں تازہ واقعہ
موتے مقدس کی چوڑی کا جو ہوا وہ
کچھ اس طرح ہوا کہ اس سے دو دن
پہلے غالباً ۲۴ دسمبر کو کشمیر میں

[شری پھر محمد خان]

جو کہ جموں سے ۱۶۰ میل نارتھ ویسٹ کی طرف ایک جگہ ہے وہاں ایک زیارت گو آگ لگائی گئی اس کے تھک دو دن کے بعد یہ موئے مقدس کی چوری سری نگر حضرت بل میں ہوئی اور پھر اس کے عین دو دن کے بعد جموں میں ایک ملدر سے دو سو تھان نکالی گئیں۔

شری اے۔ ایم۔ طارق : وائس

چھرمون صاحب - میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہے - یہ غلط ہے -

شری پھر محمد خان : آپ مہر

وقت ضائع نہ کیجئے - مجھے کہہ دیجئے -

SHRI A. M. TARIQ: I rise on a point of order.

کشت وار میں کسی زیارت میں آگ نہیں لگائی گئی - یہ غلط ہے -

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : तारिक साहब, आप बोल चुके हैं, उनको बोलने दीजिये ।

SHRI A. M. TARIQ: He is giving wrong information.

SHRI B. D. KHOBARAGADE (Maharashtra): Congress people should not fight amongst themselves.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI (Punjab): How can he say that he is giving wrong information?

شری پھر محمد خان : اس کے

بعد وہاں تحقیقات وغیرہ شروع ہوئی۔ اب تک وہاں وہ الہمدت جو پور پاکستانی تھا اور کچھ قسمریٹلڈ الہمدت تھا انہوں نے مل کر ایک ایکشن کمیٹی جیت پت بمالی - ان کو ایک موقع ملا اور اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھانا چاہا - کس کے خلاف - انڈیا کے خلاف - کشمیر کے خلاف تو کہا ہوتا تھا - انڈیا کے خلاف فائدہ اٹھانا چاہا - اس ایکشن کمیٹی کے ۱۲ یا ۱۳ ممبر ہوں اور اس میں سبجارتی ان ممبرس کی ہے جو کہ ممبر واعظ فہلسی کے ہوں - ممبر واعظ وہ شخص ہوں جو کہ پاکستان میں ہوں - مسام کانفرنس کے ۱۹۴۷ء سے پہلے پریذیڈنٹ تھے اور وہ پاکستان کے ساتھ ریاست کا الحاق چاہتے تھے - اس کے علاوہ مولوی مسعودی صاحب اس کے جفرال سمعریتری اور کرتا دھرتا ہیں - اس کے علاوہ کچھ پلیٹیفیسٹ فرنٹ اور پولیٹیکل کانفرنس کے آدمی ہیں جو کہ سب پور پاکستانی ہیں - مولوی مسعودی صاحب وہ ہیں جو کہ شیخ عبدالہ صاحب کے عم خمال ہیں اور ۱۱ تاریخ کی سمعریتری کونسل کی قیادت میں چھانڈ صاحب نے بالکل صاف شہد میں کہا ہے کہ مسعودی ایمپیشن گروپ کا آدمی ہے تو یہ ایک ایکشن کمیٹی بنی اور

انہوں نے لوگوں میں یہ بات پھیلانی کہ یہ سب کچھ بخشی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کرایا ہے۔ بھیج بھیج میں یہ ہوا پھیلی۔ ایک مسلمان کے حلقہ میں اس کو آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیز کا جب نقصان ہو برے فائدہ آپ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس وقت ان کلہور لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا اور جو پت ایک دھار بخشی صاحب کی طرف موڑ دی۔ اس میں تھیلی تھیلی تھار کی۔ لوگ اکٹھے ہوئے، جلسہ جلوس ہوا، بڑا رونا پھٹنا ہوا۔ اس کی کشیدگی ہو۔ تو اس کی دھارا اس طرح پھیر دی اور اس طرح پھرنے پر کہا ہوا۔ لال چوک میں --- بہت سے صاحبان نے وہ جگہ دیکھی ہوگی وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے۔ ان میں جب یہ بات پھیل گئی تو لال چوک کے قریب بخشی صاحب نے رشتہ داروں کی جو کچھ عمارتیں تھیں ان کو آگ لگانی گئی۔ ان کو چھوڑ دیجئے وہ تو ایک پرائیویٹ پرائیویٹ تھی پھر ان کو اکسایا گیا اور انہوں نے پھر پولیس تھانہ پر حملہ کر کے اس کو جلا دیا۔ ہوم منسٹر صاحب نے اچھے بہانے میں جو کہ کل انہوں نے دیا ہے صاف بتایا ہے کہ فائرنگ تھانہ جلاتے وقت ہوئی اور اس وقت ہوئی جب کہ پولیس پر باہر ایسالت ہونا شروع ہو گیا۔

فائرنگ تب ہوئی۔ اس طرح فائرنگ نہیں ہوئی کہ ایک آدمی کہتا تھا کہ مجھے انصاف دو اور آگے سے اسے پکڑ کر گولی مار دی۔ یہ بات نہیں تھی۔ فائرنگ اس وقت ہوئی جب کہ ایک تو تھانہ جلا رہے تھے اور دوسرے اس وقت جس وقت کہ پولیس پر حملہ شروع ہو گیا تھا۔ تو سہل قہقہے میں فائرنگ ہوئی۔

خیر یہ چیز ہوئی۔ اب گورنمنٹ آف انڈیا نے اسٹیمٹ کی ہندوئی ہونے کی وجہ سے جو کہ اس کو کرنا چاہیئے تھا کچھ بہانے سے امداد بھیجی۔ انٹیلیجنس برانچ کے کچھ آفیسرس اور ہوم سیکریٹری وہاں گئے۔ تو انٹیلیجنس برانچ نے موئے مقدس کو قہرندعلی میں حصہ لیا اور اس کی تصدیقات میں حصہ لیا۔ اس تصدیقات کے متعلق ایک دو بہانے ہوم سیکریٹری نے دیئے تو اس کلہور گروپ نے لوگوں میں کہا یہ وہی ہے کہ اسٹیمٹ گورنمنٹ معطل ہو گئی ہے اور اب انڈیا گورنمنٹ نے سارا کچھ انتظام ہاتھ میں لے لیا ہے اس طرح کچھ اور فضا خراب ہوئی۔ خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک چیز کم ہوئی ہے اور پاکستان ریڈیو میں اور وہاں کے بیانی میں یہ بات

(شہری پور متحیدہ ضلع)

آئی ہے کہ ایک ہندو نے چرایا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کرایا ہے اور اس واسطے کرایا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نہیں دیا جائے وہاں رہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اس وقت وہاں ریاست میں معاشی میں ہے اس کے یہ ٹریڈیشن تھا نہشل کانفرنس کا یہ ٹریڈیشن تھا کہ کمیونل پارٹنر ہو اور سب کو اپنا بھائی سمجھیں اور یہی ٹریڈیشن نہشل کانفرنس کا رہا ہے جس کی وجہ سے ۱۹۴۷ء میں کشمیر واپس میں کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ اسی جماعت کی تھچنگ تھی اور وہی چوڑ اور وہی ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے۔ پاکستان بھتیہ کے اتلا اکسانے کے باوجود اور سب کچھ کرنے کے بعد وہاں کوئی کمیونل ٹھنشن نہیں ہوا اور موٹے مبارک کے کم ہونے کا نتیجہ اس کا افسوس، اگر ایک طرف مسلمان نے کیا تو دوسری طرف ہندو نے بھی کیا سکھ ہیں اور جو کوئی بھی وہاں ہیں سب نے کہا۔

اب بعضی صاحب کے خلاف بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بعضی فرشتہ ہے وہ بھی ایک انسان ہے۔ مگر یہ بعضی وہی ہے جس کو ۱۹۴۷ء میں میں ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں اور

چاہتا ہوں۔ جو اس کا اسٹینڈہ جو اس کا دلی لگاؤ انڈیا کے ساتھ اس وقت تھا وہی لگانا اس وقت تک ہے اور اس سے بڑے لوگوں میں وہ بات نہیں رہی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کشمیر اسمبلی سے ایکشن پر مہر لگوائی۔ آپ میں سے بہت حضرات نے جن میں اور کشمیر دیکھا ہوگا آپ دیکھئے وہاں کہا پروگریس ہوئی ہے اور جو پروگریس ہوئی ہے وہ بخشی ہی کے رجیم میں ہوئی ہے اور قاعدہ کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کی طبیعت ایک آدمی کو نہیں چاہتی تو اس کی اچھی باتیں کوئی نہیں دیکھتا البتہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو خراب ظاہر کیا جائے۔

پھر ایک بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے لوگ اب اس حکومت کو نہیں چاہتے کوئی وقتی چھوڑیں ایسی نہیں ہوتی ہوں کہ جس سے کچھ شک اب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس معاملہ میں ہوا۔ لوگوں کے کان پر دھنکے گئے کہ یہ سب کچھ بعضی نے کرایا۔ اور بعضی نے اور حکومت نے دونوں نے کرایا ہے کہوں کہ دونوں کو اپنی تباہی کرنی ہے۔ اس واسطے ان کی تہوڑی مخالفت بھی ہوئی۔ مگر میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا

دو مورتوں کی چوری ہوئی وہاں ان کی تحقیقات ہو رہی ہے - بد قسمتی سے وہ ابھی تک نہیں ملے۔ وہاں کہا ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں اس حکومت کو بدل دو - ہماری پرچا پریشد جنہو حد سنگھ کی ایک شاخ ہے کہتی - حکومت کو بدل دو، پریشد رول کو دو، یہ کہ دو، وہ کردو۔ پرچا پریشد عہد اللہ کے وقت بھی یہی چاہتی تھی کہ پریشد رول ہو اور حکومت ختم ہو - پرچا پریشد ہتھی صاحب کے وقت بھی یہی چاہتی تھی اور اس کا بھی نعرہ تھا - تہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہو کئی افسر یہاں سے گئے تو ادھر ادھر پبلک کو بتایا گیا کہ یہ تو سہیل گورنمنٹ رفتہ رفتہ اس گورنمنٹ کو معطل کر رہی ہے اور اب اس سے چارج لے لگی - آج اور کل کے نیوز کو دیکھو - ذمہ دار سرکاری آدمیوں کے یہاں بیانات اخبار میں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس گورنمنٹ نے یہ ریکورسٹ کی کہ ہم کو ایڈمنسٹریشن کو ذرا اور اچھا کرنے کے لئے قابل آدمیوں کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس بات کو تسلیم کیا اور آجہو آفسر کشمیر بھیجے اور شاید کچھ اور اسپر کرے گی تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ چیز یہ ہے - تھیک ہ نوئی شخص طبعی طور پر ایک چیز کی مخالفت

کرنا چاہتا ہے - اس کے واسطے راستے کھلے ہوئے ہیں - وہ ہر برے یا اچھے راستے سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے - مثلاً ابھی اتنی چیزیں بتائی گئیں کہ جسے کشمیر سے ہندوستان نے انصاف نہیں کیا - کہیں انصاف نہیں کیا؟ کیا کشمیری بھوکے مر رہے ہیں؟ ہندوستان مدد نہیں دیتا، کسی طرح کی سہولت نہیں دیتا، کسی بھی بات میں کوئی مدد نہیں کرتا، یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں - ہتھی صاحب کے متعلق ایک لطیفہ ہے --- یہاں تو ہوا ہی سیکورٹی کونسل میں بھی پاکستان کے ڈیپلگٹ نے کہا --- ہتھی صاحب کا کوئی بیان دینا کر کے کہا - کہ ہتھی صاحب بھی پلیمسٹ چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے اور وہ بیان جعلی طور پر جعلی دستخطوں سے جاری کیا گیا اور اس کے بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ہوم منسٹری کو اچھی طرح سے پتہ تھا - اور اس جعلی بیان کی بھاد پر کچھ دوستوں نے یہاں پر ہاتھ نہیں کیے ہیں اور کچھ دوستوں نے جموں سے بیان بھیجا - اس جعلی بیان کی بھاد پر جس کے بارے میں 11 تاریخ کی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں مسٹر چھانلا نے جعلی کہا - تو اس طرح کی چیزیں ہیں - بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ان کا جواب دینا بھی اخلاق کے خلاف سمجھتا ہوں - ہتھی صاحب اور ان کی فیملی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جائیداد اور پدسہ ہے - یہ ہوا الزام

[شری پدو محمد خان]
 لکایا جاتا ہے۔ دیکھئے۔ بخشی صاحب
 کی جو ذاتی جائیداد ہے اس کا حساب
 آپ دیے ہوں۔ اس کو پوچھ لیں۔
 بالکل رہی ان کی فہمی؟ وہ اگر
 بزنس کر کے چار پھسے کما رہی ہے تو
 ہمیں اور آپ کو کیا غرض۔
 وہ تاکہ مار کر نہیں لائے۔ کسی کا
 گھر لوٹ کر نہیں لائے۔
 شری اے۔ ایم۔ طارق: تو کھسے
 لائے؟

شری پدو محمد خان: اور پھر
 ایک الزام یہ لکایا گیا کہ بخشی نے
 پاکستان کو رکھا اور چند ایک
 افسروں کے نام لکھے۔ آپ انتہا میں
 دیکھیں۔ بہت سے آدمی ہیں
 جنہیں میں جانتا ہوں، جو یہاں
 ملازمت میں ہیں اور ان کے رشتہ دار
 پاکستان میں ہیں۔ تو مہر واعظ
 کے باپ کے مرنے پر بخشی نے چھٹی
 کر دی اور مہر واعظ کے باپ ایک
 ماٹے ہوئے بھلے اور ایمان دار آدمی تھے۔
 دیکھئے۔ مہر واعظ نے پپ بالکل
 پاکستانی نہیں تھے، بالکل سیدھے
 سادھے آدمی تھے۔ اور اگر ان کے
 مرنے کے بعد چھٹی بھی کر دی تو
 وہ تیزرو کرتے تھے یہ چیز۔ حالانکہ جو
 میں یہ کہتا ہوں کہ چھٹی کر دی تو
 یہ بھی سبجکٹ ٹو کلفورمیشن ہے۔
 یہ حکومت کی ننگا میں ہے۔ مگر
 وہ چھٹی کی بھی لگی تو ٹارگٹ ہے۔
 یہ بھی کہا گیا کہ دو تین سو آگ،
 کی بھی ہوئی ہوگی کانگریس بخشی

عبدالرشید کے سر پر ماری گئیں۔
 ذرا اندازہ کیجئے، آگ کی بھی
 ہوئی کانگریس ابھی ایک آدمی کو دو
 بھی مار کر دیکھ لیجئے، ایک کے
 بعد ہی کیا مثال ہوگا اس کو دیکھ
 لیجئے اندازے کے طور پر۔ یہ تو
 مدالغہ کی انتہا ہے اور لوگوں کے
 جذبات کو ابھارنے کے لئے یہ طریقہ
 اختیار کرنا کوئی اچھے بات نہیں
 ہے۔ اس کے علاوہ ایک کہانی گھڑی
 لگتی کہ ایک ایس۔ پی۔ نے، سرکاری
 ملازم نے ایک ہندو کو پستول سے مار
 دیا تاکہ ہندو مسلمان میں فسادات
 پیدا ہوں۔ تو آپ ان دونوں میں
 فرق دیکھئے کہ ایک جگہ تو کہا جائے
 کہ ایک ہندو نے موٹے مہارک چڑایا
 ہے اور دوسری جگہ یہ کہا جائے کہ
 ایک مسلمان ملازم نے ہندو کو مار ڈالا۔
 زمین آسمان کا فرق ہے۔

تو چیز یہ ہے کہ ایسی چیز کہہ دینے
 سے کیا فائدہ جس کا کوئی ثبوت نہیں
 ہے کہ ۳۰۰ آگ سے بھی کانگریس کی
 پرورش کسی آدمی پر چلی گئی۔
 جب یہ کسی آدمی کے سر پر لگتی
 ہیں تو وہ بیچ نہیں سکتا۔ ابھی
 ہمارے خلاف دو سائڈ ہیں۔ ایک تو
 قسطنطنیہ گروپ کے پانچ چھ آدمی
 ہیں جن کو کامیابی نہیں ہوئی۔
 پینچھ ابھی جو الیکشن ہوئے تھے لہذا
 آف دی ہاؤس کے اس میں ۱۰۰ کے
 مقابلہ میں انہوں نے ووٹ ملی۔

ہوں اے - اہم - طارق : آپ بھی

مہالہ سے کام لے رہے ہیں - ۷۵ ہیں

۱۰۰ نہیں ہیں -

شری پیر محمد خان : کسی

وجہ سے چھ ووٹ پانے والوں کو لہذا
آف دی ہاؤس تسلیم کیا جا سکتا
ہے - میں اس میں کونسل کے
ممبروں کو بھی شامل کرتا ہوں -
میں کہتا ہوں کہ اس گروپ کی
طرف سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے
کافی اسٹریٹجک مالیاتی ہے کشمیر
گورنمنٹ کے خلاف نو کلفیڈنس موشن
لایا ہے - تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ
ایک کلسٹی ٹیوشنل دے ہے - آپ تو
کلفیڈنس موشن اتنے اور جاری بات
ٹھیک ہو جائے گی - اگر وہ پاس ہو
جائے گا تو آپ کی اسٹریٹجک معلوم
ہو جائے گی - لیکن آپ تہمت تک
اس کو نہیں لا سکتے ہیں - جو
کچھ مرفی ہے آپ کہہ سکتے ہیں
اور وہ آپ کے لئے ٹھیک ہے - میں
پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک زندہ
شخص ۲۰۰ کانگریسوں کی آگ کی
بیوروں کے نتیجے آئے گا تو زندہ نہیں
رہ سکتا - آپ لوگ اور مولوی
مسعودی صاحب جو اس الیکشن کے
روح رواں ہیں اور نئی قیادت
پیش کرتے ہیں جن کی بڑی تعریف
ڈسٹرنگٹڈ گروپ میں کی جاتی ہے وہ
نئی نئی باتیں پیش کرتے ہیں -

(THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

ہم نے کشمیر میں حوالہ سکر
ہوسوں میں بہت کام کیا اور اس
کو آگے بڑھایا - لیکن مہر واعظ یوسف
صاحب اور چودھری غلام عباس کو
پاکستان سے واپس لیا جائے وہ مانگ
ہمارے مولانا مسعودی صاحب کرتے
ہیں تاکہ وہ لوگ راونڈ ٹیبل کانفرنس
میں بے شکور کشمیر کے معاملہ کا فیصلہ
کریں - کئی چھوٹی بات ہے
کہ جو لوگ اس طرح کی بات کیا
کرتے ہیں ان کے خلاف ابھی تک کچھ
نہیں کیا گیا - مولانا مسعودی صاحب
وہی شخص ہیں جنہوں نے ۱۹۴۷
میں اور ۱۹۴۸ء کے شروع میں چودھری
عباس کو جو جوں کی چھل میں
تھوکتے وہاں سے چھڑوا کر پاکستان
بھجوا دیا تھا - اب وہی کہہ رہے ہیں
کہ انہیں پاکستان سے واپس لیا
جائے - مہر واعظ محمد یوسف اور غلام
عباس یہ دونوں ریاست کی پاکستان
میں شمولیت کے حق میں تھے -
اس وقت غلام عباس فوجی تھادی
کر رہے ہیں آزان کشمیر میں تاکہ وہ
کشمیر کے اس حصہ پر جو کہ ہمارے
قبضہ میں ہے اس پر حملہ کر سکیں -
مولوی مسعودی صاحب - مہر واعظ
صاحب غلام عباس صاحب اور
شیخ عبداللہ صاحب بھی کہا کشمیر
کے معاملہ کا فیصلہ کر سکتے ہیں
یہ کئی مضحکہ خیز بات ہے - کر

[شری پیر محمد خان]

آپ ایکشن کمیٹی کے ممبران کو دیکھیں گے تو اس میں ۱۲ رہا تھوہ آدمی ہیں اور جس میں اکثریت مہر واعظ محمد یوسف کے رشتہ داروں کی ہے اور باقی آدمی بے پاکستانی پارٹیز کے ہیں جو مسلم یونیٹنگ کانفرنس اور پلیمس سائٹ فرنٹ کے ممبر ہیں۔ اس ایکشن کمیٹی میں ایک آدمی بھی نیشنل کانفرنس کا نہیں ہے۔ بخشی صاحب نے اس ایکشن کمیٹی کے کاموں کو چلے نہیں دیا اور حکومت میں ۱۹۳۷ء سے لے کر آج تک اس قسم کے الیمینٹس کو ابھرنے نہیں دیا۔ یہی ان کا تصور ہے جس کی وجہ سے انہیں ہڈنام کیا جا رہا ہے۔ اب ان کو مذاقاً اہلی آدمی کہہ رہے ہیں۔ یہی تھوڑے عرصہ پہلے صحیح طور پر اہلی آدمی تھے اور ان کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے۔ خوش قسمتی سے ہوم منسٹر صاحب نے ۱۲ تاریخ کو راجیو سبھا میں یہ بتایا کہ اس سونے مبارک کی چوڑی میں نیشنل کانفرنس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس میں ایک سے زیادہ آدمی ہیں اور ابھی ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں کچھ گرفتاری اور کرنی پڑے۔ لہذا صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ دو تین دن میں اصلی کلیپٹس کے نام بتاؤں گا اور اعتراض کنندگان کے متعلق معاملہ روشن ہو جائے گا کہ ان

پروپگنڈا کہاں تک صحیح ہے اور پھر یہی اہلی آدمی فولادی آدمی بن جائیں گے۔

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you have taken enough time. Please wind up.

شری پیر محمد خان: پہلے اسپیکر کو کافی ٹائم دیا گیا۔ اس لئے مجھے تھوڑا وقت اور ملنا چاہئے۔ تو میں کہہ رہا تھا۔

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken nearly half an hour.

شری پیر محمد خان: تو میں کہہ رہا تھا کہ اعتراض کرنے والے نہ ٹھہرائیں دو تین دن میں دودھ اور پانی الگ ہو جائے گا۔ اور مرد اہلی کی پوزیشن آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گی۔ پارلیمنٹ میں اس طرح سے توہین آمیز باتیں کرنا پارلیمنٹ کے رولس کے خلاف ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا بے جا ہے بچا نہیں۔ اس کے بعد میں روشن آف ٹھیکس کی تائید کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقعہ عطا کیا۔

شری ایم۔ این۔ انور (مدرس):

میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ اس بازگ دور میں بخشی غلام محمد اور عبدالرشید وہ کہاں تھے۔ اور وہ میدان چھوڑ کر کدوں چلے گئے۔

تو کہا مولانا مسعودی صاحب نے
ہی اس نازک سچویشن کو سلہلا
تھا ؟

شہر پور محمد خاں :

اجازت ہو تو میں ان کا جواب دے
دوں - میں نے جس وقت جواب دیا
تھا اس بات کا اس وقت انہوں نے
فالو نہیں کیا - میں نے کہا تھا
کہ لوگوں میں یہ بات پھیلانی گئی
اس ایکشن کمیٹی کی جس میں تقریباً
سہلٹ پرسنلٹ پرو پاکستانی الیمنٹ
شامل ہیں اور انہوں نے موقع کا
فائدہ اٹھایا ہے - انہوں نے لوگوں کے کان
پھونکا کہ یہ سب کچھ بخشی نے اور
نوشل کانفرنس نے کرایا ہے -

†[**श्री पीर मुहम्मद खान** (जम्मू और
काश्मीर): वाइस चैयरमैन साहब
में प्रेजिडेंट साहब के एड्रेस पर जो वोट
आफ थैंक्स का मोशन आया है इसका
समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।
मैं ज्यादातर काश्मीर के मुतल्लिक
अपने ख्यालात का इजहार करूंगा लेकिन
पहले चाइना के मुतल्लिक भी थोड़ा कहना
चाहता हूं। चाइना के मुतल्लिक एक
पालिसी ही काम आयेगी कि हम अपने
आपको मजबूत करें और अपना इलाका
वापस लें। पाकिस्तान के मुतल्लिक जो
कुछ सिक्यूरिटी कौंसिल में हो रहा है उसको
देखने के बाद और सिक्यूरिटी कौंसिल
में जो कुछ पहले हो चुका है उसको
ध्यान में रखने के बाद मेरा ख्याल है
कि हमें आइन्दा यह करना चाहिये कि अगर
पाकिस्तान फिर सिक्यूरिटी कौंसिल में
जाये तो हम इस शर्त पर ही वहां जायें
कि वह एप्रेशन वेकेट कर दे और जब

तक वह एप्रेशन वेकेट न करे तब तक हमें
ऐसी मीटिंगों में शामिल नहीं होना चाहिये।

अब मैं काश्मीर के मुतल्लिक कहना
चाहता हूं। काश्मीर में ताजा वाकया
मुए-मुकद्दस की चोरी का जो हुआ वह
कुछ इस तरह हुआ कि इससे दो दिन
पहले, गालिवन २४ दिसम्बर, को,
किश्तवाड़ में जो कि जम्मू से १५० मील
नार्थ वेस्ट की तरफ एक जगह है वहां एक
जयारत को आग लगाई गई, उसके ठीक
दो दिन के बाद यह मुए-मुकद्दस की चोरी
श्रीनगर हजरतबल में हुई और फिर
उसके एक दो दिन के बाद जम्मू में एक
मन्दिर से दो मस्जियां निकाली गई।

श्री ए० एम० तारिक : वाइस चैयरमैन
साहब। मैं आपकी तव्वजा इस तरफ
दिलाना चाहता हूं कि यह वाकया नहीं है,
यह गलत है।

श्री पीर मुहम्मद खान : आप मेरा
वक्त जाया न कीजिये। मुझे कहने दीजिये।

श्री ए० एम० तारिक : I rise on a
point of order. किश्तवाड़ में किसी
जयारत में आग नहीं लगाई गई यह
गलत है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद
भारगव)** : तारिक साहब, आप बोल चुके
हैं, उनको बोलने दीजिये।

SHRI A. M. TARIQ: He is giving wrong
information.

SHRI B. D. KHOBARAGADE (Maha-
rashtra) : Congress people should not fight
amongst themselves.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHA-
ZARI (Punjab): How can he say that he is
giving wrong information?

श्री पीर मुहम्मद खान : इसके बाद
वहां तहकीकात वगैरा शुरू हुई। अब
तक वहां वह एलीमेंट जो प्रो-पाकिस्तानी
† [] English translation.

[श्री पीर मुहम्मद खान]

था और कुछ डिस्पेन्टल्ड एलीमेन्ट था उन्होंने मिल कर एक एक्शन कमेटी स्टाप बना ली। उनको एक मौका मिला और उस मौके से उन्होंने फायदा उठाना चाहा। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ, काश्मीर के खिलाफ तो क्या होना था, इंडिया के खिलाफ फायदा उठाना चाहा। इस एक्शन कमेटी के १२-या १३ मेम्बर हैं और उसमें मेजोरिटी उन मेम्बरस की है जो कि मीर वाज फैमिली के हैं। मीर वाज वह शख्स है जो कि पाकिस्तान में हैं। मुस्लिम कांफ्रेंस के १९४७ ई० से पहले प्रेजिडेंट थे और वह पाकिस्तान के साथ रियासत का इलहाक चाहते थे। इसके अलावा मौलवी मसऊदी साहब इसके जनरल सेक्रेटरी और कर्त्ता धर्त्ता हैं। इसके अलावा कुछ प्लेबीसाइट फ्रंट और पोलिटिकल कांफ्रेंस के आदमी हैं जो कि सब प्रो-पाकिस्तानी हैं। मौलवी मसऊदी साहब वह हैं जो कि शेख अब्दुल्ला साहब के हम-खाल हैं और ११ तारीख की सिक्कूरिटी कौंसिल की डिबेट में छागला साहब ने बिल्कुल साफ शब्द में कहा है कि मसऊदी अपोजिशन ग्रुप का आदमी हैं। तो यह एक एक्शन कमेटी बनी और उन्होंने लोगों में यह बात फैलाई कि यह सब कुछ बख्शी साहब ने और उनके साथियों ने कराया है। बीच बीच में यह हवा फैली। एक मुसलमान के सेन्टीमेन्टस को आप जानते हैं कि ऐसी चीज का जब नुकसान हो बड़े फ्लेयर्ड-अप हो जाते हैं। एक तो उस वक्त उन क्लेवर लोगों ने यह फायदा उठाया और स्टापट एक धार बख्शी साहब की तरफ मोड़ दी। मास मेन्टैलिटी तैयार की। लोग इकट्ठे हुये, जलसा जलूस हुआ, बड़ा रोना पीटना हुआ, इसकी गुमशुदगी पर। तो इसकी धारा इस तरह फेरदी और इस तरह फेरने पर क्या हुआ? लाल चौक

में—बहुत से साहबान ने वह जगह देखी होगी वहां एक जलसा होता है। उनमें जब यह बात फैल गई तो लाल चौक के करीब बख्शी साहब के रिश्तेदारों की जो कुछ इमारतें थी उनको आग लगाई गई। उनको छोड़ दीजिये, वह तो एक प्राइवेट प्रापर्टी थी। फिर उनको उकसाया गया और उन्होंने फिर पुलिस थाना पर हमला करके उसको जला दिया। होम मिनिस्टर साहब ने अपने बयान में जो कि कल उन्होंने दिया साफ बताया है कि फाईरिंग थाना जलाते वक्त हुई और उस वक्त हुई जब कि पुलिस पर बाहर एसाल्ट होना शुरू होगया, फाईरिंग तब हुई, इस तरह फाईरिंग नहीं हुई कि एक आदमी कहता था कि मुझे इन्साफ दो और आगे से उसे पकड़ कर गोली मार दी, यह बात नहीं थी। फाईरिंग उस वक्त हुई जब कि एक तो थाना जला रहे थे और दूसरे उस वक्त जिस वक्त की पुलिस पर हमला शुरू हो गया था, तो सेल्फ डिफेंस में फाईरिंग हुई।

खैर यह चीज हुई। अब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट की हमदर्दी होने की वजह जो कि उसको करना चाहिये था कुछ यहां से इमदाद भेजी। इन्टेलीजन्स ब्रांच के कुछ आफिसर्स और होम सेक्रेटरी वहां गये। तो इन्टेलीजन्स ब्रांच ने मूए-मुकद्दस को ढूढ़ने में हिस्सा लिया और उसकी तहकीकात में हिस्सा लिया। इस तहकीकात के मुतल्लिक एक दो बयान होप सेक्रेटरी ने दिया तो इस क्लेवर ग्रुप ने लोगों में क्या फैला दिया कि स्टेट गवर्नमेंट मौअतल हो गई है और अब इंडिया गवर्नमेंट ने सारा इतजाम हाथ में ले लिया है। इस तरह से कुछ और फिजा खराब हुई। खैर अब देखना यह है कि एक चीज गुम हुई है और पाकिस्तान रेडियो में और वहां के लीडरों के बयान में यह बात आती है कि एक हिलू ने बुराया है, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह कराया है और इस वास्ते कराया है कि मुसलमानों को वहां से नेस्तोनाबुद कर दिया जाये

वर्गों, वर्गों। वह जमायत जो इस वक्त वहाँ रियासत में मेजोरटी में है उसका यह टरेडीशन था, नेशनल कॉफ़ेंस का यह टरेडीशन था कि कम्प्यूनल हार्मनी हो और सब को अपना भाई समझे और यही टरेडीशन नेशनल कॉफ़ेंस का रहा है जिसकी वजह से १९४७ ई० में काश्मीर वादी में कोई कम्प्यूनल रायट नहीं होने दिया गया। यह उसी जमायत की टीचिंग थी और वही चीज और वही टरेडीशन चला आ रहा है। पाकिस्तान रेडियो के इतना उकसाने के बावजूद और सब कुछ करने के बाद वहाँ कोई कम्प्यूनल टेन्शन नहीं हुआ। और मृण-मुबारक के गुम होने का रंज, इसका अफ़सोस, अगर एक तरफ़ मुसलमान ने किया तो दूसरी तरफ़ हिन्दू ने भी किया, सिक्ख ने भी किया और जो कोई भी वहाँ है सब ने किया।

अब बख़्शी साहब के खिलाफ़ बहुत सी बातें कहीं गई हैं। मैं यह नहीं कहता कि बख़्शी फ़रिस्त है, वह भी एक इंसान है। मगर यह बख़्शी वही है जिसको १९४७ ई० में मैं जाती तौर पर देख रहा हूँ और जानता हूँ। जो उसका स्टैंड, जो उसका दिल्ली लगाव इंडिया के साथ उस वक्त था वही लगातार इस वक्त तक है। और उससे बड़े लोगों में वह बात नहीं रही और मैं आपको यह बात बताऊँ कि यह वही शख्स है जिसने काश्मीर असम्बली से एक्सेशन पर मोहर लगावाई। आप में से बहुत हज़रत ने जम्मू और काश्मीर देखा होगा, आप देखिये वहाँ क्या प्रॉप्रेस हुई है और जो प्रॉप्रेस हुई है वह बख़्शी ही के रेजिम में हुई है और कायदे की बात है कि अगर एक आदमी की तबीयत एक आदमी को नहीं चाहती तो उसकी अच्छी बातें कोई नहीं देखता अलबत्ता यह कॉन्शस की जाती है कि उसको ख़राब जाहिर किया जाये।

फिर एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि कहा जाता है कि काश्मीर के लोग अब इस हुकूमत को नहीं चाहते। कोई वक्ता चीज़ ऐसी भी होता है कि जिससे कुछ शक़अप होता है। जैसा कि इस मामले में हुआ, लोगों

के कान भर दिये गये कि यह सब कुछ बख़्शी ने कराया और बख़्शी ने और हुकूमत ने, दोनों ने कराया है। क्योंकि दोनों को अपनी तबाही करना है। इस वास्ते उनकी थोड़ी मुखाफलत भी हुई। मगर मैं एक चीज़ अज करना चाहता हूँ कि अभी जम्मू में जहाँ कि दो मूर्तियों की चोरी हुई वहाँ इनकी तहकीकात हो रही है, बदकिस्मती से वह अभी तक नहीं मिली, वहाँ क्या हो रहा है कि कहते हैं इस हुकूमत को बदल दो, हमारा प्रज प रिषद् जो जनसंघ की एक शाख है कहती है हुकूमत को बदल दो, प्रेजीडेंट रूल कर दो, यह कर दो, वह कर दो। प्रजापरिषद अब्दुल्ला के वक्त भी यही चाहती थी कि प्रेजीडेंट रूल हो और हुकूमत ख़त्म हो। प्रजा परिषद बख़्शी साहब के वक्त भी यही चाहती थी और इसका यही नारा था। तो यह कोई नई चीज़ नहीं है। और फिर कई आफ़िसर्स यहाँ से गये तो इधर उधर पब्लिक को बताया गया कि यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट रफ़ता रफ़ता इस गवर्नमेंट को मुअत्तिल कर रही है और अब इससे चाज़ ले लेंगी। आज और कल के न्यूज़ को देखें। जिम्मेदार सरकारी आदमियों के यहाँ बयानात अख़बार में देखें, तो पता चलेगा कि इस गवर्नमेंट ने यह रिक्वेस्ट की कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रा और अच्छा करने के लिये काबिल आदमियों की ज़रूरत है और गवर्नमेंट अथ इंडिया ने इस बात का वैल्यू म किया और कुछ आफ़िसर्स काश्मीर भेजे और शायद कुछ और स्पेयर करेंगी। तो यह कोई ख़ास बात नहीं है। चीज़ यह है, ठीक है कोई शख्स तबई तौर पर एक चीज़ की मुखाफलत करना चाहता है उसके वास्ते रास्ते खुले हुए हैं वह हर बुरे या अच्छे रास्ते से करना चाहे तो कर सकता है। मसलन अभी इतनी चीज़ें बताई गईं जैसे काश्मीर से हिन्दुस्तान ने इन्साफ़ नहीं किया। क्या इन्साफ़ नहीं किया? क्या काश्मीरी भूखे मर रहे हैं? हिन्दुस्तान मदद नहीं देता? किसी तरह की सहाय्यत नहीं देता? किसी भी बात में कोई मदद नहीं करता, यह सब बातें कही जाती हैं। बख़्शी

[श्री पीर मुहम्मद खान]

साहब के मुतल्लिक एक लतीफा है—यहां तो हुआ ही, सिक्कूरिटी कौंसिल में भी पाकिस्तान के डेलीगेट ने कहा—बख्शी साहब का कोई बयान रेफर कर के कहा—कि बख्शी साहब भी प्लेबसाइट चाहते हैं, यह है, वह है। और वह बयान जाली तौर पर जाली दस्तखतों से जारी किया गया और उसके बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया की होम मिनिस्टरी को अच्छी तरह से पता है और इस जाली बयान की बुनियाद पर कुछ दोस्तों ने यहां पर बातें कहीं हैं और कुछ दोस्तों ने जम्मू से बयान भेजा। इसी जाली बयान की बुनियाद पर जिसके बारे में ११ तारीख की सिक्कूरिटी कौंसिल में मिस्टर छागला ने जाली कहा। तो इस तरह की चीजें हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि उनका जवाब देना भी अखलाक के खिलाफ समझता हूं। बख्शी साहब और उनकी फौमिली के मुतल्लिक कहा जाता है कि उनके पास जायदाद और पैसा है। यह बड़ा इल्जाम लगाया जाता है। देखिये बख्शी साहब की जो जाती जायदाद है उसका हिसाब आप देख लें, उसको पूछ लें, बाकी रही उनकी फौमिली वह अगर बिजनेस कर के चार पैसे कमा रही है तो हमें और आप को क्या गरज। वह डाका मार कर नहीं लाये। किसी का घर लूट कर नहीं लाये।

श्री ए० एम० तारिक : तो कैसे लाये ?

श्री पीर मुहम्मद खान : और फिर एक इल्जाम यह लगाया गया कि बख्शी ने पाकिस्तानियों को रखा और चन्द एक अफसरों के नाम गिने। आप इंडिया में देखें बहुत से आदमी हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो यहां मुलाजमत में हैं और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। तो मीर वाज के बाप के मरने पर बख्शी ने छुट्टी कर दी और मीर वाज के बाप एक माने हुए भले और ईमानदार आदमी थे। देखिये, मीर वाज के बाप बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं थे, बिल्कुल सीधे सादे आदमी थे। और अगर उनके मरने के बाद छुट्टी भी कर दी तो वह

डिज़रव करते थे यह चीज। हालांकि जो मैं यह कहता हूं कि छुट्टी कर दी तो यह भी सबजेक्ट टू कन्फर्मेशन है। यह हुकूमत की निगाह में है। मगर वह छुट्टी की भी गई तो ठीक है। यह भी कहा गया कि २-३ सौ आग की भरी हुई कांगडियां बख्शी अब्दुल रशीद के सर पर मारी गईं। जरा अन्दाज़ा कीजिये आग की भरी हुई कांगडी अभी एक आदमी को दो भो मार कर देख लीजिये, एक के बाद ही क्या हाल होगा, इसको देख लीजिये अन्दाज़े के तौर पर। यह तो मुबालिगा कि इन्तहा है और लोगों के जज्बात को उभारने के लिये यह तरीका अख्तियार करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा एक कहानी घड़ी गई कि एक एस० पी० ने सरकारी मुलाजिम ने, एक हिन्दु को पिस्तौल से मार दिया ताकि हिन्दु मुसलमान में फसादात पैदा हों। तो आप इन दोनों में फरक देखिये कि एक जगह तो कहा जाये कि एक हिन्दु ने मूए-मुबारक चुराया है और दूसरी जगह यह कहा जाये कि एक मुसलमान मुलाजिम ने हिन्दु को मार डाला। जमीन आसमान का फर्क है।

तो चीज यह है कि ऐसी चीज कह देने से क्या फायदा जिसका कोई सबूत नहीं है—कि तीन सौ आग से भरी कांगडियों की यूरश किसी आदमी पर चलेगी जब यह किसी आदमी के सर पर लगती है तो वह बच नहीं सकता। अभी हमारे खिलाफ दो साइड हैं। एक तो डिस्ट्रिक्टल सुप के ५-६ आदमी हैं जिनको कामयाबी नहीं हुई। पीछे अभी जो इलेक्शन हुये थे लीडर आफ दी हाउस के उसमें १०० के मुकाबले में उन्हें ६ वोट मिली।

श्री ए० एम० तारिक : आप भी मुबालगे से काम ले रहे हैं। ७५ है, १०० नहीं है।

श्री पीर मुहम्मद खान : किसी वजह से ६ वोट पाने वालों को लीडर आफ दी हाउस तसलीम किया जा सकता है? मैं इसमें कौंसिल के मੈम्बरो को भी शामिल करता हूं

मैं कहता हूँ कि इस ग्रुप की तरफ से जो यह कहता है कि हमने काफी स्ट्रेंथ बना ली है, काश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ नो कान्फाडेंस मोशन लायेगा, बड़ी अच्छी बात है। और यह एक कान्सिट्रिब्यूशनल वे है। आप तो कान्फाडेंस मोशन लाइये और सारी बात ठीक हो जायेगी। अगर वह पास हो जायेगा तो आपको स्ट्रेंथ मालूम हो जायेगी। लेकिन आप क्यामत तक इसको नहीं ला सकते हैं। जो कुछ मर्जी है आप कह सकते हैं और वह आपके लिये ठीक है। मैं फिर आपको याद दिलाऊँ कि एक जिन्दा शख्स २०० कांग्रेसियों की आग की यूरश के नीचे आयेगा तो जिन्दा नहीं रह सकता। आप लोग और मौलवी मसऊदी साहब जो इस एक्शन के रूढ़िबान हैं और नई डिमान्ड पेश करते हैं, जिन की बड़ी तारीफ़ डिसपेन्टल्ड ग्रुप में की जाती है और वह नई नई बातें पेश करते हैं।

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

हमने काश्मीर में १६-१७ बरसों में बहुत काम किया और इसको आगे बढ़ाया लेकिन मीर बाज़ यूसुफ साहब और चौधरी गुलाम अब्बास को पाकिस्तान से वापस लाया जाये यह मांग हमारे मौलाना मसऊदी साहब करते हैं ताकि वह लोग राउण्ड टेबल कॉफ़ेंस में बैठ कर काश्मीर के मामले का फैसला करें। कितनी हैरानी की बात है कि जो लोग इस तरह की बात किया करते हैं उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं किया गया। मौलाना मसऊदी साहब वही शख्स हैं जिन्होंने १९४७ ई० में और ४८ ई० के शुरू में चौधरी अब्बास को जो जम्मू की जेल में कैद थे वहां से छुड़ाकर पाकिस्तान भिजवाया था, अब वहीं कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से वापस लाया जाये। मीर बाज़ मोहम्मद यूसुफ और गुलाम अब्बास ये दोनों रियासत के पाकिस्तान में शामिलियत के हक में थे। इस वक्त गुलाम अब्बास फौजी तैयारी कर रहे हैं आजाद काश्मीर में ताकि वह काश्मीर के उस हिस्से पर जो कि हमारे कब्जे में है उस पर हमला कर सकें। मौलवी मसऊदी

साहब, मीर बाज़ साहब, गुलाम अब्बास साहब और शेख अब्दुल्ला साहब भी क्या काश्मीर के मामले पर फैसला कर सकते हैं? यह कितनी सज्जेका खेज बात है? अगर आप एक्शन कमेटी के मेम्बरान को देखेंगे, तो उसमें १२-१३ आदमी हैं और जिस में अवसोरीयत मीर बाज़ मुहम्मद यूसुफ के रिश्तेदारों की है। और बाक़ आदमी प्रो-पाकिस्तानी पार्टीज के हैं जो मुस्लिम पोलिटिकल कॉफ़ेंस और प्लेबिसाइट फ्रंट के मेम्बर हैं। इस एक्शन कमेटी में एक आदमी भी नेशनल कॉफ़ेंस का नहीं है। बरखी साहब ने इस एक्शन कमेटी के कामों को चलने नहीं दिया और हुक्मत में १९३७ ई० से लेकर आज तक इस किस्म के एलीमेंट्स को उभरने नहीं दिया, यही उनका कुसूर है जिसकी वजह से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आज उनको मजाकिन अहनी आदमी कह रहे हैं। यही थोड़े असे पहले सही तौर पर आहनों आदमी थे और उनकी तारिफ़ करते थकते नहीं थे। खुश किस्मती से होम मिनिस्टर साहब ने १२ तारीख को राज्य सभा में यह बताया कि इस मूए-मुबारक की चोरी में नेशनल कॉफ़ेंस का कोई हाथ नहीं था, उसमें एक से ज्यादा आदमी हैं और अभी मुमकिन है कि इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारी और करनी पड़े। नन्दा साहब ने आज यह भी कहा है कि दो तीन दिन में असली कल्परिट्स के नाम बता दूंगा। और एतराज कुनिन्देगा के मुताल्लिक मामला रौशन हो जायेगा कि उनका प्रापेगन्डा कहां तक सही है और फिर यह आहनी आदमी फौलादी आदमी बन जायेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you have taken enough time. Please wind up.

श्री पीर मुहम्मद खान : पहले स्पीकर को काफी टाइम दिया गया है इसलिये मुझे थोड़ा वक्त और मिलना चाहिये। तो मैं कह रहा था...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken nearly half an hour.

श्री पीर मुहम्मद खान : तो मैं कह रहा था कि एतराज करने वाले न घबरायें, दा तीन दिन में दूध और पानी अलग हो जायेगा और मर्दे आहूनी की पोजिशन आपको अच्छी तरह मालूम हो जायेगी। पार्लियामेंट में इस तरह से तोहीन आमोज बातें करना पार्लियामेंट के रुतज के खिलाफ है। इस तरह की बातें करना बेजा है। बेजा नहीं। इसके बाद मैं मोशन ग्राफ थैंक्स की ताईद करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका इनायत किया।

श्री एन० एम० धनवरा (मद्रास) : मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं कि इस नाजूक दौर में बख्शी गुलाम मुहम्मद और अब्दुल रशीद वह कहाँ थे। और वह मैदान छंड कर क्यों चले गये? तो क्या मोलाना मसऊदी साहब ने ही इस नाजूक सिचुएशन को सम्भाला था?

श्री पीर मुहम्मद खान : मुझे इजाजत हो तो मैं इनका जवाब दे दूँ। मैंने जिस वक्त जवाब दिया था उस बात का, उस वक्त उन्होंने फोले नहीं किया। मैंने कहा था कि लोगों में यह बात फैलाई गई इस एक्शन कमेटी की जिसमें तकरीबन सेंटरनैन्ट प्रो-पाकिस्तानी एलीमेंट शामिल है और उन्होंने मोर्चे का फायदा उठाया है। उन्होंने लोगों के कान में फूँका कि यह सब कुछ बख्शी ने और नेशनल काँग्रेस ने कराया है।]

THE DEPUTY CHAIRMAN: You need not begin another speech. You can give the explanation. Shri Mehta.

SHRI M. M. MEHTA (Gujarat): Madam, I rise in support of the Motion. Our worthy Vice-President has elaborately discussed the various problems at home and abroad in his Address. In the very first paragraph he said:

"In spite of difficulties and detractions, we have continued to move forwards our objective of a democratic and socialist order at home . . ."

I will agree with him as far as the democratic part is concerned but I have grave doubts as to whether we are marching towards a socialistic pattern or order. He has said rightly only 'moved in spite of difficulties and distractions'. We talk too much of socialism—is it not—now-a-days and practically we do nothing absolutely. It is a mockery of socialism, I will say. Our beloved Prime Minister alone has fought for socialism in this country and I am very sorry to say over here that no colleague of his has participated or shared his sentiments as yet and that is why, if we all his colleagues had given him—that is what I say, we all,—full support to his sentiments we would have achieved socialism long before but he is a great democrat. He has accommodated the sentiments of others and that is how to-day if we look at the situation in India, I will dare say—as so many Members of the Planning Commission even agree with the opinion—that socialism is still far a way, unfortunately or I should say rather fortunately. I am very glad that, you all know, by the Grace of God our beloved Prime Minister has come out of his serious illness. The whole of India was very anxious about his health. He is still one of the greatest figures in the world at present. He is the only architect of modern India and idol of young India for ever. I know how the younger people of India love him. I know and I run an institution of young people in Kutch which is called the Tarun Mitra Mandal. I know many of its members prayed to God, when our Prime Minister was not keeping well—they were prepared to give away their lives—to give Panditji a very long life so that he may consolidate his work of relieving the exploited masses of India and human beings everywhere. I am very happy to see him again getting back his health and our ever-young Panditji is blossoming just like a flower.

Since long the Congress has been the ruling party. While even in 1930 when Sardar was the President in Karachi, the Congress was talking since long about socialism. My heart always used to thrill when Sardar and Panditji roared that the people who did not believe in socialism should get out of the Congress. I will ask the Secretary, Shri K. K. Shah, here—unfortunately he is not here—how many people who did not believe in socialism, have left the Congress or will he give the list of members whom he has driven out of the Congress who did not believe in socialism.

AN HON. MEMBER: How can he?

SHRI M. M. MEHTA: I say that, of Mr. Shah, I do not say that of the Minister. He must have a list and I ask for the list. The Secretary keeps a list. Up to this time the definition of socialism was not clear even. To some, capitalism was socialism and they wanted to define socialism. Now, today, I hope we are very clear about it. I think now in the coming year, if at all socialism is to come, it will come under the leadership of Panditji only, otherwise it is not going to come in India at all.

SHRI P. N. SAPRU: What is socialism?

SHRI M. M. MEHTA: I will define it. That is what I say. Still the Congress people have no clear idea of what socialism is. Gandhiji, who preached to us for so many years, was telling all these years: 'When you do not find the way, look at the poorest man of India.' That is what I am telling you, find out the way to satisfy his needs. To-day we have unfortunately not seen to the needs of the poorest man in India. Look at our Plans. As the very basis of the Plan we have taken the village with more than 10,000 people and we have done everything to give facilities to them but the real poor people in India live in the villages. Those villages of below 10,000 people are still rotting as such. I was saying so many times on the floor of the House 1100 R.S.D.—7.

that even drinking water is denied to them. Even in my State of Gujarat, there are more than 4,000 villages where there is no drinking water at all. There is no source of drinking water. I come from a district of Kutch, a border district. It was promised by Sardar Patel that it would be put in the line of the neighbouring States. The Centre took it and I am very miserable and I have to say with pangs in my heart that today there are plenty of villages that are being evacuated only because of lack of drinking water. I do not ask for anything beyond any necessities or for luxuries. Do you call this the socialism that we have marched forward to? I will give you one example about the administration. Last time, while speaking on ex-Rulers' Privy Purses that are being given to them, when it was said that they are not to pay taxes on their investments and Government Securities, the Government was surprised as to under what law this was given to them and as I come to know, they have decided to exempt them up to 1963 and henceforward to charge the taxes on their investments. I do not understand it, the gross callousness on the part of the administration and yet no officer or no Department is taken to task. I do not understand why the Princes are being exempted as such up to 1963 when we come to know that it is not a legitimate thing. Do you call this socialism?

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): This is not socialism.

SHRI M. M. MEHTA: Still we talk of socialism so proudly. That is what I say. That does not mean that I do not believe in planned economy. I myself believe in planned economy and I am an admirer of planned economy. But as I told you, our plans are very faulty. We have lost the very basis of planning. Even so many members of the Planning Commission have expressed the same view.

AN HON. MEMBER: Who are the persons?

SHRI M. M. MEHTA: If you read the papers, you will find it. There are plenty of them. The main occupation of the village, namely agriculture, has been neglected as has been agreed to by the President himself in his Address. You can see it in paragraph 7 of the Address where it is stated:

"Despite these satisfactory trends, the overall rate of economic growth has lagged behind the Plan target. This is mainly due to the shortage in agricultural production which in 1962-63 showed a fall of 3.3 per cent."

And further:

"A steady increase in agricultural production is the most important task before us today."

AN HON. MEMBER: That is an admission.

SHRI M. M. MEHTA: They have lagged behind the target and the main question is agricultural production and that is being neglected. This rise in the price of essential commodities we are not able to control. That is the main thing today and the middle-class people and the poor people find that the rise in prices of essential commodities comes in their way. That is their main concern. Of course, we have developed some big projects, as has been referred to by the President. The whole of India will be proud of these big projects that we have in the public sector. I have visited so many of them and I feel proud of them and the whole of India will be proud of them. But then there are the other problems which daily touch the people. Today after nearly completing three Plans, if the people still find that they do not get enough to eat and they feel that they are being neglected then I do not know how we are marching towards socialism at all.

The second thing and the most important thing that I would like to submit is that unless this present pattern of the administration is changed, we are never going to achieve socialism. It is the same British bureaucratic pattern of administration under which we are being administered. Even the I.A.S., people newly recruited today, do not know anything, about what India wants to achieve. They are just minted a bureaucratic officers.

AN HON. MEMBER: But they are honest.

SHRI M. M. MEHTA: As far as this machinery is concerned, whether it is working under Lord Mountbatten or Pandit Nehru, the coin comes out with the same print. There is exploitation and corruption, nothing else. We require to change the whole of this machinery. However good the metal may be that you put in, the coin that comes out will be the same. The whole die requires to be changed.

AN HON. MEMBER: What is your suggestion?

SHRI M. M. MEHTA: I will give one or two examples. I was very much surprised to know that in all the public sector concerns there is no auditing of the store purchases. You visit any public sector big project. I was told that there is no auditing of the store purchases.

SHRI N. C. KASLIWAL: You are quite wrong.

SHRI M. M. MEHTA: What about Mr. Goenka?

SHRI N. C. KASLIWAL: It is absolutely wrong. There is audit.

SHRI M. M. MEHTA: You mean after the store is disposed of there is audit? I am prepared to prove it from the very people who are there. Even when I asked the people in the Food Ministry, they agreed that in the case of foodgrains there is no auditing about it. It is only on paper.

AN HON. MEMBER: Question

SHRI M. M. MEHTA: There is no actual auditing. It is shown in the figures.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: On a point of personal explanation. As a member of the Public Accounts Committee, I would submit that whatever the hon. Member has stated just now is not borne out by the facts.

AN HON. MEMBER: He said it is shown on paper.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mehta, you better carry on. You have only nine more minutes,

SHRI M. M. MEHTA: That is what I came to know from the Head of the Department in the Natural Gas Commission—Mr. Goenka. At Dehra Dun I asked him about it and he told me that there was no auditing.

SHRI JOSEPH MATHEN (Kerala): You probably did not understand what he said.

SHRI M. M. MEHTA: You don't bother about my understanding. I know that. The second thing is . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is the third thing.

SHRI M. M. MEHTA: May be third thing. Whether it is first or third, it is immaterial, but it is a very important thing when we talk of socialism. Due to certain geographical and geological conditions, some parts of India are coming up, while certain other parts of India lag behind like anything. So the people in some parts get more facilities of life while the people in certain others do not get the opportunities to come up. The Administration should do something about this. Is it not our duty, when we talk of socialism to give equal opportunities to all the people in India?

AN HON. MEMBER: Are they not being given?

SHRI M. M. MEHTA: Definitely no. There are States which because of their geographical and geological position are in a much better position than other States in India. That is one of

the reasons why a change in the way of the Administration is needed.

SHRI JOSEPH MATHEN: Can you change geography?

SHRI M. M. MEHTA: It is not a question of changing geography. It is a question of the economic distribution of the revenue, of all the revenue that we collect. Pool all the revenues of all the States and hand them over to a Board composed of all the Finance Ministers of all the States, the Union Finance Minister being its president or chairman. And then distribute that pooled revenue according to the needs of the States. I can discuss about this plan, for I have my own way of thinking. And if you do that then all these quarrels about boundaries and rivers and so on, will not be there and India will remain one integrated whole. This does not mean that I advocate a unitary form of Government at the Centre. No, for I know the practical drawbacks of that. I only advocate this in the case of revenue. If consideration is given to this point then we will have an integrated India and only then will everybody feel a thrill when any part makes an advance. In this way I think we can achieve the goal of socialism.

I am very happy and I feel like congratulating the Finance Minister, Shri T. T. Krishnamachari.

AN HON. MEMBER: For what?

SHRI M. M. MEHTA: I think he has decided to give pension to the widows and minor dependants of Government servants. I think he will find out a way to give the same kind of facilities to all servants not only to Government servants but to all concerned. It is a very difficult task, but you will have to do it. The time will come when you cannot differentiate between Government servants and other servants. Otherwise it becomes an official socialism and not real socialism, the socialism of the nation. I know that the Finance Minister has the real picture about the middle class and lower classes also. He was the first person

[Shri M. M. Mehta.] also who put up a Budget which can be called an attempt towards going in the direction of socialism. Now the next Budget is coming and I know that at least there will be no more taxes.

SHRI JOSEPH MATHEN: How? You know the Budget?

SHRI M. M. MEHTA: The Government has collected all the money. As you know from the appraisal of the Plan we have not put up anything new and so all that money should be there lying. One thing I would like to say. There are some hillocks in the social plain of India in the form of some few rich houses. They should be tapered off to the level of the plain. Only then will real socialism come. Due to the emergency or whatever it is, it is these few houses that have benefited. The other point is the availability of plenty of money in religious trusts absolutely unused. Why not that money be mobilised for the sake of those people who belong to those sects? This will go a long way.

The Address contains reference to many projects but I would like to remind the House that Khandla is being neglected. It is still not connected with a Broad Gauge line and there has been talk of a free trade zone ever since the inception of the port but I am sorry to tell Manubhai that nothing much has been done, no work has been started. Khandla is not even linked to a highway. It requires some more attention. (*Interruption*). Yes it is in his charge, the creation of a free trade zone.

I totally agree with our Vice-President in regard to the coming up of the projects but there is one danger facing us and I would like to draw the attention of the House to this fact and that is about future intentions of Mr Bhupesh Gupta and his friends on the opposite. They are trying to agitate industrial labour for a general strike like the one we had in 1957. I think this will retard our industrial progress if we are not

very careful about it and if we do not take proper steps. This, of course, is a first step in the election campaign of 1967. Whatever may be the thing, we must be prepared to meet that threat. It is not that we can meet the threat only by yielding to their demands, by giving a few more rupees to industrial workers. They constitute only a small section of the people depending on manual labour. The real solution, as I said earlier, is to bring down the prices of essential commodities. We have seen that labour in Ahmedabad was given bonus, and in other places too, but what is the result? A few of the people in the area got an increase and the rates immediately go up, they get inflated. Similarly, increase in emoluments will have repercussions.

It is complained that our coastal trade is not coming up. We have a coastline of 2900 miles and 150 working ports. In spite of this, the complaint is that freight is not coming in. Some people say that the freight rate is not well adjusted. I agree with this. I know about Khandla and that is why I can say this. It is said that Khandla is to replace Karachi. I will ask the Government and our worthy Ministers present here, what was the freight rate to Karachi before partition? It was much cheaper to send goods from Cochin to Karachi than even to Bombay but today the rates and other charges in Khandla are so high that even North Gujarat people prefer to go to Bombay and export their materials than having them shipped from Khandla. So many items are there. I specially want to draw the attention of the House to the question of adjustment of freight rate.

There are plenty of things to speak about but time being limited I would now talk about the problems abroad, especially about China and Pakistan. It is said about China that there is now no war but I want to ask this House, what about our promise to re-occupy our land conquered by the Chinese? There is plenty of misunder-

standing about the letter of Mrs. Bandaranaike to Mr. Chou En-lai, as pointed out by some friends there. This requires immediate clearing up of our intentions on the floor of the House. If we do not talk anything about it, the boundary will remain where it is today. What are our intentions? Are we going to march up to the MacMahon Line or not? This should be made clear.

I am happy to note that we have started taking some strong fiction against Pakistan and the Western Powers, the sponsors of the 'Resolution. It has been made clear before the world that these Western Powers, Britain and America pamper Pakistan and all the mischief that is done against India is due to this. There is no doubt anywhere about this. I am happy that Mr. Chagla boycotted a reception given at the U.N. in New York. I am happy also to see reports in the Press that Shri Lal Bahadur called the American Ambassador and the British High Commissioner and talked to them some plain thing about our thinking. This attitude is required in a dynamic way to deal with Pakistan. We have the while been writing protest notes; I do not know what is their number and Pakistan has become immune to them. We must speak in the language that Pakistan understands. There is no point in speaking any other language which has the same effect as talking to a deaf man. I congratulate our Government for talking from this angle.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: Madam Deputy Chairman, first of all I thank you for giving me an opportunity early to express my views. We are considering the Motion of Thanks on the Address delivered by the Vice-President discharging the functions of the President.

Naturally when we are discussing this Motion, everybody is overwhelmed with the events that have recently occurred in East Pakistan and West Bengal, events in Khulna, Narayan-gunj, Jessore which were well-organised

and pre-planned. There is no doubt about this because we learn from newspapers that more than twenty thousand people were organised to lead the procession and parade through the streets of the cities of Pakistan indulging in loot, arson, massacre and mass murder. The question is, who is responsible for all those things? There is no doubt that the President of Pakistan, the Foreign Minister, Mr. Bhutto, and the officials in East Pakistan were responsible for inciting the feelings of citizens in East Pakistan. President Ayub Khan had issued several statements instigating the masses in East Pakistan. Mr. Bhutto had mischievously issued a statement that sacred relic at Hazrat-bal shrine was stolen by Hindus, the most irresponsible statement to be made by a person like the Foreign Minister of Pakistan, Mr. Bhutto. The Pakistan Radio also was indulging in a most mischievous and malicious propaganda and hatred campaign against India. It was announced by the Pakistan Radio that more than one lakh of Muslims from the Twentyfour Parganas District had crossed into Pakistan. Therefore, it will be noticed that high-ranking officials and Ministers from Pakistan have instigated people there to start this communal frenzy and orgy and incited those people to indulge in mass murder, looting and arson. Madam, we in this country are perturbed about the minority people in East Pakistan. Thousands of people have come from Pakistan. I think this morning only the number was given by the Chief Minister of West Bengal and according to the statement made by him about 15,000 people have crossed the border from Pakistan into India. Apart from that, thousands of people had to lose their lives. No doubt the Press is controlled in Pakistan. There was strict censorship and no news could trickle out of Pakistan (but) whatever news has trickled out of Pakistan clearly proves that thousands of people have lost their lives and property.

Madam, a report appeared in the *The Guardian* published from Man-

[Shri B. D. Khobaragade.] Chester and London. In that report which was despatched from Dacca by Reuter it is mentioned that this was the biggest Hindu-Muslim riot there in the last ten years. The Reuter correspondent from Dacca has claimed that this was the biggest riot in the last ten years in Pakistan. Another proof is also there. One American peace corps nurse who came from Dacca has revealed that six hundred people were dead in the Dacca Medical College Hospital alone. From this fact we can realise that the number of people who lost their lives in these riots must be more than thousand.

If we refer to the Nehru-Liaquat Ali pact, we find that it is one of the conditions of the agreement that there will be complete equality of citizenship irrespective of religion, a full sense of security of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship subject to law and morality and the members of the minority community shall have equal opportunity with members of the majority community to participate in public life of their country. It is one of the conditions of this pact that the life, property and honour of the minority community should be respected and protected but unfortunately this has not been the case. It is also one of the conditions of this pact that the Government will take prompt and effective steps to prevent the dissemination of news and mischievous information calculated to rouse communal passion by the Press, Radio or by any individual or organisation but this condition also has been violated by no less a person than President Ayub Khan and Foreign Minister, Mr. Bhutto. Therefore what is the use of having this Nehru-Liaquat Ali pact if the conditions of this pact are to be violated by the highest officials in Pakistan?

Madan, what is the solution to this?

It is suggested by some

political leaders in India that there should be exchange of population but I do not approve of this solution. Whatever the number of Hindus who want to come from East Pakistan, we would welcome them and I would suggest that whatever restrictions are imposed on immigrants should be removed. Whichever Hindu wants to come to India from Pakistan must be allowed to come but it does not mean that we must forcibly ask the Muslims in this country to go to Pakistan in exchange for the Hindus who come to India from Pakistan. We cannot force the Muslims in this country to leave the country. It is our responsibility to protect their lives also. Unfortunately in West Bengal and in Calcutta we could not take steps earlier. The State Government in Calcutta did not take steps earlier. The Chief Minister was busy with his Congress session in Bhubaneswar. In view of the incidents and happenings in East Pakistan, the Chief Minister should have returned immediately to Calcutta but he did not return. He came later on when the situation had deteriorated to such an extent that it had gone out of control, so that he had to summon the military there. Naturally, during this period the minorities in West Bengal had to suffer to some extent. There are Press reports to that effect and the Muslims in Calcutta and West Bengal had to suffer. Had the State Government been prompt enough, I am quite sure that the Government would have been in a position to control the situation and to save the lives and property of the Muslims in Calcutta and West Bengal but unfortunately they could not do so. Therefore we should try to protect the life and property of the Muslims and minorities in this country. We should not ask them to go out of the country to Pakistan. But we should allow all the Hindus if they want to come, to come to India and there should be no restrictions on them whatsoever. If possible, we should try to bring moral and diplomatic pressure on Pakistan and try to get some territory from

Pakistan to rehabilitate those persons •who are crossing over from Pakistan to India. (*Interruption*) Naturally it is difficult task; perhaps an impossible task but it does not matter. Our Government should make an effort and try to bring diplomatic pressure on Pakistan. Instead of giving one bit here one bit there as in the case of Berubari, we should try to get territory from Pakistan and try to rehabilitate our people who are coming from Pakistan.

Madam, I will refer to the incidents in Kashmir also because this Pakistan trouble is the outcome of the most unfortunate incident that took place in Kashmir. There is no doubt that the theft of the sacred relic from the Hazratbal shrine was also pre-planned; otherwise how was it possible for the people to organise a rally at four of the clock in the morning, just two hours after the sacred relic was stolen? The sacred relic was stolen at about two of the clock in the night and immediately afterwards even before the break of day they could organise a mass rally and a demonstration. It means that those people who organised the rally and the demonstration knew all about it. They must have planned and conspired to steal the sacred relic. Madam, there have been reports in the Press that the State Government is rather trying to protect some persons there. This is the most unfortunate thing. This morning also there was demand in this House that the names of those culprits who were responsible for this theft should be disclosed but the names have not been disclosed even today. According to Press reports, Bakshi Ghulam Mohammed and some of his colleagues who were disgruntled because they were removed from power, had to do something with the theft. Only on the 6th February last when Bakshi Ghulam Mohammed tried to address a public meeting in Jammu, he had to face angry demonstrations and he could not hold his meeting successfully there. It meant that those people, those disgruntled element; definitely had a hand in the theft of V:<e

sacred relic and, therefore, it is very essential that all those persons, however highly placed they may be, must be dealt with severely according to the provisions of law. Of course, Mr. Lal Bahadur Shastri has been in a position to secure the sacred relic back and also to get it verified by all those persons who knew about it. But that is only the end of one chapter. It does not solve the whole Kashmir problem. It is essential that in Kashmir we should have such a Government which will enjoy the confidence of the masses in Kashmir. From Press reports and from the feelings of the people there, we learn that they had agitated against the State Government and not against the Government of India. They have always been saying that the Indian Government should intervene. The people of Kashmir have been demanding that the Central Government should take the whole case in their own hands, that the Central Government should investigate the offence and deal with all the culprits. Not only that. The demand has been persistently made that a judge from outside Kashmir should be brought to try the offence. It means beyond doubt that the people of Kashmir have full faith and confidence in the Government of India, in the Indian people, in the Indian nation as a whole. They have lost faith only in the Government of Mr. Shams-ud-Din, who wants to rule there according to the good wishes of Bakshi Ghulam Mohammed. Therefore, if we want to solve the Kashmir problem, if we want to have law and order and peace and tranquility in Kashmir, it becomes essential that those people who have lost the confidence of the people in Kashmir should be removed from power and those persons who are still enjoying the confidence of the masses in Kashmir should be allowed to govern that State. A suggestion has been made that the President's Rule should be imposed, there. I do not agree with it. In the present international situation it will create more complications. Therefore instead of imposing the President's Rule over Kashmir, we can only

[Shri B. D. Khobaragade.] change the Government which has lost the confidence of the people and instal such Government and such people there as would enjoy the people's confidence.

Madam, we have spoken about the minorities in East Pakistan. We have spoken about the atrocities perpetrated on Muslim minorities in Calcutta, in West Bengal. But what about the atrocities that are being perpetrated on the Buddhist minorities in this country? I will refer to one incident. On the 22nd December 1963, four or five Buddhist women, Scheduled Caste women, were paraded through the streets of a village completely naked. This happened in December, 1963, in Shirazgaon village, in the Aurangabad district of Maharashtra State. It is unfortunate that Members of Parliament do not know it. Even Mr. Manu-bhai Shah's facial expression seems to suggest that he does not know about this incident. It means that the press in India has completely slept over this incident. It is more shameful and disgraceful than that. Women are paraded through the streets naked and the people of this country do not know it. Why? We have tried to raise this question in this House. I had also given notice of a Motion for Papers, but unfortunately when the Buddhist minorities are being treated in this way no notice is being taken. Madam, we have taken notice of the atrocities perpetrated on Muslim minorities in West Bengal. Is it because Pakistan is there to voice their protest against this happening? If you give the impression that the minorities will be protected only if there is some foreign power to protest against it, if it is the attitude of the Government that they will take cognisance of atrocities perpetrated on the minorities only if foreign Governments are voicing their protests, then I think the Government is following a most dangerous policy. Are you going to take cognisance of atrocities perpetrated on Christians only if some Christian powers come and voice their protest? Are you going to take cognisance of atrocities

perpetrated on Muslims only if some Muslim powers come and protest? Are you going to take cognisance of atrocities perpetrated on Buddhists only if some Buddhist nations come and protest? This is a dangerous trend and a dangerous policy. We are citizens of this country and we are entitled to live in this country with respect and honour and, therefore, it is the responsibility of the Government to see that no such atrocities are perpetrated on the minorities whether they happen to be Muslims, whether they happen to be Christians, whether they happen to be Buddhists. Therefore, I would urge upon the Government that they should look into the affair in Shirazgaon village in Maharashtra State, give protection to the Buddhist minorities there and assure the whole-country.

Finally, I would refer to one more question and that is regarding the issue of Belgaum and the issue of Goa. We have been told again and again that the question of Belgaum and Karwar may be solved soon and assurances were also given by the former Home Minister, Mr. Lal Bahadur Shastri. Unfortunately, so far, this question has not been solved. Only a few days back there appeared in the Press the news that our Home Minister, Mr. Gulzarilal Nanda, has evolved his own formula, by which he wants to solve the problem. Belgaum and Karwar, the two district towns, are to be handed over to Mysore State. If the news about this formula is correct then I must emphatically state here that the people from Maharashtra will never be satisfied with this solution or with this formula. We have been agitating since long that Belgaum and Karwar are predominantly Marathi-speaking areas and, therefore, they should be merged with Maharashtra. In the past so many elections—local elections as well as parliamentary elections—the people of Belgaum and Karwar have demonstrated beyond reasonable doubt that they want to merge with Maharashtra and, therefore, it is essential that Belgaum and Karwar should be merged.

with Maharashtra immediately. I hope our Government will soon find a favourable solution and try to solve this problem.

Then, coming to the problem of Goa, about two or three months back elections were held to the Goa Assembly. The people in Goa, by voting in favour of the Maharashtra Merger Party—the Maharashtra Gomantak Dal—have clearly indicated that they want Goa to be merged with Maharashtra. Unfortunately, in spite of this clear verdict given by the people in Goa, the Government is trying to keep Goa separate. Immediately after the election results were out, the Government tried to bring before this House a Bill by which they wanted to remove Goa from the jurisdiction of the Bombay High Court. That Bill seeks to establish a separate Court in Goa and thus promote separatist tendencies in Goa. This is a most unfortunate development and is uncalled for. According to the law, immediately after the elections, three Members are to be nominated to the Assembly. But spite of the fact that the elections were over about two months back, in spite of the fact that the Assembly had its first session also, these three members have not been nominated so far. Are we to understand that the Central Government is still manoeuvring to convert its minority in Goa into a majority and to overthrow the majority Government by this indirect way? Madam it is; high time that these three people are nominated. There were reports in the Press that when the Chief Minister of Goa, Mr. Bandodkar, was in Delhi for the Republic Day celebrations, he was shabbily treated by a Central Government official, and a protest has been voiced against this. While speaking on the Goa Bill last year, I had opposed this provision of nominating three members, because at that time itself I had said that by this provision perhaps the Central Government would try to convert the majority into a minority and the minority into a majority. That apprehension is still in the minds of the people of Goa and Maharashtra.

Therefore, I suggest that those three members should be immediately nominated, and if they are to be nominated they should be nominated according to the advice tendered by the Chief Minister of Goa, that is, Mr. Bandodkar. His advice in this respect should not be ignored and should not be neglected. In view of all those developments in Goa, Madam, I would suggest that Goa should be merged immediately with Maharashtra. Unfortunately we find that there is some kind of animus, there is some kind of indifference towards Maharashtra's problems. The other day only we have read in the papers and this morning also this question was raised in the House that an important and influential person, the President of the Maharashtra Congress Committee—not of any opposition Party but the President of the Maharashtra Congress Committee—was not allowed to hold a meeting in Nagar Haveli. Why? Because the people of Nagar Haveli want it to be merged with Maharashtra and the Central Government does not want it. Does it mean that the President of the Congress Committee should not be allowed to hold meetings? Is there any restriction on it? As a citizen of this free country everybody is entitled to travel throughout the whole country, to hold meetings, to organise mass meetings, to solve their own problems. Therefore, Madam, I would only say that all these problems, whether it is Dadar and Nagar Haveli or whether it is Goa or whether it is Belgaum or Kaiwar, should be solved as early as possible, and in no case injustice should be done to Maharashtra.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR (Madras): Madam, our hearts bleed when we hear about the atrocities in East Pakistan. We are entirely in agreement with the previous speaker that all minorities, their life, property and honour should be protected, but it is unfortunate that all happenings in East Pakistan have their inevitable reactions in West Bengal. What we are immediately concerned with is a (terrible) em

[Shri T. S. Avinashilingam Chettiar.]

It seems as if you cannot any more stop a large migration of Hindus from East Pakistan to West Bengal. Time was when we pacified them, time was when they themselves had hopes that life would get settled for them in Pakistan. But those hopes are being belied and we will not be surprised if millions of people in the next few months or years cross over to West Bengal. That makes us face the problem as to what we shall do with the large masses of men that are bound to come. Already 20,000 people have come. You cannot prevent their coming. I am happy that it has been stated that the problem will be tackled on a national basis and not on a West Bengal basis. While that is true, yet the fact remains that the increase in population in India by way of addition to its strength of a few lakhs, 10 lakhs or 15 lakhs or 30 lakhs, will make a considerable difference.

In this connection I cannot help referring to the illegal migrants from East Pakistan, Muslim migrants most of them, to Tripura and Assam. What stands in the way of our Government in those places from preventing them, I am unable to see. Part of the blame must be borne by the Ministry of Assam. Assam's politics have been such that I do not want to say anything more than this that they seem to prefer Bengali Muslims to Bengali Hindus for political reasons. That statement has been made more than once in this House, but still we see that immigrants from Pakistan are entering Assam. Apart from pious explanations, nothing much has been done to prevent it. If Muslims are coming into India on the one side and Hindus from East Pakistan are coming into India on the other side, what is going to happen to us? Madam, this is a very grave problem. There is no easy way of solving that problem. But it seems as if the time has come when at least we will have to face a forced exchange of population, not by our own

volition but by the action of those populations. I think this must be raised internationally when such a large number of population is coming and when we cannot claim compensatory land from East Pakistan for that purpose. We will be cowards if we do not raise this problem. When populations ooze in, they have been living on land in that country and they must be provided with the requisite amount of land contiguous to this country so that those populations may live on them.

This leads to another problem, and that is the question of population. It is unfortunate—I would not say unfortunate—it is a well-recognised problem but the President has not chosen to refer to it in his statement. What has happened to us in this country? During the decade 1911—21 the population was only 249 million. During the 30 years following 1921, however, the population has grown by about 44 per cent and the number has increased from 250 million to 360 million. During the decade 1951—61 the growth of the Indian population has been exceptionally high recording a growth of the order of 22 per cent or 2.2 per cent per annum. The population is already around 465 million on record, that is at the end of December last year. Demographers have calculated that it is not 438 million but it is 465 million. It is anticipated that by 1976 the figures would be round about 625 million. That is what the projection of figures by demographers has told us in this scientific paper. What is going to happen to us with this explosion of population? This is based on the population of India and not of the new entrants. And then we have development plans, we want to raise the standard of life of our people, we want to raise the standard of income of our people. Something has happened. When the national income has risen by nearly 50 per cent, the per capita income has risen only by 16 per cent; and 16 per cent and Rs. 272 will only mean Rs. 300 per year, not per month. It

is per year, the *per capita* income of the population, with all the Five Year Plans that we are having. We have a proverb in Tamil: mixing asafoetida in the sea. Asafoetida is a sweet-smelling thing which you mix in preparations in pots.

THE MINISTER OF SUPPLY (SHRI JAISUKHLAL HATHI): Hing.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: Yes, hing. If you mix it in the ocean, what will happen? Nothing will happen. This is the case with our development plans. What has happened to our food? We wanted to

increase the food production 4 P.M. to nearly 90 million tons. Instead of having nearly 90 million tons, we have gone back. The President's Address makes it clear that we lost 3-3 per cent. in the last year, and about this year, what does the newspaper say? The production of food has not been very much better, and what does this mean? We wanted to reach one hundred million tons by the end of the Third Year Plan but the population that is growing will not be satisfied even if it is one hundred million tons. All that we produce will not satisfy the growing population of this country. And the greatest and the gravest problem that faces us in this country is how we are going to face the population explosion in this country. And not a word about that has been said—a great problem—in this Address. While I support the Motion of Thanks, I would like to draw the attention of this House, this Government and this country that something should be done. Something is being done. We have family planning clinics; we have a Family Planning Board. Something is being done. Well, I was talking with certain foreigners—Americans, and we were discussing India's problems in some of the universities where I was asked to speak about the problem. Some of them said that they wanted to help us, that they were willing. They said, "But sometimes when we see the population explosion in your country, when we see the tremen-

dous growth of population in your country, we begin to doubt whether with all our help you can raise the standard of life of your people because all the income that you get gets divided up among the exceedingly large population which is growing." They want to help us with the idea that our standard of living will increase and that we will become a stable Government. But with misery all round, with poverty all round, with squalor all round, with the population increasing all round, what will happen to all the aid that they are giving? This is a doubt which is creeping not only into them but into the minds of economists and other people who see the future of India with a vision. And I want to know whether the steps that we have taken for the control of the population in the last few years—we have taken some steps—have been effective enough to arrest the growth of population. That is the question. I know that questions are answered. My friend, Mr. Karmarkar, when he was the Health Minister, and the present Health Minister would give us a long list of the things that were being done; with those answers you can shut the mouths of the people in this House but you cannot arrest the growth of population in this country.

SHRI D. P. KARMAKAR (Mysore): I. You can avoid marriage, I

SHRI T. S. AVINASHILINGAM

CHETTIAR: I say, Madam Deputy Chairman, all that has been done in this direction has not been much effective and unless something effective is done, all our efforts at improving the status of the people of this country and the standard of their life will be in vain. And we have not been seized of the urgency of this problem. That is my complaint.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: What is your solution?

SHRI T. S. AVINASHILINGAM

CHETTIAR: My solution is . . .

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: that they should follow your example.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: That is a great solution which every one cannot follow, many people cannot. Whatever steps the other countries might have taken— you do not expect me to tell you, explain to you, the ways and mean* how this can be done—this must be done, something drastic. Firstly, the people must be convinced that this is good. Many people are not yet convinced. Even villagers with eight or ten children say that it is God's will. It is for us to preach. We go Out for elections, to get votes. I know what efforts we make. Do we make any efforts to convince people having too many children about this? We have not done that. Not only that. Are we convinced as to the methods? Have we given them facilities? We are having family planning clinics in the cities, but have we given those facilities to the villagers? Everybody knows how it can be done. The only thing is that it has not been taken seriously. The urgency of it has not been imported into this problem. And then it will remain unsolved for ever, and I want that urgency to happen. I want this problem to be faced not only by the upper strata of society. In the upper strata of society it always happens, because they are very clever; Many civil servants with two or three children have undergone this operation, two thousand or three thousand. But people with a low income, people with many children, they do not see the urgency of it. It requires a tremendous amount of propaganda to bring to them a sense of urgency, and that must be done if India is to live.

I may refer to another matter. This matter of agricultural production has been talked about so many times in this House. But somehow agricultural production, with all the tricks that you are trying to do, is not going up. What is the reason? I see a fundamental reason for our failure in agricultural production. When the cost of production rises up, what do the industrialists do? They shout, they come to the Ministries and the

Ministry people hear them. Tariff Boards are appointed; recommendations are made and up go the prices. But what happens to agriculture? Here is a statement made by the Minister of Food only in the last session. He said:

"... I was referring to the question of the cost of production which we have to bear in mind when we approach this question. I mention that as far as West Bengal is concerned, it has been calculated by our surveys that it comes to Rs. 24-30 nP. per maund of rice."

But the price paid in West Bengal for getting rice is from Bs. 21 to Rs. 25. In Madras, the cost of production is Rs. 19-05 nP. while the purchase price is from Rs. 15 to Rs. 17. In Andhra Pradesh, the cost of production comes to Rs. 21, whereas the price paid is from Rs. 16 to Rs. 18. And he says further—

"We agree that this price is less than the cost of production."

Then he has got another argument as to why he wants to get rice at a lower price than the cost of production and here is what he says. He says that Americans have come to this country and have made recommendations that you must give a price which is near the cost of production and more. He says that you cannot give protection to that section to the extent that protection is given in the West. He refers to the West. He says:

"Of course, we cannot afford to give price support of the level that is being given in countries like the United States or for that matter any developed country in the West because, as far as India is concerned, 70 to 75 per cent, of the population directly or indirectly depends on agriculture. So, if you protect that section to the extent that protection is given in the West, what would happen is that the en-

tire burden would shift on to the 20 per cent, section, which would be an unbearable burden. So, there is a limit to our giving price support or a remunerative price to the farmer. That has also to be borne in mind. In the USA, only 1] or 12 per cent, of the population is dependent on agriculture . . ."

Madam, I entirely disagree with what the Government has said in this matter. Who pays the price of the rice? The man who eats; it. Seventy per cent of the people live in villages and twenty per cent of the people who Consume rice pay a higher price. How do you say that the 20 per cent in the cities will not bear the price rise simply because 70 per cent live in villages and 20 per cent in towns? I say, this is giving a proper deal to the agriculturist.

SHRI R. K. BHUWALKA (West Bengal): In West Bengal it is Rs. 35 now.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: And so long as this policy is pursued, the agriculturist will not put his heart and mind. If he does not produce, he will not starve, but it is towns people who will starve. Even if he does not produce, he will get enough to eat, but it is the other people who will not get enough to eat and so, this is a very wrong policy not to give a proper price to the agriculturist. I say unless your attitude towards food production and towards agriculture is peasant-oriented so that the peasant may live, so that the peasant may prosper, however much you may cry from the house-top, with all the big officials that you have in the Secretariat you cannot produce one grain of rice. They can advise. They draw circulars. They can issue orders, but that cannot produce grains. It is the peasants who are in the six lakhs of villages and who are actually engaged in agriculture who have to produce the grains, and if they are to produce rice, they must be encouraged, they must be given the proper price, and according to the

statement made in this House by the Minister for Food, it is very correct; he said it very plainly that the price that they are giving for procuring rice is less than the cost of production of rice. To do so is wrong, entirely wrong and I think it will not do for encouraging higher production. I do not like to go into other steps which can give greater production, but the basic policy of not paying a proper price for the agriculturists and cultivators is not a right policy, and unless that policy is changed, I took upon with gloom at the prospect of higher production in agriculture. Make it worth while. If a man in the town can have a motor-car and can send his son to the engineering college or medical college, why should not a man in the village do it? He will have the ambition. He must do it. And if you don't get him a proper price, how will he educate his children? This is not the proper way, and I would appeal that the point of view which has been represented by the Food Minister in his statement before this House should change, and the sooner it changes, it will be better for higher production in this country.

Now, Madam Deputy Chairman, I come to another matter, and that is the matter of avoidance of corruption. I am very happy that Shri Gulzarilal Nanda, since he became the Home Minister, has been devoting himself to this very big question. I hope we will have some time for a discussion on that Vigilance Commission which he is proposing to appoint. Fifteen years back we thought that corruption was impossible at higher levels in the Secretariat, for example, even at the level of Secretary; about fifteen or twenty years back we never thought that corruption would prevail even at the higher levels; we thought it was impossible, but it is unfortunate today, we hear charges of corruption. People come to us and tell us about them. Somebody says that it is impossible, but Somebody else comes and says that it is possible—it was only a matter of money. They say: you go

[Shri T. S. Avinashilingam Chetti-*tiar*.]

with a decent sum of money and you get a licence. And they prove it too. I say, maybe that the Government thinks that these controls are inevitable. But the greater the controls, the greater the corruption. They go together; you cannot avoid it. I have a few suggestions to make to show how it can be tackled. Mere *danda* (stick) does not stop corruption. You can do it, there is some deterrent punishment and you can give it. But then there is so much temptation for them and when one sees the 'other making a fortune through corrupt means, he begins to think, "Why not I too make something out of it?" Now I make a few suggestions to the Government. In those departments where favours are shown, where licences are issued, where they have a lot of discretion, a man takes some time to learn and to think about corruption. And here I say that at least once in three or five years the man must be changed from the tempting departments to more innocent departments.

SHRI D. P. KARMARKAR: Like post office.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: Yes, like post office, like education, like health and other departments which are fairly innocent. It is where you deal with the rich people that the danger comes in. They don't care for a lakh of rupees; they care nothing. The Ashoka Hotel today is a very fine place—I understand—where people can meet over cups of tea or coffee, or dinner or lunch, and talk many things. Now I think that the transfer of officials from these dangerous departments to innocent departments once in three years or five years will at least deter them before they get emboldened to take to corruption. After all they require time to pick up courage.

SHRI D. P. KARMARKAR: The incoming people will get the opportunity also.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: Our ex-Health Minister seems to have experience, but I do not think so. Now I shall also ask the same question. The question was asked about Ministers, as to what organisation was being set up to enquire into the conduct of Ministers. You know, Madam Deputy Chairman, as things stand, allegations are being made, and there is some truth in them. Certain very grave allegations have been made against Ministers, and corruption gets encouraged when the top people go free.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. F. BHARGAVA) in the Chair]

I would like to know what is being done in this regard; something must be done. I know this is politics; this is more than administration and when politics comes in, many things have to be reckoned with—the man's strength, how many followers he has in the Parliament or in the Assembly; many things come in. Therefore I say that some top man in the judicial line, one who is beyond influence, one who will go into these matters also must be put on the job, because when the top source is corrupt, the others alone cannot be blamed. Thirdly, deterrent punishment should be given whenever they are found out. Many times the really corrupt persons cannot be found, and whenever they are found, there should be no mercy on any ground whatsoever. Having known a little of Government, many times, when you see a thing, you get angry, and if you delay taking action against the delinquent, other people come, pressure comes, influence comes and many things happen, and that is one of the reasons why some of the Members wanted that necessary action should be taken immediately.

These are some of the suggestions which I am making to eradicate corruption, and the sooner we are able to do something about it, the better. Thank you. I support the Motion.

SHRI K. V. RAGHUNATHA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, at the very outset let us express our greatfulness to Providence for the recovery of our Prime Minister, and we trust and believe that his services will be available to the nation for many years to come and that we will have the benefit of his guidance.

Mr. Vice-Chairman, I fully share the views and feelings expressed by a number of hon. Members here regarding Kashmir, regarding Pakistan and regarding the miserable rhythms of foreign policy expressed by the representative of Great Britain in the Security Council. I trust that Britain would realise the pathetic nature of its policy and try to mend the mistakes committed in relation to Kashmir as early as possible.

Mr. Vice-Chairman, the Vice-President was pleased to refer in the course of his speech to various aspects of socialism and democracy, and he has stated that it is the aim of this Country to take this country to socialism through democracy and peaceful means. In this context I presume that he meant that through various forms of economic policies the economic disparities are to be brought down. I may in this context, Mr. Vice-Chairman, refer to a very learned statement made by Professor K. N. Raj, an eminent economist of this country. In one of his articles he has stated:

"The view that economic inequalities can be dealt with by fiscal measures and that, therefore, it is not really necessary to substitute social for private ownership to prevent concentration of economic power is based on wrong premises. Economies of scale in industry lead inevitably to the corporate form of organisation, to larger-sized corporations, and to various kinds of integration and it is difficult to check these tendencies without coming in the way of economic growth itself. There are many difficulties in applying the principle of progression

to the taxation of companies. The corporate form of organisation also facilitates evasion of tax in various ways by those associated with it (such as through expense accounts). As long as privately-owned corporations are given an important functional role in an economy, concentration of economic power in private hands cannot really be avoided."

The Congress President, Mr. Kamaraj, with his sense of realism and practicality, had stated, in the course of his presidential address at Bhubaneswar, with a telling simplicity and with full sense of practical approach to this problem, as follows:

"Many of us may have believed in the past that we can reduce disparities through taxation. Since apparently this means has not proved sufficiently effective, we should have a second look at it and adjust our taxation and other policies to accomplish this very desirable end."

I hope the sentiments expressed by the Congress President and the learned Professor would have some effect on the budgetary policy which the hon. Finance Minister is going to enunciate in the near future.

In this context, at page 30 of his book, "Liberty in the Modern State", Prof. Laski has said: —

"The private ownership of the means of production is no longer compatible with democratic institutions and that accordingly the more prolonged its continuance, the more certain it is to result in the problems which are unlikely to be settled by peaceful means."

Hence, I humbly ask whether the time has not come when we should exercise our minds over these various policies, consider the nature of changes in social and economic policies that would really bring about to reduce economic disparities.

In this context, Sir, inevitably one should understand as a student of economics that there is absolute need?—

[Shri K. V. Raghunatha Reddy.] sity for nationalising all important TS trf our economy, the basic step being the nationalisation of banks. When I speak of nationalisation, I am immediately reminded of the contemporary juristic thoughts that are prevalent in this country either through judgments or interpretations of law. With your permission, Mr. Vice-Chairman, I may refer to a very recent judgement of the Supreme Court which raises certain very important issues, which concern the various economic policies that Parliament, the Central Government and the State Governments may have to consider and decide.

The Supreme Court has gone into the question of policy enunciated by the State in relation to the nationalisation of bus routes in the Kurnool district of Andhra Pradesh. Hon. Members, Mr. Vice-Chairman, must be quite aware of the situation which led to the resignation of a very able Chief Minister of one of the Seates of the country. Mr. Vice-Chairman, this is not purely an individual problem that confronts either a particular Chief Minister or a Minister of a certain State. This is a problem which has to be faced squarely in principle, not in relation to any particular personality. This problem has to be understood in the context of social and institutional changes since we believe in the results of changes in social institutions for the purpose of development of socialism. Every time, every day an administrator has to face this problem. And in political life, Mr. Vice-Chairman, you cannot always expect only friends. Often you have to deal with your friends as well as vour adversaries. You will have to deal with all kinds of persons. Es-pecially when there is a struggle between the private sector and the public sector, the private sector will not consider any means at their disposal to be mean enough not to be used asainst the public sector or the protagonists of the public sector. In that .context, Mr. Vice-Chairman, this judg-

ment has to be viewed. We have to view how far the courts can interfere with the questions of policy which are the main responsibility of the executive and the legislatures.

Further, Sir, we have always believed that no man will be condemned without being made a party to a proceeding and without a proper notice being issued to him by the court either by his designation or by name. Without making him a party to a proceeding no adverse comments can be passed against him, Mr. Vice-Chairman, any allegations of *mala fides* or misconduct in law are in the nature of charges in the criminal law. In relation to opportunity, trial or en quiry and burden of proof, the principles applicable to criminal trial and the rules of procedure apply to arrive at a finding of *mala fides*. Unfortunately, this rule of procedure or the rule of burden of proof which says that all the allegations must be proved beyond reasonable doubt has been set at naught. These are matters which the jurists of this country, which the Members of Parliament will have to ponder over and see whether there is any crisis in the development of juristic processes and offer their advice.

Mr. Vice-Chairman, all that happened in this matter was that instead of nationalising the bus routes in one district nationalisation was taken up in another district because it was felt by the Government and by the Chief Minister that the routes in that particular district were more contiguous to the already nationalised sector. Under the Motor Vehicles Act, under section 34, the Government has got the power to issue directions to the Road Transport Corporation to nationalise in any particular manner. But in this case > the Government, without resorting to the power granted to them under section 34 what they did was they requested the Road Transport Corporation to consider the various suggestions, which the Government is entitled to make, whether nationalisation of routes in a particular district like

Kurnool would be beneficial Or not. On considering the various suggestions the Road Transport Corporation came to a certain conclusion.

Now a test has to be applied in all these matters. If an act done is manifestly good, the intentions of a human being will have to be judged on the face of the act because it is impossible for any man to find out how the mind of a man works. If the act is done, on the face of the act the intentions of the man are manifest. If it is not judged in this way, by a court of law, I am afraid this is an act of juristic misconception.

Mr. Vice-Chairman, there is one more principle. If there are two conclusions that can be reasonably drawn by a court of law, one consistent with the *bona fides* and another consistent with the *mala fides*, in the criminal jurisprudence the primary rule that has to be followed in this matter says that the one consistent with the *bona fides* should be taken up for the purpose. I am afraid this rule also has been set at naught and this leads to a crisis in juristic thought. I hope the jurists of the country would take note of this matter and raise this issue for a public discussion so that these principles may be well settled.

It is said, Mr. Vice-Chairman, by Prof. Laski in one of his essays that "Humanity in history has always crucified its pioneers". And the Chief Minister of Andhra Pradesh as a Congress man—I am not a Congress man—has set a very noble example of his conduct. By offering to resign he has enhanced the prestige not only of the Congress organisation but also the prestige of the judicial institutions. But while his conduct has to be appreciated and while his nobility has to be emulated, I ask all Congress persons who are charged with administration—if this principle is not settled—whether it would not lead to a dangerous precedent. Mr. Vice-Chairman, as a politician you must know that while contesting elections you have to meet all kinds of political peo-

ple and it is not necessary always that you may meet friends everywhere. All kinds of allegations will be made and day after day the Government has to pass not one order but thousands of orders and if a Government is likely to be faced with such a problem, the question is what are the principles to govern and what are the principles that are to govern the conduct of human beings in relation to these matters.

While we appreciate the attitude shown by Shri Sanjeeva Reddy, while he has set an example as a pioneer in this field by coming forward to relinquish power which is not easily done by human beings, still I wish he should not have yielded his ground because all that he had done he had done for public good though due to legal technicalities and legal interpretations the orders may not have been found to be good by the courts.

I do trust that the people of Andhra in particular and the people in general would certainly appreciate his stand and stand in solid phalanx as far as Shri Sanjeeva Reddy is concerned in the attitude he had taken and certainly support his leadership, for he has now become the first pioneer in this field. Probably his case stands unique in contemporary political history. I think the year 1964 is seeing a good beginning. I hope the Parliament and the leaders of the nation would decide this principle and see that the policy matters are not interfered with and the example set up by Mr. Sanjeeva Reddy however noble it may be, I am afraid, is a dangerous precedent and he should have been persuaded not to resign.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Shri Dayaldas Kurre.

श्री दयाल दास कुरे (मध्य प्रदेश) :
उपाध्यक्ष महोदय, उपराष्ट्रपति के अभिभाषण के सिलसिले में हमारे हाउस के बयोवृद्ध सदस्य श्री देवकीनंदन नारायण जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करने के लिये यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ।

[श्री दयाल दास कुर्रे]

हमारे देश की वैदेशिक नीति पर, हमारी सीमा पर आई हुई आपत्तियों और राष्ट्र उन आपत्तियों का उन आक्रमणों का और उन समस्याओं का किस प्रकार से सामना कर रहा है उस पर, राष्ट्र में किस प्रकार की औद्योगिक तरक्की हो रही है, खेती में किस प्रकार की तरक्की हो रही है तथा राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा लाने के लिये किस प्रकार से आगे प्रगति कर रहा है, इन सब पर उपराष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक विहंगम दृष्टि डाली है और इन स्थितियों पर जो उन्होंने प्रकाश डाला है या उसके लिये जो प्रयास किया है उसके लिये हम उनके बहुत आभारी हैं।

कल मैंने इस सदन में इस सदन के दो मीनियर माननीय सदस्यों का भाषण सुना, उसको सुनने का मुझे अवसर मिला, उनमें से एक बयोवृद्ध सदस्य हैं श्री घोष और दूसरे हैं श्री गंगाशरण सिंह और उन दोनों ने काश्मीर और पाकिस्तान की समस्या को ले कर बहुत ही सुन्दर चित्रण किया और उन्होंने सरकार के सामने और इस सदन के सामने जो अपने सुझाव दिये हैं वे सचमुच में प्रशंसनीय हैं। श्री घोष ने बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों की शासन पद्धति अलग अलग है, जब कि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, वालिग मताधिकार को ले कर के हमारी शासनपद्धति चल रही है और हमारे देश में प्रजातांत्रिक आधार पर तीन चुनाव हो चुके हैं तब पाकिस्तान में हम देखते हैं कि प्रजातंत्र का नाम भी नहीं है, वहां प्रजातांत्रिक आधार पर, वालिग मताधिकार के आधार पर, चुनाव की या शासन की कोई पद्धति नहीं है, वहां एकसत्तात्मक राज्य है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति पाकिस्तान में ठीक तरह से समझी जायगी और हम सबों का, सदन का और सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिये कि ऐसा वातावरण वहां भी बनाया जाये जिससे कि पाकिस्तान हम सबको और यह समझे कि हमारी और पाकि-

स्तान की मित्रता की कितनी आवश्यकता है ताकि एक समय ऐसा आयेगा कि जब कि वह इस पर विचार कर सकेगा। काश्मीर के सिलसिले में श्री गंगाशरण सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक पवित्र बाल की चोरी के सिलसिले में पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर एक सुन्दर चित्र बह ला सके और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसा नमूना बह पेश करे जिससे कि हिन्दुस्तान बदनाम हो और काश्मीर की यह समस्या पाकिस्तान के पक्ष में जाय। यह जो बात श्री गंगाशरण सिंह ने रखी उसका मैं समर्थन करता हूं।

हमारे राष्ट्रपति जी ने विदेशों के साथ जिस प्रकार के सम्बन्ध रखे और संसार के दूसरे देशों—अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान आदि प्रदेशों का दौरा कर के उन्होंने उनके साथ जिस मित्रता का और जिस भाईचारे का सम्बन्ध बनाया और जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ाया उसके लिये भी वह हमारे बड़े आदर के पात्र हैं। उसी प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी सूडान, इथोपिया और संयुक्त अरब गणराज्य की यात्रा की और उससे उन देशों के साथ हमारी मित्रता बढ़ी, उनकी हमारे साथ अच्छी कामनायें बनीं और उन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे बने। इसी प्रकार से विदेशों के महान पुरुषों ने भी महामहिम लाओस नरेश, महामहिम नेपाल नरेश और उनकी महारानी तथा जोर्डन और अन्य देशों के नायक लोगों ने हमारे देश की यात्रा की और इससे हमारे और उन देशों के संबंध बढ़े। हम देखते हैं कि भारतवर्ष का संबंध विश्व के और देशों के साथ बहुत अच्छा है और जब चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण किया तब विश्व के ६२ राष्ट्रों ने हमारे प्रति जो सद्भावना दिखाई और जो हमें सहायता भंजी उससे प्रमाणित होता है कि विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। केवल यह बात प्रदर्शित करती है

कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। हम किसी गुट में शामिल होना नहीं चाहते और हम "जिओ और जीने दो" की नीति पर विश्वास करते हैं। तथा जिओ और मिलजुल कर जिओ की इस नीति पर भी विश्वास करते हैं।

हमारे उपराष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में खेती की उन्नति के बारे में सुन्दर प्रकाश डाला है। हमारे देश का जो सब से बड़ा उद्योग है, जो बहुमत को लेकर चलता है वह खेती है। हम देखते हैं कि ७० से ८० प्रतिशत लोगों का जीवन खेती पर आधारित है। तो खेती का जो उत्पादन हुआ है उस विषय में अभिभाषण में कहा गया है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष खेती का उत्पादन कुछ कम हो पाया है इसलिये भावों में भी कुछ उतार-चढ़ाव आया है परन्तु सन् १९६३-६४ में सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है कि खेती का उत्पादन बढ़े और राज्यों की तरफ से इस विषय में प्रगति के पथ पर जाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। खेती की तरक्की के संबंध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस समय हमारे यहां सीमा पर ६० हजार एकड़ भूमि ऐसी ऊजड़ पड़ी हुई है और उस विषय पर सरकार और सदन विचार करे और अगर उसे खेती में ले लें तो विशेष तरक्की खेती की हो सकती है, वह सीमा चम्बल का डाक्यूस्त एरिया है। जहां पर मध्य प्रदेश, यू० पी० और राजस्थान इन तीन राज्यों की सीमा आती है वह डैकोडट एरिया के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य में जब तीन, चार राज्यों का विलय हुआ तो उसके बाद डाकू समस्या को हल करने के लिये प्रयत्न किये गये और अब भी प्रयत्न जारी हैं और उसके फलस्वरूप सैकड़ों डाकू गोली के शिकार बनाए गए और हजारों को पकड़ कर जेल में डाला गया है। फिर भी वह बीहड़ की समस्या और डाकूओं की समस्या वहां आज विद्यमान है। तो मैं सदन से इस बात के सिलसिले में निवेदन करना

चाहता हूँ कि यदि इस डाकू समस्या को हम हल करना चाहते हैं तो केन्द्र सरकार इसको अपने हाथ में ले। यदि वह डाकू समस्या हल हो जाती है तो जनता का बहुत हित हो सकता है।

साथ ही साथ, जैसा कि मैंने निवेदन किया, ६०,००० एकड़ जमीन जो इस समय चम्बल के बीहड़ के अन्दर आती है, यदि सरकार उसे कृषि के योग्य परिवर्तित करना चाहे तो वहां पर अधिकांश लोगों को जो भूमिहीन हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको जमीन दे सकते हैं और खेती का उत्पादन अधिक बढ़ सकता है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, गत वर्ष मध्य प्रदेश शासन के अग्रिकलचर विभाग से और केन्द्रीय शासन के अग्रिकलचर विभाग से इस विषय में चर्चा हुई है और केन्द्रीय शासन ने मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग को ५ करोड़ रुपये बुलडोजर, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिये देने का आश्वासन दिया है। यदि यह बात सही है तो यह केन्द्रीय सरकार का बहुत बड़ा कदम है और यदि वह खुद अपने हाथ में ले तो बहुत ही अच्छा कदम हो, और हम ऐसा करके खेती के उत्पादन को मध्य प्रदेश में बढ़ा सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है, खास कर मध्य प्रदेश के उस भाग में जहां से मैं आता हूँ, कि इस समय गल्ले की चीजों की कमी होने के कारण गल्ले की कीमत बढ़ गई है और इस समस्या को हल करने के लिये प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार दोनों के पास अन्न का जो स्टॉक है और वहां से फेयर प्राइस शाप को जो अनाज देते हैं, उसमें हमने देखा कि बड़ी कमी आ गई है और मैंने यह भी महसूस किया कि फेयर प्राइस शाप जो इस समय खुले हैं यदि उनकी संख्या बढ़ाई जाय तो गरीब, लोअर और लोअर मिडिल क्लास को अधिक सुविधा दी जा सकती है। इसके साथ

[श्री बहाल दास कुरी]

ही मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को राइस मिल्स जितनी हैं, उनके कोटा में भी वृद्धि करनी चाहिये। जहां तक मुझे ख्याल है, चालीस प्रतिशत राइस मिल का उत्पादन केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार लेती है—२० प्रतिशत केन्द्रीय शासन और २० प्रतिशत प्रान्त शासन लेती है जब कि हम देखते हैं कि प्रान्तीय शासन स्टाक को जब फेयर प्राइस शाप में देती है तो वह इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से परमिट लेने का रास्ता देखना पड़ता है और इसमें समय लगता है। तो ४० प्रतिशत जो राइस मिलों से कोटा लिया जाता है उसको बढ़ा कर ६० प्रतिशत किया जाय और उसमें से चालीस प्रतिशत प्रान्तीय शासन को दिया जाय, उसको गोदाम में रखा जाय जिससे हम लोगों को राहत दे सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इसमें हम ज्यादा सफल हुए हैं, हम अधिक लोगों को आगे राहत दे सकते हैं।

इसी के सिलसिले में मैं वेयरहाउसिंग की बात भी करना चाहता हूं। वेयरहाउसिंग द्वारा जहां हम सरकारी गोदाम बनाते हैं वहां हम अन्न को अधिक अच्छी तादाद में रख सकते हैं। उनकी संख्या आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है और उनको अधिक संख्या में खोलने की जरूरत है जिससे कि हम सरकारी माल के अलावा गैर सरकारी माल को भी अधिक तादाद में रख सकते हैं। तो मैंने खास कर मध्य प्रदेश में देखा कि वहां वेयरहाउसिंग की कमी है। खाम करके कम्युनिटी डेवलपमेंट इनके लिये बड़ी प्रयत्नशील है। लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और जहां हम गैर सरकारी प्रतिवर्ष के उत्पादन की चीजों को रख सकते हैं वहां उन लोगों को जो ऐसी चीजों को रखते हैं ऋण के रूप में रकम भी दे सकते हैं। इससे किसान वर्ग को अच्छी सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

उप सभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखते हुए मुझे भी यह महसूस हुआ कि हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। अभिभाषण में कहा गया है कि गत वर्ष के उत्पादन को देखते हुये जब हम उद्योग धंधों की कार्य विधि को देखते हैं तो सन् १९६३-६४ में ७.८ प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है—ऐसी आशा उप राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में व्यक्त की है। मैं भी इससे सहमत होता हूं। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, खास कर मध्य प्रदेश का वह भाग जो कि पुराना महाकौशल कहलाता है, वह इस समय पूरे राष्ट्र को रा मीटीरियल देने के लिये बहुत उत्तम स्थान बन गया है। खास कर लोहा, कोयला, मँगनीज, ये चीजें आपको उस स्थान में मिलती हैं, और आपका ध्यान उस ओर तो अवश्य जाता होगा जहां भिलाई का कारखाने जैसी एक बहुत अच्छी चीज अपने देश में बन गयी है। उसी तरह से बस्तर जिले में वेलाडिला का नाम आपने सुना होगा जहां हम अच्छे दर्जे का लोहा देश को दे रहे हैं। पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी अच्छी चीजें, रा मीटीरियल हम उस भाग से देते हैं, लेकिन हम उस प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से उन्नति की ओर अप्रसर नहीं पाते हैं। आज ही मुझे अपने प्रदेश के वयोवृद्ध नेता श्री मांडलोई जी से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि सन् १९५२ से लेकर आज तक १० वर्ष के दमियान में, जैसा कि मालूम हुआ, प्राइवेट सेक्टर में केवल १० करोड़ रु० खर्च हो पाए हैं? यह हमारे प्रदेश की तरक्की का एक नमूना है। जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था, यह भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है और रा मीटीरियल की दृष्टि से बहुत ही अच्छी जगह है। यदि हम औद्योगिक

दृष्टि से उस क्षेत्र का विकास न कर सकें तो हम वहाँ के पिछड़े लोगों की तरक्की नहीं कर सकेंगे।

जहाँ तक कच्चा माल जो उद्योग वंधों के काम आता है उसको परमिट केन्द्र सरकार से प्रान्तों को दिये जाने की बात है उसमें भी हमारे पास बहुत कम हिस्सा आता है। सन् १९६२ का एक आंकड़ा मैं देता हूँ जिससे मालूम होगा कि आवश्यक चीजें, जैसे तांबा, जस्ता, पीतल अल्युमिनियम और दूसरी चीजें जैसे स्टेनलेस स्टील का कोटा इतना कम दिया जाता है हमारे प्रदेश को कि बहुत से कारखाने बंद हो गए और बहुत से उत्साही लोग जो नए कारखाने प्राइवेट सेक्टर में चलाना चाहते हैं उनका उत्साह खत्म हो गया क्योंकि उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया और उनकी आशा निराशा में बदल गई। जैसा कि मैंने कहा, एक आंकड़ा स्टेनलेस स्टील का है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, और मद्रास को दिये गये कोटा की जरा तुलना कीजिए। सन् १९६२ में गुजरात को ५६ टन मिला है, जबकि मध्य प्रदेश को केवल ७ टन मिला है और महाराष्ट्र को २०४ टन, पंजाब को १०८ टन, मद्रास को १३२ टन और मैसूर को १४२ टन। तो उन राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को केवल ७ टन मिला है स्टेनलेस स्टील। अब आप समझ लीजिए कि इसमें कितने कारखाने चलाये जा सकते हैं और किस प्रकार से उनको हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। यह तो मैंने एक ही उदाहरण दिया। इसी प्रकार से टिन की चादरों के सिलसिले में, तांबे के सिलसिले में, जस्ते के सिलसिले में, पीतल के सिलसिले में, जितनी भी चीजों का लाइसेंस सेंटर द्वारा किया जाता है उसमें मध्य प्रदेश को नेगलेक्ट किया गया है और मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होना

चाहिये और मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में बदलना चाहिये।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : भिलाई भी तो वहाँ है।

श्री दयाल दास कुरै : एक भिलाई से क्या होता है। सारा लोहा हम दे देते हैं। हमारे लिये बड़ी खुशी की बात है कि कोरबा में एक थर्मल प्लांट बन रहा है, वहाँ एक ऐसा स्थान नियुक्त किया गया है जहाँ अल्युमिनियम का एक कारखाना बनने जा रहा है। हंसदो प्रोजेक्ट का एक केन्द्र स्थान कोरबा बन रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कोरबा का एक छोटा सा गांव भिलाई की तरह हो रहा है। मैं केवल इस विषय में सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोरबा एक औद्योगिक बस्ती के रूप में परिवर्तित हो रहा है लेकिन वहाँ पर सरकार ने टाउन डेवलपमेंट की कोई स्कीम अभी तक नहीं बनाई और न प्रान्तीय सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। जब तक वहाँ पर टाउन डेवलपमेंट की स्कीम नहीं बनती तब तक हम वहाँ पर किसी तरह की स्कीम लागू नहीं कर सकते हैं। आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि कोरबा तक जाने के लिए हमारे पास कोई अच्छी सड़क नहीं है। वहाँ की सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि जो गाड़ियां वहाँ सामान लेकर जाती हैं तो उनका अधिक खर्च अपनी ट्रकों और गाड़ियों के रिपेयरिंग करने में ही हो जाता है। वहाँ पर जो टाउन डेवलपमेंट की स्कीम है वह पंचायत अपनी जो २ हजार रुपया उसकी आमदनी होती है उससे कर रही है।

दूसरी बात जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ वह यह है कि मध्य प्रदेश का एक तिहाई भाग पिछड़ा है, फारेस्ट से भरा हुआ है और उसमें हरिजन तथा आदिवासी लोग रहते हैं। ये लोग हर दृष्टि से पिछड़े हुए

[श्री दयाल दास कुरें]

हैं और उन्हें तरक्की के रास्ते में लाने की बहुत आवश्यकता है। मैं सदन के सामने यह निवेदन करूंगा उस क्षेत्र की तरक्की के लिए एक पायलट स्कीम की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें उस क्षेत्र के लिए बहुत कार्य कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार की ओर से उस क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है और प्रान्तीय शासन भी इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील है। परन्तु मैं केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ईस्ट यू० पी० के क्षेत्र को प्रगति के पथ पर लाने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने पायलट स्कीम बनाई है उसी तरह की स्कीम इस क्षेत्र के लिए भी उसे बनानी चाहिए। इस महाकोशल एरिया का जो छत्तीसगढ़ का भाग है उसकी जो आबादी है वह हरिजनों और आदिवासियों से ही भरी हुई है और उन लोगों के लिए विशेष काम खोले जाने चाहियें ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत में सुधार हो सके। अगर इस तरह की कोई स्कीम वहाँ पर लागू की गई तो उन लोगों का आर्थिक विकास हो सकेगा और वे भी प्रगति के पथ पर देश के और लोगों के साथ आगे बढ़ सकेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस तरह की स्कीम बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर हम अपने देश में रोड की स्थिति को देखें तो अन्य देशों की अपेक्षा वह बहुत कम है। हमारे वहाँ रोड की स्थिति बहुत कमजोर है। भारत के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में मध्य प्रदेश में रोड की स्थिति और भी खराब है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की हालत को देख कर मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में अधिक रोड की लाइन देने की जरूरत है और उसके लिए प्रान्तीय सरकार के बजट में एक अलग फंड बनाने

की आवश्यकता है। जिससे इस प्रदेश में रोड की स्थिति ठीक हो सके। इस फंड से पुरानी रोडों की मरम्मत हो सकेगी और नई सड़कें तैयार की जा सकेंगी।

एयर लाइन की सुविधा भी वहाँ पर बहुत कम है। दिल्ली से भोपाल को जोड़ने के लिए एक नई लाइन आई है। इसी तरह से भोपाल, नागपुर, जबलपुर और रायपुर को मुख्य स्टेशनों से कनेक्ट करने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश भारतवर्ष के अन्य राज्यों से कम से कम एरिया में सब से बड़ा है। उसके प्रत्येक डिविजनल हैडक्वार्टर्स को एयरलाइन्स से जोड़ने की आवश्यकता है। इस के लिए सरकार को शीघ्र ही व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोग आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी गई तो लोगों को काफी सुविधा हो जायेगी और शासन का कारोबार भी ठीक तरह से चलेगा।

SHRI A. D. MANI: Mr. Vice-Chairman, in taking part in this debate on the President's Address, I should like to join other Members who have paid a tribute to our President who has undergone an eye operation. I should like to join with all in wishing the President a very speedy recovery and return to his office. We also are much obliged to the Vice-President for his addressing the joint session of Parliament, discharging the functions of the President of India during his illness. Sir, the House also deeply regrets that illness has prevented the Prime Minister from taking an active part in the proceedings of Parliament. We have seen for ourselves what the Prime Minister means to Parliament today. It seems to me that he was the soul of the Parliament and we are ¹ sorry that illness has prevented him from taking an active part in its proceedings.

Sir, I do not wish to introduce a note of controversy in the debate at this late stage of the evening but I

should like to say that the time has come for us to provide in the Constitution for emergencies of the character which has arisen on account of the illness of the Prime Minister. In the United States there is at present a furious public debate going on on the question of Presidential disability on account of illness and there are suggestions that the Constitution of the United States should be amended in order to provide for the effective leadership of Government if in any case the President or the Vice-President is disabled or incapacitated from functioning. Sir, I think the time has come, for the effective leadership of Government, that the Constitution should be amended in order to provide for the appointment of a Deputy Prime Minister who will be appointed by the President on the advice of the Prime Minister so that there is continuity of leadership if for any reason the Prime Minister on account of illness is not able to discharge his functions. I must say that the so-called troika that is functioning today, the leadership being distributed among three persons does not seem to be effective. We have seen for ourselves how ineffective the leadership of Government is in both Houses of Parliament and I do hope, Sir, that in view of the illness of the Prime Minister, serious attention will be given by Government and the Members of the Congress Party as well as of the Opposition parties to the question of amending the Constitution for this purpose. Sir, I do not propose to go into the way in which the Congress Party evolves its leaders; the way in which the Congress Party discovers its leaders seems to be as mysterious as that of the Conservative Party in Great Britain where the leadership is evolved through a mysterious process. Whatever may be the manner in which the leadership of the ruling party is evolved, I think that we should provide in the Constitution itself for the

effective leadership of Government and it need not be presumed that a person who is chosen as Deputy Prime Minister will inevitably become the Prime Minister in case a vacancy arises. It is only to see that with effectiveness the Government is carried on that I am making this suggestion.

Sir, I must confess that I am disappointed with the reference in the Address in paragraph 14 to the Chinese threat. The emergency is continuing. The Defence of India Act and the Defence of India Rules are in force. And so great is the emergency and so great is the impact of the emergency on Government and the public mind that in the whole Address there are only four lines devoted to the Chinese threat. I am reading the lines concerned:

"The Chinese threat has continued throughout the year, though there has been no actual fighting along our borders. China still maintains its intransigent attitude on the Colombo proposals and Chinese military build-up along our borders has increased."

On November 8, 1962, we passed in this House as well as in the other House . . .

AN HON. MEMBER: November 14th.

SHRI A. D. MANI: On November 8 the Resolution was moved and on November 14 the Resolution was adopted in this House as well as in the other House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. F. BHARGAVA): You can continue later.

The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 14th February, 1964.